हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 1983

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

मंगलवार, 22 मार्च, 1983

विशय सूची

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(12)24
विभिन्न विशयों को उठाया जाना	
एच0सी0एस0 अधिकारियों में व्याप्त रोश सम्बन्धी	(12)34
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	(12)34
वाक आउट	(12)42
वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान	(12)42
वाक आउट	(12)50
वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(21)51

प्वायंट आफ आर्डर	
विधान सभा में मैम्बर्ज को पैम्फलैट/पब्लिके ान डिस्ट्रिब्यूट करने सम्बन्धी	(12)66
वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)67
बैठक का समय बढाना	(12)82
वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)82
बैठक का समय बढाना	(12)89
वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)90

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होगें।

Bitumen Purchased

***148 Smt. Chandrawati:** Will the Minister of state for Public Works be pleased to state:-

(a) the total quantity of bitmen purchased during the year 2982-83 and the quantity out of it allocated to and utilised by each district in the State separately together with the kilometres of roads, constructed/repaired in each district during the said period; sand

(b) sub-division wise and district wise number of labourers employed and amount of wages paid to them for the purpose referred to in part(a) above during the same period?

Minister of State for Public Works (Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan):

(a) (i) During the year 1982-83 (1-4-1982 to 31-1-1983) 19313 M.T. of bitumen was purchased.

(ii) The accounts of allocation and utilization of bitumen are maintained Circle-wise and not district wise. Therefore, the desired information has been given circle wise in Annexure-I which is placed on the Table of the House.

(iii) Accounts of labour employed and wages pair are maintained Division/Circle wise and not Civil Sub-Division wise or District wise. Therefore the desired information is given Division/Circle Wise in Annexure-II which is placed on the Table of the House.

Annexure-I

Sr. No.	Name of Circle	Quantity of allocated & utilized out of purchases made during 1982-83 (from 1-4-82 to 31-3-83)	Kms. of roads constructed with bitumen during 1982-83 (from 1-4-82 to 31-3-83)	Kms. of roads repaired with bitumen during 1982-83 (from 1-4-82 to 31-3-83)	
1	Ambala	2182	45	310	2231

2	Bhiwani	1699	66	422	1885
3	Chandigarh	961	35	202	1436
4	Gurgaon	2272	39	421	2968
5	Hisar	4710	136	696	2811
6	Jind	640	58	209	1908
7	Karnal	1625	118	210	1715
8	Rohtak	1337	30	183	1409
9	N.H. Faridabad	852	-	170	190
10	N.H. Karnal	3035	25	315	435
	Total	19313	552	3138	16988

Anneuxre-II

Sr. No.	Name of PWD Division	Name of PWD Circle	No. of labourers employed (Man days) from 1-4-82 to 31-3-83	Amount of wages paid to labourers from 1-4-82 to 31-3-83
1	Ambala Division No.I	Ambala	75700	908000

	Ambala Division No.II Kurukshetra Division No. 1 Kurukshetra Division No. 2	Circle		
2	Bhiwani Division, Dadri Division, Narnaul Division, Rewari Division	Bhiwani Circle	80660	968000
3	Chandigarh Divn. No. 1 Chandigarh Divn. No. 2 Naraingarh Divn. Jagadhri Divisoin	Chandigarh Circle	50500	667000
4	Gurgaon Divn. No. 1 Gurgaon Divn. No. 2 Faridabad Divn. Palwal Divison Nuh Division	Gurgaon Circle	110300	1320000
5	Hisar Divn. No.1	Hisar Circle	159300	1769000

	Hisar Divn. No.2 Sirsa Divn. 1 Sirsa Divn. 2 Fatehabad Division			
6	Jind Divison Narwana Division Sonepat Divn. No.1 Sonepat Divn. No.2	Jind Circle	71800	860500
7	Karnal Divn. No. 1 Karnal Divn. No. 2 Panipat Divn. Kaithal Divn.	Karnal Circle	76300	915000
8	Rohtak Divn. No. 1 Rohtak Divn. No.2 Jhajjar Division Rohtak Constn. Division	Rohtak Circle	46935	563300
9	Faridabad Division Rohtak Division	N.H. Circle Faridabad	32500	325000

	Palwal Division			
10	Karnal Division Sonepat Division Hisar Division Panipat Division	N.H. Circle Karnal	110720	1320000
		Total	814715	9615800

श्रीमति चन्द्रावतीः मंत्री जी बताएंगे कि क्या वियुमन की भी राजनैतिक आधार पर सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यू ान हुई है या जरूरत के अनुसार हुई है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः इसमें राजनैतिक आधार की कोई बात नहीं है। जहां जितनी जरूरत होती है वहां उसके मुताबिक दिया जाता है।

श्री मंगल सैनः मंत्री जी बताएंगे कि क्या यह बात सही है आपके विभाग में बिचुमन की कमी के कारण काफी काम रूके हुए है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः ऐसी कोई बात नही है। हमारे पास बिचुमन था और हमने काम किये है।

श्री मंगल सैनः अभी वजीर साहब ने अपने दिये गए जवाब में अनैक चर–1 में बताया है कि इस पीरियड में कितने

किलोमीटर में सरफेसिंग की और कितना पैच वर्क किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि रोहतक जिले में जो इन्होंने 183 किलोमीटर सडक की सरफेसिंग की क्या वहां पर इतनी ही जरूरत थी या जानबूझ कर कम की?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, जरूरत के मुताबिक की काम किया गया है जानबूझ कर कम कहीं पर नहीं किया गया। जितनी जरूरत थी उतना कर दिया गया है।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो अनैक चर–1 में सूचना दी है उसमें हिसार सर्कल में 136 किलोमीटर सडके बनाई गई और गुडगांव सर्कल में सिर्फ 39 किलोमीटर सडके बनाई गई जबकि गुडगांव सर्कल में एक और भी जिला भाामिल है। क्या गुडगांव सर्कल की जरूरत ही कम थी या कोई और कारण था?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक काम किया गया है। हिसार सर्कल में सिरसा जिला भी पडता है वहां पर सडके कम थी इसलिये वहां ज्यादा बनाई गई है।

श्रीमति चन्द्रावतीः मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या वह तथ्य है कि सडकों पपर जो मजदूर लगाये जाते हैं उनकी हाजरी तो ज्यादा की लगाई जाती है और वास्तव में वहां पर हाजरी के 1/4 मजदूर भी नहीं होते।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः यह बात बिल्कुल निराधार है। जितने मजदूर काम करते है उतनी की ही हाजरी लगाई जाती है।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदय इस बात की इंक्वायरी करवाने के लिये तैयार है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः अगर सरकार के नोटिस मे कोई ऐसी बात लाई जाएगी तो जरूर देखेंगे। हम वैसे भी वक्तन फवक्तन देखते रहते है।

चौधरी कुलबीर सिह मलिकः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वह कम मिलती है और उनके दस्तखत ज्यादा पैसों पर करवाते है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी मिसाल नोटिस में लाएगें तो हम जरूर एक ान लेंगे।

श्री हरि चन्द हुडडाः स्पीकर साहब, रोहतक सर्कल में केवल 183 किलोमीटर सडक पर सरफेसिंग की गई है। क्या यह कमी इसीलिये तो नहीं है कि उनकी पार्टी का उस जिले से कोई कैडीडेट जीतकर नहीं आया? अगर ऐसा नहीं है तो उस कमी को पूरा करने की कोि ा ा करेंगे?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें न पार्टी की बात है और न पालिटिक्स की। जहां जितनी जरूरत समझी जाती है उसके मुताबिक काम करते है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, तारकोल आम मार्किट में तो खुला मिलता नहीं है। जो भी आदमी मकान बनाता है वह छतों को मजबूत करने के लिये उन पर तारकोल डालता है। मंत्री जी के नोटिस में यह बात है या इस किस्म की कोई ि ाकायत मिली है कि जब तारकोल परमिट से नहीं मिलता है तो लोग जो छतों पर तारकोल डालते है क्या वह इनके महकमें वाले ब्लैक में तो नहीं बेचते है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः ऐसी बात नहीं है। तारकोल बाजार में आम मिलता है। जो लोग अपनी छतों पर इसका इस्तेमाल करते है वे बाजार से खरीदते है।

श्रीमति बसन्ती देवीः मंत्री जी बताएंगे कि जो सडके बनते बनते टूट जाती है क्या वे तारकोल की कमी की वजह से तो नहीं टूटती है। इसकी मिसाल मैं बताती हूं कि रोहतक सर्कल में भाूगर मिल के सामने एक सडक बनी थी। उसको बनी को एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसमें दो दो फूट के गहरे गढढे पड गये।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः ऐसी तो कोई बात नहीं है कि सडक बने और टूट जाए। गढढे पडने की बात हैवी ट्रैफिक की

वजह से भी सकती है। हम उस सडक को चैक करवा लेगें और अगर जरूरत हुई तो उसकी रिपेयर करवा देंगे।

चौधरी धीर पाल सिहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक किलोमीटर सडक की सरफेसिंग में तारकोल और रोडी की क्या रे ाो होती है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः यह तो एक टैंक्नीकल बात है। अगर इसके लिये अलग से नोटिस दिया जाएगा तो बता दिया जाएगा।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, सडकों पर जो तारकोल डाला जाता है वह आम तौर पर ज्यादा जला दिया जाता है। क्या मंत्री जी इसको रोकने के उपाय कर रहे है। दूसरा सवाल यह है कि जो सडकों पर मजदूर काम करते है उनका मिनिमम वेज क्या है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आई कि तारकोल को ज्यादा जला दिया जाता है। तारकोल को उतना ही गर्म किया जाता है जितने की जरूरत होती है। जहां तक वेजिज की बात है इस बारे में हमारे पास कोई ि ाकायत नहीं आई है कि किसी को कम वेज दिया गया हो। वैसे आज कल हम 13 रूपये मिनिमम वेज दे रहे है फिर भी अगर कोई ि ाकायत नोटिस में लाएंगे तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कहा कि बिचुमन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो लिंक रोडज है। उनकी रोडी नीचे से निकल आती है। क्या उन पर तारकोल डालने की कोई योजना है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, इन्होंने कोई सडक ऐसे मौसम में देख ली होगी जिस वक्त तारकोल का काम नहीं होता। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि रोडी नीचे से निकल आए।

मास्टर राम सिंहः स्पीकर साहब, हमारे पास सडकों के बारे में लगातार ि ाकायतें आती है। एक सडक कालवा से बिरथला है और दूसरी गुन्थला से करनाल सडक है। इन पर तारकोल न डालने की वजह से ये टूट गई है। क्या इन पर तारकोल डालेन का प्रबन्ध किया जाएगा?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः जैसे मैंने पहले कहा कि जो नई सडक बन रही है उन पर अभी पूरा तारकोल नहीं डाला है। मैं इन दोनों सडकों को चैक करवा लूंगा अगर कोई कमी होगी तो देख लेंगे।

श्री भले रामः मंत्री जी बताएंगे कि जनवरी 1983 तक जितना तारकोल खरीदा गया क्या वह एस्टीमेंट के मुताबिक खरीदा गया या कम खरीदा गया?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः कम नहीं खरीदा है साल के लिये जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक खरीदा है।

मास्टर ि ाव प्रसादः मंत्री महोदय ने जवाब में बताया कि 814715 मजदूरों ने 31.1.83 तक काम किया और उनको 9615800 रू0 को वेतन दिया गया। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि हम मजदूरों को 13 रू0 मजदूरी देते है। लेकिन यह तो 12 रू0 से भी कम बनती है इसका क्या कारण है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः 13 रू0 मजदूरी तो हमने 1983 से की है। यह फीगर 1982 की है।

चौधरी नर सिंहः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पाई हल्का में राहडा से बाकल और नरड से सेधा तक की सडके डेढ साल से बन नहीं पाई। कर्मचारी बताते है कि ये सडके तारकोल न होने की वजह से नहीं बन पाई। क्या मंत्री जी इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य यदि किसी पर्टीकुलर रोड के बारे में कहते है तो वे मुझे उसका नोटिस दे दें उस रोड को देख लिया जाएगा।

चौधरी हुकम सिंह फोगटः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दादरी डिविजन में बिटुमन की कमी के

कारण पिछले चार साल से सडकों की मुरम्मत अलग से नोटिस देंगे तो इन्कवायरी करवा लैंगे।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, अगर माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोटिस देंगे तो इंक्वायरी करवा लेगें।

चौधरी रो ान लाल आर्यः स्पीकर साहब, सरकार के कागजों में तो सडकें बिल्कुल ठीक हालत है लेकिन अगर उन सडकों को मौके पर जाकर देखा जाए तो उनका बहुत बुरा हाल है। मैं आपके दवारा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी बात उनके नोटिस में है।

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, ऐसी बात ही नहीं है कि सरकार के कागजों में सडके बिल्कुल ठीक हालत में हैं और मौके पर जाकर देखा जाए तो बुरा हाल है। जो भी सडके टूट जाती है उनकी समय समय पर मुरम्मत करवाई जाती है।

Buses for Asiad

***109. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) whether any Haryana Roadways Buses were sent to Delhi for the Asiad and; if so, the depotwise number thereof; and

(b) the mileage covered together with the details of profits made or losses suffered by each such bus, separately?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) Yes, the number of buses sent by Haryana Roadways to Delhi for Asiad alongwith the name of each depot is given bellow:-

Sr. No.	Depot	No. of Buses	Sr. No.	Depot	No. of Buses
1	Ambala	10	7	Rewari	24
2	Ch. garh	10	8	Bhiwani	26
3	Gurgaon	45	9	Sirsa	25
4	Rohtak	25	10	Sonepat	33
5	Karnal	10	11	Yamana Nagar	15
6	Hisar	25	12	Faridabad	34
				Total	282

(b) The statement at Annexure-A is laid on the Table of the House.

Annexure-A

Sr. No.	Name of Depot	Kms covered per bus	Profit/loss per buss (Rs.)
1	Ambala	3933	-2125
2	Ch. garh	2823	+1239
3	Gurgaon	2017	+5669
4	Rohtak	3894	-234
5	Karnal	4849	-1102
6	Hisar	3688	-1176
7	Rewari	3309	-1031
8	Bhiwani	2668	+756
9	Sirsa	3441	+2393
10	Sonepat	2203	+4610
11	Yamana Nagar	3517	+617
12	Faridabad	2291	+1535
	Total/Average	3059	+1111

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, सवाल के जवाब में बताया गया है कि एि ायाड गेम्ज के लिए हरियाणा रोडवेज के 12 डिपुओ से 282 बसे भेजी हुई थी। इसके अलावा सवाल के जवाब के अक्नै चर ए में बताया गया है कि 12 डिपुओं में से 5

डिपुओं की बसों में घाटा रहा और 7 डिपुओं की बसों में फायदा रहा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एि ायाड गैम्ज के लिए जो बसें दिल्ली में लगाई गई थी क्या वे बसें हर रोज डिपुओं से चल कर दिल्ली जाती रही है और सर्विस करती रही है।

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, हर रोज डिपुओं से बसों को दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने दिल्ली के आस पास तीन जगह नियुक्त की हुई थी गुडगांव, बहादुरगढ और फरीदाबाद यहां से सारी बसें आप्रेट करती थी और भााम को इन तीन जगहों पर वापिस चली जाती थी। हो सकता है कोई एक या दो बसें दिल्ली में भी रूक गई होगी।

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, सवाल के जवाब के अनैक ाचर ए में यह बताया गया है कि जो बसें एवरेज किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा चली है वे घाटे में रही है और जो बसें किलोमीटर के हिसाब से कम चली है वे मुनाफे में रही है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन बसों ने किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा एरिया कवर किया है वे घाटे में रही है और जिन बसों ने किलोमीटर के हिसाब से कम एरिया कवर किया है वे बसें मुनाफे में रही है इसका क्या कारण है यदि कम चलने से बसें मुनाफे में रहती है तो फिर हमारी बसों को खडा करके रखा जाए ताकि सरकार को काफी मुनाफा हो सके।

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, मुनाफा कम होने का और ज्यादा होने का कारण यह नहीं है कि जिन बसों ने किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा एरिया कवर किया वे बसें मुनाफे में रही और जिन बसों ने किलोमीटर के हिसाब से कम एरिया कवर किया वे बसें घाटे में रही। बसों में घाटा और मुनाफा होने का यह कारण है कि दिल्ली में हमारी जितनी भी लोकल रूटस की बसें चलती रही हैं उनका किराया बहुत कम है क्योंकि दिल्ली में डीटीसी की बसों का किराया हरियाणा से बहुत कम है। हमारी जितनी भी बसें थी वे सारी दिल्ली के बसों के किराए के अनुसार ही चली थी। दूसरा कारण यह भी था कि दिल्ली में पर लीटर किलोमीटर एवरेज कम आती है क्योंकि लोकल रनिंग करनी पडती है। तीसरा कारण यह भी था कि एि ायाड गेम्ज के टाईम पर स्पै ाल आर्गेनाइजे ान कमेटी ने कहा कि दिल्ली में जो प्रदे ा अपनी बसें उपलब्ध करेंगे उनको एक बस के दो ड्राईवर और दो कंडक्टर देने होंगे। स्पीकर साहब, जिन जिन डिपुओं की बसें लौंग रूटस पर रही वे बसें नुकसान में रही। और जिन जिन डिपुओं की बसें लोंग रूटस पर रहीं वे बसें मुनाफे में रही। हमने दिल्ली डीटीसी वालों से लौंट रूट भी ले लिए थे। स्पीकर साहब, जिन जिन डिपुओं में प्रोफिट हुआ है वह इसलिये हुआ क्योंकि मैजोरिटी आफ बर्सिज बाहर चलीं और जो घाटा है वह इसलिये हुआ क्योकि मैजोरिटी आफ बर्सिज लोकल रूटस पर चली।

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, फिर तो हम यह समझें कि जिन जिन डिपुओं की बसें लोकल रूटस पर चली है वे घाटे में रही है और जिन जिन डिपुओं को मुनाफा रहा है उनकी बसिज लौंट रूटस पर चली है।

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का यह सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है कि जिन जिन डिपुओं की बसें लोकल रूटस पर चली वे घाटे में रही है और जिन डिपुओं की बसें लौंट रूटस पर चली वे मुनाफे में रही है। जिन जिन डिपोज का प्रोफिट दिखाया गया है वे मैजोरिटी आफ बसिज लौंग रूटस पर चली है और जिन जिन डिपोज का घाटा दिखाया गया है वे मैजोरिटी आफ बसिज लोकट रूटस पर चली है।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने यह बताया था कि दिल्ली में लोकल बसों का किराया बहुत कम है और जितनी बसें दिल्ली में लोकल रूटस पर चलाई थी हमें उनका किराया उसी हिसाब से लेना पडा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या दिल्ली के किराए के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बसों कै लिए नई टिकटें छपवाई गई थी यदि छपवाई गई थी तो कितने किलोमीटर की टिकटें छपवाई गई और कितने पैसे की टिकटे छपवाई?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, सैंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यह

फैसला किया गया था कि हरियाणा रोडवेज की जो बसिज दिल्ली में चलेगी उनका एक्चुअल फेयर दिल्ली की लोकल बसों के अनुसार होगा। दिल्ली में साढे तीन पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर चार्ज किया जाता है। हरियाणा रोडवेज की जितनी भी बसें दिल्ली में चली है। उनको साढे तीन पैसे प्लस एक रूपया पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर मिला है। स्पीकर साहब, एि ायाड गेम्ज में जो स्पै ाल आर्गेनाइजे ान कमेटी थी उस कमेटी के आफि ियल्ज के लिए हरियाणा रोडवेज को 60 बसें सिलैक्ट की गई थी। उन बसिज का किराया साढे चार रूपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया गया था उसमें हमें काफी फायदा रहा है उन आफि ियल्ज ने हरियाणा रोडवेज की बडी सराहना की है और यह कहा है कि हरियाणा रोडवेज की बसें एक मिनट के लिए भी लेट नहीं हुई।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि कितने किलोमीटर की टिकटें छपवाई गई थी और कितने पैसे की टिकटें छपवाई गई?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, हमने नई टिकटें नहीं छपवाई जो दिल्ली की बसों के लिए डीटीसी ने टिकटें छपवाई हुई थी वे टिकटें हरियाणा रोडवेज की बसों के लिए दे दी गई थी। डीटीसी की टिकटों में जितना किराया था वही हमें लेना था इसलिए हमें नई टिकटें छपवाने की कोई आव यकता नही पडी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने फरमाया था कि हमे दिल्ली के अन्दर वहीं किराया लेना पडा जो वहां पर डीटीसी की बसें किराया लेती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि दिल्ली की बसों का किराया कम है तो क्या हरियाणा में बसों का किराया कम करने के बारे में सरकार विचार करेगी?

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कितना कम किये जाने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा रोडवेज की जितनी बसें एि ायाड गेम्ज के लिए गई थी उसमें सारी बसों का 3 लाख 13 हजार रूपए का प्रोफिट है (थम्पिंग)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने यह फरमाया था कि दिल्ली में लोक बसिज का किराया कम है और हरियाणा में बसों का किराया ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में पर किलोमीटर किराया कितना है और हरियाणा में पर किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया है?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, दिल्ली में साढे तीन पैसे पर किलोमीटर किराया है और हरियाणा में 10 पैसे पर किलोमीटर किराया है। सारे हिन्दुस्तान में एक या दो स्टेटस को छोडकर हमारे यहां सबसे कम बस फेयर है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में कुरप ान की वजह से जो हैवी लौंसिज हो रहे हैं क्या उनको रोकने के लिए कोई कदम उठाये गये है?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल हैवी लौंसिज से तो संबधित नहीं है। फिर भी मैं आपकी इजाजत से इनको बता देना चाहता हूं कि दिसम्बर 81 के अन्दर हरियाणा रोडवेज को 34 लाख रूपये का घाटा हुआ था और दिसम्बर 82 के अन्दर हरियाणा रोडवेज को तकरीबन 35 लाख रूपये का फायदा हुआ है। इस एक माह की अवधि के दौरान तकरीबन 69–70 लाख रूपये के आसपास का फायदा हुआ है। हमने अपने डिपार्टमैंट के रैवेन्यू में बचत की है। यह फायदा भी हमें उस समय हुआ है जबकि डीजल के रेटस बढ गए थे। यह अलग बात है कि हमें थोडे से किराये बढाने पडें। इस बात का ये भाई जिक्र करेंगे कि यह फायदा किराया बढाने की वजह से हुआ है। स्पीकर साहब, हमने अपने एम्पलाईज को 4–5 एडि ानल डियरनैंस अलांउस की किस्ते भी दी है। इन सब के बावजूद हमें एक साल में 69–70 लाख रूपये का फायदा हुआ है। हरियाणा रोडवेज ने अब तक टैक्स की भोश में तकरीबन 32 करोड रूपया स्टेट एक्सचैकर को दिया है।

श्री निहाल सिंहः मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दी है उसके हिसाब से एवरेज पर किलोमीटर प्रति बस 1111 रूपये का फायदा रोडवेज को हुआ है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि

यदि ये बसें हरियाणा के अन्दर चलती तो कितना फायदा होता? इस बात को तो सीएम साहब ने कहा है कि दिल्ली के अन्दर हमारी बसों की प्र ांसा हुई है लेकिन जो बसें हमारी वहां बाहर चली है उस की वजह से कितना घाटा हुआ है।

कर्नल राव राम सिंहः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि एि ायन गेम्ज के दौरान हमें तकरीबन 3 लाख 13 हजार का फायदा हुआ है। जो सवाल इन्होंने पूछा है उसका उत्तर भी मैं इनको दे देता हूं। यदि ये बसें हरियाणा से बाहर यानि इन्टर स्टेट चलती तो फायदे में रहती और यदि रूरल रूटस पर चलती तो बहुत घाटा रहता।

चौधरी भागमलः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं। सीएम साहब ने एक बात कही है कि हमारी बसों की वहां पर प्र ांसा हुई है। क्या यह प्र ांसा हमारे जो ड्राईवर या कन्डक्टर थे उनके अच्छे काम करने के कारण नहीं हुई है। क्या यह भीसही नहीं है कि उन कर्मचारियों को अभी तक उस समय का टीएडीए भी नहीं दिया गया है।

कर्नल राव राम सिंहः मैम्बर साहब का यह कहना सही है कि यह प्र ांसा हरियाणा रोडवेज के जो कन्डैक्टश्र या ड्राईवर थे या जो फिटर्जवगैरा थे, जिन्होंने बसों को एक मिनट के लिए भी नहीं ठहरने दिया, उन्हीं के कारण हुई है। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ हमारे जो हरियाणा रोडवेज के अफसर थे, उनके

भी इस काम में पूरा पूरा सहयोग रहा है जिस कारण हमें प्र ांसा मिली है। जहां पर टीएडीए देने का सवाल है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता कि जितना उनका डयू था उससे ज्यादा ही देने की कोि ा ा की है within the frame-work of the rules and regulation.

श्री मंगल सैन: वजीर साहब ने फरमाया है कि 32 करोड रूपये टैक्स की भाकल में गवर्नमैंट के एक्सचेकर में जमा करवाये गए है। मैं पूछना चाहता हूं कि बसों में ओवर लौडिंग के बाद भी इनको 34 लाख रूपये का घाटा कैसे हुआ?

कर्नल राव राम सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस समय में जवाब दे रहा था, भाायद डा0 साहब ने उसे ध्यान से नहीं सुना मैंने यह कहा था कि दिसम्बर 81 के अन्दर हमें 34 लाख रूपये का घाटा रहा था और दिसम्बर 82 के अन्दर हमें तकरीबन 35 लाख रूपये का फायदा हुआ है। इनकी यह बात ठीक है कि बसों में ओवर लौंडिंग होती है। पिछले एक सवाल के जबाव में भी मैंने बताया था कि जहां जहां पर ज्यादा ओवर लौडिंग होती है वहां पपर हम एडि ानल बसें देने की भी कोि ा ा करते हैं। जनसंख्या बडी तेजी के साथ बढ रही है जिस कारण ओवर लौडिंग भी ज्यादा होती जा रही है। जहां पर संभव होता है वहां तक हम ऐसे रूटों पर नयी बसें खरीद कर यानि उन रूटों पर और बसें चलाते है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज के जो कन्डक्टर है उनको न तो पैन् ान की सुविधा है और न ही उनको कन्फर्म किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कन्डक्टरों को भी कन्फर्म करने और पैं ान की सुविधा देने पर विचार करेंगे?

कर्नल राव राम सिंहः अध्यक्ष महोदय, अब हरियाणा रोडवेज की सभी पोस्टें पैन् ानेबल हो चुकी है। जहां तक कन्डक्टरों की बात है उनके संबंध में मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो कन्डक्टर एसएसएस बोर्ड से आते है उनको तो कन्फर्म कर ही दिया जाता है लेकिन जहां तक उन कन्डक्टरों का ताल्लुक है जिनको एडहोक पर लगाया जाता है यदि वे 240 दिन पूरे कर लेते है तो उनको भी रैगुलर कर दिया जाता है ब ार्ते कि उनका रिकार्ड ठीक हो।

Suicides committed in the State

***124. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister be pleased to state:-

(a) the number of suicides committed during the year 1979-80, 1980-81 and 1981-82 separately together with the cause thereof; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to check the cases of dowry deaths in the State?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal): A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The number of suicides reported in Haryana State during the last four years i.e. from 1979 to 1982 is given below:-

Year	Tota No. of suides
1979	460
1980	358
1981	618
1982	460

The causes for suicides are domestic quarrels, love affairs, dreadful diseases/prolonged illness, insanity, poverty, failure in examination, dowry disputes etc.

(b) The following steps have been taken to check the dowry deaths:-

(i) Strict instructions have been given to the local police to register liberally the cases of dowry deaths u/s 302 or 306 of the Indian Penal Code, accordingly to the circumstances of the case.

(ii) Such cases are treated as Special Report Cases and Gazetted Police Officer visits the spot immediately to supervise the investigation.

(iii)Women Police is associated during the investigation of such cases.

(iv) Assistance of the respectable of the locality is also taken in these cases.

(v) In controversial cases, the investigation is taken up by the Crime Branch (CID) and finalized expenditiously.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, लीडर आफ दी हाउस ने अपने जवाब में कहा है कि स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी जाती है और उसमें पार्ट बी के जवाब में फमीचा है कि strict inistructions have been given to the local police to register liberally the cases of dowry u/s 302 or 306 of the Indian Penal Code, accordingly to the circumstances of the case मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्ट्रिक्टली और लिबरली में कोई भी अन्तर नहीं है।

चौधरी भजन लाल: इसका मतलब यह नहीं है जो आप कह रहे है। हमने यह हिदायतें जारी की हुई हैं कि कोई भी मामला नोटिस में आए तो फौरन केस रजिस्टर करके इन्क्वायरी और तफ ी ा की जाए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने तो स्ट्रिक्टली और लिबरली का अन्तर पूछा है क्योंकि इन दोनों में बहुत बडा अन्तर है। (व्यवधान व भाोर)

10.00 बजे

चौधरी भजन लाल: इस में लिबरली का सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगर इसका मतलब डिक ानरी में देखें तो इसका मतलब बडा लम्बा चौडा निकलता है।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने सुसाईडज के बारे में जवाब दिया है कि पुलिस को हिदायत दे दी है कि पुलिस ठीक तरह से केसिज रजिस्टर करें। सुसाईड करने के जो कारण मुख्यमंत्री महोदय ने बताये है उन कारणों को दूर करने के बारे में नहीं कहा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पावर्टी और डाउरी डिसप्यूटस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टैप्स लिए हैं?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, दो तरह की आत्महत्यायें होती हैं एक वह जो खुदक ाी करते हैं और दूसरी वह जो किसी को खुदक ाी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई दफा बच्चे इम्तिहान में फेल हो जाने के कारण खुदक ाी करते है। कई दफा पागलपन की वजह से भी मौंते हो जाती है। कई आदमी बीमारी से तंग आकर खुदक ाी कर लेते है और कई दफा नौजवान लडके लडकियां प्रेम में खुदक ाी कर लेते है। तो इस तरह खुदक ाी करने के कई रीजन्स है। इनका बाकायदा मामला दर्ज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को खुदक ाी करने के लिए मजबूर किया जाए तो भी सरकार मामला दर्ज करती है और इन मामलों की जांच करने में सरकार की तरफ से न कभी कोई कोताही हुई है और न कभी होगी।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि उनके द्वारा रिट्रक्ट एक ान लेने के बावजूद भी दहेज के कारण मरने वाली औरतों की संख्या में कमी क्यों नहीं हुई है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आप हरियाणा के आंकडे उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि हरियाणा में दहेज की लानत दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कम है पिछले चार सालों में 46 केसिज दर्ज हुए जिन में दहेज की वजह से मौंते हुई। यह फिगर दूसरी स्टेटों के मुकाबले में बहुत थोडी है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उन्होंने इंस्ट्रक ान्ज जारी कर दी है कि हत्याओं के केसिज फौरी तौर पर दर्ज किए जाएं। क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि लव–अफेयर्ज की वजह से जो सुसाईड कर लेते है इस पर सरकार क्या एक ान लेती है।

चौधरी भजन लालः खुदक ाी का केस दर्ज कर सकते है और इसमें क्या हो सकता है? बाकी अगर कुछ हो सकता है तो इसका जवाब डा0 मंगल सैन जी दे सकते हैं (हंसी)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अपनी जिन्दगी में मैंने यह काम कभी नहीं किया। (हंसी)

चौधरी रो ान लाल आर्यः क्या मुख्य मंत्री जी के नोटिस में है कि बेरोजगारी की वजह से बहुत से एमए, बीए पास

नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं? क्या आपने इसका सर्वे किया है कि बेरोजगारी की वजह से कितनी मौंते हुई है?

चौधरी भजन लाल: यह हो सकता है कि बेरोजगारी से तंग आकर नौजवानों ने खुदक ी कर ली हो। इन पढे लिखे नौजवानों के लिए हमने कई योजनाएं बनाई है ताकि ये रोजगार कर सकें। ये नौजवान अपने उद्योग धंधे लगा सकते है गवर्नमैंट फैसिलिटीज देती है।

चौधरी रो ान लाल आर्य: स्पीकर साहब, मैंने सवाला पूछा है कि कितने लडके बेरोजगारी के कारण मरे है?

चौधरी भजन लाल: यह कैसे बताया जा सकता है? मरने वाला कोई चिटठी छोड जाए ि कवह इस वजह से मर रहा है तब तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि 1982 में खुदक ी से 460 मौतें हुई है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि इन में से कितनी मौतें दहेज के कारण हुई है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने साल वाईज आत्म हत्याओं की संख्या बताई है और 1982 में टोटल आत्महत्यायें 640 हुई है। आत्म हत्यायें दो तरह की होती है– एक वह जो खुद खुदक ी कर लेते हैं और दूसरी वह जिनको खुदक ी करने के लिए मजबूर किया जाए जिनको मजबूर किया

गया उनकी संख्या 64 है और जिन्होंने खुदक ाी की है उनकी संख्या 46 है।

श्री भले राम: क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि सुसाइड करने वालों में औरतें ज्यादा है या मर्द ज्यादा है।

चौधरी भजन लाल: इनमें 232 मर्द है और 218 औरतें है।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब इन्होंने छोड दिया है। यह ठीक है कि लव–अफेयर्ज की वजह से इम्तिहान में फैल होने की वजह से किसी ने आत्महत्या कर ली हो। मुख्यमंत्री जी ने दो मेन कारण बताए है– एक डाउरी डिसप्यूट और दूसरा ड्रैडफुल डिसीजिज क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ड्रैडफुल डिसीजिज कौन कौन सी है, इन डिसीजिज को कम करने के लिए और पावर्टी को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टैप्स लिए है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार समय समय पर कार्यवाही करती है लेकिन इसमें अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, माननीय सदस्यों का भी सहयोग होना चाहिए। जब तक समाज से इस बुराई को जड से उखाड कर नहीं फैंक देंगे तब तक यह बुराई दूर नहीं हो सकती और इस काम को करने के लिए अपोजि ान के सदस्यों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना कि सरकार का।

श्री मनफूल सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायंगे कि खुदक ाी से जितनी मौंते हुई है इन में हरिजन कितने थे? (हंसी)

चौधरी भजन लाल: आप एक बात पूछना भूल गये हैं कि वहां पर हरिजनों के लिए जो रिजर्वे ान थी वह पूरी कर दी गयी है या नहीं। (हंसी)

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, सुसाइड के जो डिफरैंट–डिफरैंट केसिज बतायें है इन का मेन कारण पावर्टी और अन–एम्पलायमैंट रहा है। जो पढे लिखे ग्रेजुएट लडके है ये सुसाइड करने की कोि ा ा न करें इसके लिये इनकी सरकार क्या अन–एम्पलायमेंट भत्ता देने के बारे में कोई विचार रखती है?

चौधरी भजन लाल: इनको काम देने की बात सरकार सोचती है लेकिन घर बैठे भत्ता देने की बात सम्भव नहीं है। इनके लिए बाकायदा योजनायें बनी हुई है। ये लडके देहात में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा सकते है। सरकार उनको पैसा देगी, कम सूद पर ऋण देगी नो–हाउ की जानकारी देगी और दूसरी सहूलियतें देगी। जो माल ये तैयार करेंगे उनको बेचने की फैसिलिटी सरकार देगी लेकिन बेरोजगारी भत्ता देना संभव नहीं है।

श्री दया नन्द आर्य: स्पीकर साहब, एक एंटी डाउरी एक्ट है लेकिन इस एक्ट के तहत डाउरी का कोई भी केस दर्ज

नही किया जाता। क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि इस एक्ट को हरियाणा में लागू क्यों नही किया जा रहा?

चौधरी भजन लाल: जो एक्ट बना है बाकायदा उस पर कार्यवाही होती है इसके अलावा ज्यों ही डाउरी से संबंधित किसी बात का पता लगता है तो क्लास 1 आफिसर मौके पर जाता है और जांच करने के बाद सख्य से सख्त एक ान लिया जाता है।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने आत्महत्यायें की फिगर बताई। अगर उनके पास फीगर हो तो बता दें कि आत्महत्यायें की संख्या किस डिस्ट्रिक्ट में हाईयस्ट है और किस में लोएस्ट है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सन 1979 में अम्बाला में 20 मर्द और 11 औरतें, कुरूक्षेत्र में 10 मर्द और 9 औरतें, करनाल में 32 मर्द और 15 औरतें, जींद में 37 मर्द और 11 औरतें, हिसार में 39 मर्द और 23 औरतें, सिरसा में 4 मर्द और 10 औरतें, भिवानी में 21 मर्द और 17 औरतें, नारनौंल में 9 मर्द और 17 औरतें, फरीदाबाद में 6 मर्द और 6 औरतें, रोहतक में 35 मर्द और 74 औरतें, सोनीपत में 18 मर्द और 22 औरतें तथा गुडगांव में 1 मर्द और 3 औरतें ने आत्महत्या की है।

श्री मंगल सैन: मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि सन 1979 से लेकर 1982 तक कम ा: 460358618 और 460 मर्द और औरतों ने आत्महत्यायें की है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना

चाहता हूं कि जो लोग बेकारी के कारण मरे हैं जिनकी सरकार मदद नहीं कर सकी उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है ताकि बेकारी के कारण भविश्य में लोग इस प्रकार की आत्महत्यायें न करें?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरि चन्द हुडडा: स्पीकर साहब, हरियाणा में सन 1981 में 460 औरतें और पुरूशों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या का सम्बन्ध मौरेलिटी से है इसलिए मौरलिटी कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि छोटे से प्रान्त में 460 आत्महत्यायें हुई तो ये आत्महत्यायें सरकार को मौरल कैरेक्टर कमजोर होने की वजह से तो नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता।

श्री हरि चन्द हुडडा: स्पीकर साहब, आत्महत्या करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता।

Mr. Speaker: Do not waste the time of the House please like this.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, जब थाने से किसी केस में इन्वैस्टीगे ान ठीक तरह से न हो सके तो सीआईए स्टाफ को या सीबीआई को केस दे दिया जाता है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सीआईडी को जब कोई केस भेजा जाता है तो उसका क्या काइटेरिया है?

चौधरी भजन लाल: गुप्तचर विभाग सही मायनों में केस की जांच करता हैं आप तो वकील है आपको सारी बातों का पता है। पुलिस की एवीडेन्स होती है इसलिाए सीआईडी को केस भेजा जाता है ताकि सही जांच हो सके। हुडडा साहब कह रहे थे कि आत्महत्या से मोक्ष प्राप्त नहीं होता स्वर्ग में नहीं जाता। अगर हुडडा साहब ऐसा कोई कदम उठायेंगे तो देख लेंगे। (हंसी)

Land irrigated in the State

***144. Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total area of irrigated land for which abiana has been realized during the last three years in the State; and

(b) whether full supply of water was made available according to the requirement of crops sown on the land as referred to in part(a) above?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala)-

(a) The total area of irrigated land on which abiana has been realized during the last three years is detailed below:-

	Hectares	Acres
1979-80	1634688	4039461

1980-81	1801068	4450601
1981-82	1824710	4509023

(b) Yes. Full supply of water was made available according to the requirement of crops sown on the land.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पार्ट ए के जवाब में बताया है कि वर्शवार कितने एकड जमीन जिसको सिंचित किया गा है का आबियाना वसूल किया गया। मंत्री महोदय ने पार्ट बी के बारे में बताया है कि बीजी गई फसल के लिए पूरा पानी दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक गेंहू की फसल के लिए कृशि विभाग के मुताबिक कितने पानी की आव यकता मानते है? क्या उन्हें उसके मुताबिक पूरा पूरा पानी दिया गया है?

श्री अध्यक्ष: जैसी जैसी जमीन होगी वैसे वैसे ही पानी की आव यकता होगी। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मुखतलिफ काप्स के लिए कितना कितना पानी चाहिए वह मैं बता देता हूं। भाूगरकेन के लिए तीन फुट डैल्टा पानी चाहिए, पैडी के लिए 2.60 फुट डैल्टा, काटन के लिए 1.25 फुट डैल्टा, गेंहूं के लिए 1.25 फुट डैल्टा और बाजरे के लिए सिर्फ तीन इंच डैल्ट पानी चाहिए।

चौधरी हुकम सिंह फोगट: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि फसल बोने के बाद आव यकता फसल को पानी दिया जाता है। लोहारू कैनाल पर जो फसलें बोई गई गेहूं की बिजाई होने के बाद क्या उनको आव यकतानुसार पानी दिया जाता रहा है या नहीं?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, डब्लूजेसी और भाखडा कैनाल में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि यदि इनमें पानी की फुल सप्लाई न हो तो राटे ान के हिसाब से पानी दिया जाता है लेकिन जो लिफट इरीगे ान स्कीम्ज है उनके लिए कोई रोटे ान मुकरर्र हनी है। उनसे फसल की बीजाई के लिए और फसल के पकने तक के लिए जरूरत के मुताबिक उनको पूरा पानी देने का प्रयत्न किया जाता है। पिछले साल और इस साल उन लिफट कैनालज में फसल के वक्त पूरा पानी दिया गया।

श्री राम बिलास भार्मा: मंत्री महोदय ने बताया कि सन 1981–82 में 1509023 एकड जमीन का आबियाना लिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि महेंद्रगढ कैनाल से कुल कितना एरिया इरीगेट हुआ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: हर कैनाल के बारे में फिगर्ज मेरे पास नहीं है अगर आप अलग से नोटिस दे कर सवाल पूछेंगे तो जवाब दे दिया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, डिफरैंट क्राप्स के लिए डिफरैट नम्बर आफ टाईम्ज पानी देने से फसल पक जाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक बार पानी देने के बाद भी आबियाना पूरा ही वसूल किया जाता है? क्या वे इस बात के लिए भी विचार करेंगे कि जितनी बार पानी दिया जाये उसकी तारीख वगैरा नोट की जाये? अगर अब तक नहीं की जाती है तो क्या भविशय में नोट करेंगें?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, एक बार पानी देने से तो गेंहू की फसल पक नहीं सकती। अगर कोई फसल खराब हो जाये तो उसका आबियाना नौर्मली माफ नहीं हो सकता। तारीख तो जमीन मालिक खुद ही नोट करे कि कितनी बार पानी दिया गया और किस तारीख को दिया गया। महकमें वाले नोट नहीं करते।

श्री भागी राम: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर किसी किसान के दस या 15 किल्ले में नहर का पानी भी लगता है और टयूबवैल भी लगा हुआ है तो सरकार किस प्रकार से पता लगाती है कि इस खेत में नहर का पानी आया है या इसने टयूबवैल का आया है? जमींदार को नहर का भी आबियाना देना पडता है और साथ ही टयूबवैल का बिजली का खर्चा भी देना पडता है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: जहां तक मुझे ज्ञान है कि जिस एरिया में कैनाल लगती है उसमें पूरा ही आबियाना लिया जाता है। अगर किसी आदमी ने नहर और टयूबवैल का पानी लगाया है तो उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कई बार जब किसान की जमीन को पानी लग जाता है तो अपनी फसल तो बो देता है लेकिन दूसरा या तीसरा पानी मिलने से पहले ही नहर टूट जाती है। जैसे कि फतेहाबाद ब्रांच जो पक्की बन रही थी टूट गयी है। तकरीबन डेढ महीना तक वह नहर बन कर तैयार होगी। लेकिन जिन लोगों ने इस वि वास के साथ अपनी फसलें बोयी थी कि उनको पानी मिलता रहेगा उनकी फसलें खराब हो गयी है। क्या सरकार ऐसे लोगों को आबियाना माफ करने पर विचार करेगी?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आबियाना माफ करनके के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने रूल्ज बना रखे है। अगर रूल्ज में यह फाल करता होगा तो जरूर माफ करने पर विचार किया जायेगा।

श्री भले सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले साल नहरों में कितने क्यूसिक्स पानी आया और क्या वह पिछले सालों के मुकाबले में कम था या ज्यादा था।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो हमारी रिक्वायरमैंट थी और जितना पानी हमें पिछले तीन सालों में सप्लाई किया गया है वह मैं बता देता हूं। 1979–80 में हमारी रिक्वायरमैंट पर एकड फीट 5262430 थी ओर हमें पानी सप्लाई किया गया था 8435384 पर एकड फीट। इसी तरह से 1980–81 में हमारी जरूरत थी 5199921 पर एकड फीट और हमें सप्लाई किया गया 8211674 पर एकड फीट। इसी तरह से 1981–82 में हमारी जरूरत थी 5401609 एकड पर फीट और हमें सप्लाई किया गया 8543620 पर एकड फीट।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: मंत्री महोदय के नोटिस में क्या यह बात है कि मेरे हलके जुलाना में सुन्दर सब–ब्रांच में तो पानी है लेकिन माइनर्ज में पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर नोटिस में है तो क्या इसे ठीक करवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आज से पहले मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं लाये अगर लायेंगे तो हम जरूर इस बात का पता लगाने की कोि ा ा करेंगे कि ऐसा क्यों है और जल्दी से जल्दी दिक्कत दूर करने की कोि ा ा करेंगें। (व्यवधान व भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे माननीय सदस्य जानते हे कि एक या दो बार पानी देने के बाद

भी आबियाना पूरा ले लिया जाता है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी या कोई ऐसी प्रोपोजल उसके अन्डर कंसिड्रे ान है जिसके तहत जितना पानी किसान को दिया जाये वह नोट कर लिया जाये। कहने का मतलब यह है कि डेटस नोट कर ली जाये जिन दिनों में पानी दिया जाता है। जितना पानी उनको दिया जाता है उसी के हिसाब से उनसे आबियाना वसूल किया जाये।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, सरकार के विचाराधीन एक बात यह है कि जो आउटलैटस हैं उनके उपर मीटर लगाकर मीटर्ड सप्लाई भाुरू की जाये तीन चार पांच जगह पर हमने एक्सपैरीमैंट के तौर पर ऐसा भाुरू भी किया हुआ है। अगर कोई सदस्य यह चाहे और उसके एरिया के किसान भी चाहें कि उनको यहां पर भी ऐसे ही पानी की सप्लाई भाुरू की जाये ंतो हमें बता दे ंहम प्रबन्ध करने के लिये तैयार है।

चौधरी नर सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो टयूबवैल्ज का एरिया भी नहीं है और वहां पर नहरों का पानी भी टेल तक नहीं पहुंचता, क्या उसके लिये कोई उपाय करने पर विचार कर रहे है ताकि पानी टेल पर पहुंच सके।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, टेलों पर पानी न पहुंचने की ि ाकायत कुछ एरियाज में बडी कौनिक है। उसका मुख्य कारण यह है कि हैंड रीच पर जो किसान है वह

आम तौर पर अन–अथोराईज्ड पानी इस्तेमाल करता रहता है उसके लिये हमने कई उपाय किये हैं। नहरों के महकमें के आफिसर्ज भी ग त करते हैं और पुलिस के लोग भी ग त करते हैं और जो पकडा जाये। उसके खिलाफ फौजदारी मुकददमा दर्ज करवाते हैं और ऐसा करने वाले को पूरी सजा दिलाने की कोि ा ा करते हैं। मैं चौधरी नरसिंह जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इस मामले में हमसे सहयोग करें। वे लोगों की यह समझायें कि इस तरीके से नाजायज पानी इस्तेमाल न करें।

चौधरी नर सिंह: स्पीकर साहब, जैसे रेहडा माईनर और जखोली डिस्ट्रिब्यूटरी के एरियाज में पानी सिर्फ एक बार तो मिल जाता है जिससे लोग चना तो बो लेते है लेकिन वह पक कर तैयार नहीं होता। इसी तरह से लोग जो गेंहू बोते हैं वह भी पक नहीं सकती। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से मिलकर लोग माइनर्ज को कट कर लेते हैं और किसान को टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता क्या यह बात उनके नोटिस में हैं?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: सरकारी कर्मचारियों के बारे में अगर कोई स्पैसिफिक ि ाकायत हो तो बतायें, हम उसे जरूर देख लेंगे। हमने तो वहां पर पुलिस चैक बिठाने का भी प्रबन्ध किया है। इसके अलावा वहां पर कई कैसिज दर्ज भी किये गये हैं जिनमें पानी की चोरी पकडी गयी है। अगर उनके पास सरकारी कर्मचारियों के बारे में कोई स्पैसिफिक ि ाकायत हो तो बतायें।

ठाकुर बहादुर सिंह: मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। 1981782 में फतेहबाद ब्रांच में जाला पडने की वजह से किसानों को बडा भारी नुकसान हुआ था। ऐसा कई बार होता रहता है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई प्रबन्ध किया गया है या नहीं?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद ब्रांच में जाले की काफी ि ाकायत है उसके लिये जब तक तो हम उसे पीरियोडीकल बन्द करके उसकी सफाई करवा देते हैं जिसके लिये कई बार दो हफते लग जाते है। हम यह समझते है कि इसका बन्द करने से कई बार किसान को काफी नुकसान होता है। हम जाला साफ करने के लिये एक म ाीन खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भी देख रहे है कि कोई कैमीकल डालकर अगर उसमें जाला पैदा होने से बचाया जाये, तो वह भी किया जा सके, इस बारे में हम पहले से ही विचार कर रहे हैं।

Setting up of Depot and Sub-Depot of Haryana Roadways at Sirsa and Fatehabad

***170. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the dates on which the depots and sub depots of Haryana Roadways were set up at Sirsa and Fatehabad, separately;

(b) whether the constructed work on the building and the workshop of Haryana Roadways depot, Sirsa has been started; if not, the reasons therefore;

(c) whether the constrction work of the building of Fatehabad sub-depot has been completed; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the government to construct a Bus Stand at Sirsa; if so, the time by which the construction work thereon is likely to be started and completed?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) Sirsa Depot was set up on 1-4-1978. No sub depot at Fatehabad has been set up so far.

(b) The construction work could not be started as there was delay in obtaining possession of the land through acquisition.

(c) Does not arise.

(d) Yes. The construction of bus stand is likely to be started during the next financial year and efforts will be made to get the work completed before the close of next financial year subject to availablitiy of funds.

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि सिरसा डिपो 1–4–1978 को बन

गया था लेकिन फतेहाबाद में सब–डिपो भी नहीं है। वहां पर फतेहबाद में बस अडडा बन कर तैयार भी हो चुका है और उसके लिए 10–15–20 लाख रूपया खर्च भी हो चुका है अब तक भी सिरसा में बस अडडा बनाने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है इसका क्या कारण है?

कर्नल राव राम सिंहः मुख्य कारण श्री भागी राम जी खुद ही है। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, जब 1978 में एक दफा बस स्टैंड बनाने की प्लान बनाई गयी तो उस वक्त पोलीटिक्ल ग्राउन्डज पर जो जमीन इसके लिए सिलैक्ट होनी थी उसको बदल करके बरनाला रोड पर कर दिया गया। पता नहीं किस पोलीटीकल हिसाब–किताब से इन्होंने दूसरी जमीन एक्वायर करने की प्लान भाुरू कर दी। (व्यवधान व भाोर) चौधरी देवीलाल और भागी राम दोनों एक ही बात है। एक जगह हिसार रोड पर आलरेही जगह सिलैक्ट हो चुकी थी, 10 एकड जमीन ली हुई थी लेकिन 1978 में बरनाला रोड रोहडी रोड पर जमीन एक्वायर करने की प्लान बनायी गई। लेकिन वह जगह इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं थी। इसलिए 1980 में वह प्रोपाजल ड्राप कर दी गयी और हम ओरीजनल प्रोपोजल पर वापिस आ गए। अब ओरीजनल प्रोपोजल जो सब जेल के पास जमीन एक्वायर करने की थी वहां पर एरिया कुछ कम था इसलिए दूसरी जमीन 14 किल्ले के करीब एक्वायर हो गई है और नैक्सट फाइनैंि ायल ईयर में सिरसा बस स्टैंड पर

काम भुरू हो जायेगा और उम्मीद है कि अगले फाइनैंि ायल ईयर में सिरसा बस–स्टैंड बन कर तैयार हो जायेगा।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि वहां पर बस–अडडा न बनाने का कारण हम हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जब बने थे उसके बाद जो पहले वहां पर बस–अडडा बनाने के लिए जमीन ली गई थी उसको बदला गया। यह केवल बदले की भावना से बदला गया। कोई और दूसरा कारण नहीं है। फतेहाबाद बस–अडडा क्यों पहले बनाया गया। इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पर उप–चुनाव होना था। मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल सिरसा में बस स्टैंड बदले की भावना से नहीं बनने देना चाहिये क्या यह बात ठीक है?

Mr. Speaker: This is no question. Hon. Members question hour is now over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Enquiry into cases of irregularties in Civil Hospital, Mohindergarh

***158. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether any equiry has been instituted during the last one year into the alleged cases of irregualarities and corruption committed in the Civil Hopsital, Mohindergarh; and

(b) if so, the action, if any taken thereon?

स्वास्थ्य मंत्री श्रीमति प्रसन्नी देवीः

(क) जी हां।

(ख) मामले में आगामी कार्यवाही करने का प्र न सरकार के विचाराधीन है।

Payment of Electricity Charges by the Market Committee

***165. Chaudhri Kulbir Singh Malik:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) whether any expenditure has been incurred during the last two years by any of the Market Committees in the State, on the installation of Sodium Lamps and Tubes, outside the mandi areas; if so, Market Committee-wise details thereof, and

(b) whether the Market Committees are competent to incur expenditure on electricity maintenance outside their respective territories?

कृशि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह): (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। विपणन समितिवार ब्यौरा अनुबंध ए में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। विपणन समितियां अपने क्षेत्र (अधिसूचित मार्किट ऐरिया) के बाहर बिजली के संधारण पर खर्च करने में सक्ष्म नहीं है।

अनुबंध 'ए'

मंडी क्षेत्र से बाहर वर्श 1981–82 और 1982–83 (28–2–83 तक) सोडियम वेपर लैम्पस और टयूबस पर जिलावार खर्च को द र्ाते हुए विवरण।

क्र.स.	मार्किट कमेटी का नाम	1981–82	1982–83	जोड
1	2	3	4	5
अम्बाला जिला		रू0	रू0	रू0
1	अम्बाला भाहर	348893.20	–	348893.20
2	नन्योला	–	–	–
3	अम्बाला छावनी	410789.91	–	410789.91

4	बराडा	34713.00	—	34713.00
5	जगाधरी	71877.50	—	71877.50
6	यमुनानगर	18232.50	—	18232.50
7	छछरौली	35938.75	—	35938.75
8	मुलाना	34723.00	—	34723.00
9	सडौर	16747.50	—	16747.50
10	नारायणगढ	45708.00	—	45708.00
11	रायपुररानी	45708.00	24745.51	70453.51
12	कालका	71822.85	—	71822.85
	जिला कुरूक्षेत्र			
13	थानेसर	—	101111.25	101111.25
14	पीपली	29000.00	—	29000.00
15	भााहबाद	57777.86	5777.78	63555.64
16	लाडवा	80889.00	—	80889.00
17	रादौर	—	—	—

18	इस्मैलाबाद	—	—	—
19	पेहवा	77504.00	—	77504.00
20	ढांड	71333.00	—	71333.00
21	पुण्डरी	—	—	—
22	कैथल	68400.00	—	68400.00
23	चीका	35057.26	—	35057.26
24	सिवानी	13321.00	—	13321.00
	जिला करनाल			
25	करनाल	—	—	—
26	तरावडी	79284.99	—	79284.99
27	निसंग	69302.00	—	69302.00
28	घरौंडा	49588.30	—	49588.30
29	पानीपत	55632.00	—	55632.00
30	मडलौडा	—	—	
31	समालखा	23800.00	4000.00	27800.00

32	अंसध	49846.50	—	49846.50
33	इन्दरी	128947.75	—	128947.75
34	नीलोखेडी	—	—	—
	जिला सोनीपत	41826.00	—	41826.00
35	सोनीपत	—	—	—
36	गोहाना	—	—	—
37	गनौर	—	—	—
	जिला जींद			
38	जींद	60776.00	—	60776.00
39	जुलाना	15193.75	—	15193.75
40	सफीदों	30679.50	—	30679.50
41	नरवाना	51453.66	15217.36	66671.02
42	उचाना	21565.20	9241.35	30806.55
43	पीलूखेडा	—	—	—
44	कलायत	24486.00	—	24486.00

	जिला रोहतक			
45	रोहतक	—	—	—
46	महम	—	—	—
47	सांपला	11787.30	—	11787.30
48	बहादुरगढ	13951.62	—	13951.62
49	झझर	—	—	—
50	कोसली	—	—	—
	जिला गुडगांव			
51	गुडगांव	17081.00	10248.60	27329.60
52	पटौदी	9300.00	—	9300.00
53	फिरोजपुर झिरका	—	—	—
54	पुनहाना	—	—	—
55	नूंह	62215.00	—	—
56	सोहना	—	—	—
57	तावडू	66910.00	—	—

	जिला फतेहाबाद			
58	फरीदाबाद	—	—	—
59	पलवल	—	—	—
60	होडल	—	—	—
61	बल्ल्वगढ	—	—	—
	जिला महेंद्रगढ			
62	नारनौल	—	10400.00	10400.00
63	अटेली	—	—	—
64	रिवाडी	—	20825.00	20825.00
65	कनीना	30607.50	—	30607.50
66	महेंद्रगढ	—	61760.00	61760.00
	जिला भिवानी			
67	भिवानी	45900.00	—	45900.00
68	चरखी दादरी	—	—	—
69	लोहारू	—	—	—

70	जुई	—	—	—
71	तोशाम	—	—	—
72	बहल	—	—	—
73	सिवानी	—	—	—
	जिला हिसार			
74	हिसार	165200.00	—	165200.00
75	हांसी	40933.13	—	40933.13
76	बरवाला	—	—	—
77	उकलाना	—	—	—
78	भूना	—	16480.00	16480.00
79	टोहाना	413434.44	—	413434.44
80	रतिया	—	—	—
81	जाखल	—	—	—
82	फतेहाबाद	74352.00	—	74352.00
83	भटटूकंला	16922.96	—	16922.96

84	आदमपुर	1872.00	—	1872.00
	जिला सिरसा			
85	सिरसा	—	163625.00	163625.00
86	डींग	—	—	—
87	कलावाली	28184.38	—	28184.38
88	डबवाली	6210.00	70360.00	76570.00
89	एलनाबाद	—	—	—

Construction of Roads

***195. Shri Inder Sing Nain:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following road-

(i) Kapro to Banbhori;

(ii) Koth Kalan to Khapar (Jind);

(iii) Bhaini Amirpur to be linked by a new road to join Narnaund Jind road;

(iv) Link road to village Kundanpur (near Uklana Mandi);

(v) Lind road to join Hisar-Barwala road to Dhani Garan; and (vi) Lind road from Hansi-Barwala road to Dhani Khan Bahadur village; and

(b) if so, the date from which the work is likely to be started and the period within which it is likely to be completed?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान):

(ए) जी हां।

(बी) कमांक 2, 4, 5 और 6 पर वर्णित चार सडकों पर निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है। यह सडके मार्च 1985 से पहले पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। बाकी सडकों पर कार्य तभी भुरू हो सकेगा जब इन के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध होगा।

Upgradation of Schools

***200. Shri Basanti Devi:** Will the Minister of State for Education be pleased to state:-

(a) the number of Government Schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High, in the State during the year 1980-81;

(b) the month in which the Schools, referred to in part(a) above, are upgraded; and

(c) whether the required staff and other facilities are provided simultaneously upon the upgration of the Schools?

ि ाक्षा मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) प्राथमिक से माध्यमिक 149 और माध्यमिक से उच्च 101।

(ख) अप्रैल 1980 के अक्तूबर 1980 तथा मास दिसम्बर 1980 के दौरान बढाया गया।

(ग) जी नहीं।

Supply of canal water to Rohtak District

***206. Chaudhri Om Parkash:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that canal water for irrigation was supplied to Rohtak District lesser than its due share in the months of October, November and December, 1982 while the adjoining Districts were given more than their due share during the above said period; if so, the reason therefore; and

(b) whether it is also a fact that the canal water for irrigation it still being supplied to district Rohtak lesser than its due share?

(c) whether the required staff and other facilities are provided simultaneously upon the upgration of the Schools?

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला):

(क) यह ठीक नहीं है कि रोहतक जिले को सिंचाई के लिये, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 1982 के महीनों में, नहरी पानी इसके उचित हिस्से से कम दिया गया जब कि इसके साथ लगने वाले जिलों को इसी समय के दौरान उनके हिस्सों से ज्यादा पानी दिया गया।

(ख) यह ठीक नहीं है कि रोहतक जिले को अभी भी सिंचाई के लिये नहरी पानी इसके उचित हिस्से से कम दिया जा रहा है।

Industrial units set up by Indians living abroad

***216. Sh. Kanwal Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the total numer of industrial units set up in Haryana by the Indians living abroad during the year 1980-81, 1981-82 & 1982-82; and

(b) the number of such units out of those referred to in part (a) above, set up after the tour undertaken by the Chief Minister to foreign countries to motivate entrepreneurs togetherwith the number of such cases pending final disposal?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन सिंह): (क) भारतीय अनावासियों द्वारा प्रमोट कुल यूनिट रजिस्टर किये गये निम्न प्रकार से हैं–

1980–81	3
1981–82	27
1982–83	125
कुल योग	155

यहां यह सूचित किया जाता है कि भारतीय अनावासियों से 586 प्रार्थना पत्र हरियाणा में औद्योगिक प्लाटों के लिए प्राप्त हुये है। इनमें से 196 केसिज में आ ाय पत्र/अलाटमैंट पत्र जारी किये गये है।

इन 196 में से 155 व्यक्तियों ने अपनी इकाईयों को पंजीकृत कराया है 155 पंजीकृत इकाईयों में से 53 इकाईयां सक्रिय रूप से कार्यान्वित है।

(ख) मुख्यमंत्री महोदय की यात्रा के उपरान्त पंजीकृत इकाईयों का विवरण निम्न प्रकार है–

1981–82	27
1982–83	125
कुल योग	152

पंजीकृत के लिए कोई केस विलम्बित नहीं है। फिर भी 154 प्रार्थना पत्र भूमि नियतन के लिए अन्तिम निपटान हेतु विलम्बित है।

Bus Stand at Ambala City

***321. Chaudhri Bhag Mal:** Will the Minister of Transport be pleased to state:-

(a) the total expenditure incurred on the construction of Haryana Roadways Bus Stand at Ambala City togetherwith the date of the completion of the construction thereof; and

(b) whethter any expenditure has been incurred on the repairs of the building, as referred to in part(a) above, after its completion; if so, the total expenditure incurred on such repairs together with the dates on which the repairs were undertaken?

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) 1178067.87 रूपए। निर्माण कार्य दिनांक 15—4—72 को पूर्ण हो गया था।

(ख) जी हां। 75002.37 रूपए। भोश सूचना के सम्बन्ध में अनुबन्ध 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

अनुबन्ध 'क'

भवन की मुरम्मत एवं सफेदी आदि पर अब तक 75002. 37 रूपए की रा ि ा व्यय की गई है जिसका ब्यौरा निम्न रूप से है—

वर्श	खर्च की गई रा ि ा रू0	कार्य जो किया गया
1976—77	2370.92	मुरम्मत / सफदी
1978—79		
1—7—78	19930.00	अम्बाला भाहर बस अडडे पर अतिरिक्त निर्माण कार्य (अन्दर तथा बाहर जाने की सडक)

6—11—78	3000.00	खम्बे का निर्माण
3—12—78	5000.00	अम्बाला भाहर लोकल बस अडडे की वि ोश मुरम्मत।
5—12—78	14200.00	अम्बाला भाहर लोकल बस स्टैंड पर ईंटों के फ र्ा का बिछाना।
7—3—79	1881.45	छत के पंखों व लाईटों की मुरम्मत।
30—9—80 (80—81)	16370.00	चार दिवारी निर्माण/ मुरम्मत तथा सफेदी।
22—2—83 (82—83)	12250.00	नारायणगढ दि ाा की ओर बस अडडें की चार दिवारी का निर्माण।

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

एच0सी0एस0 अधिकारियों में व्याप्त रोश सम्बन्धी

श्री मंगल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैन ान मो ान एचसीएस औफिसर्ज के बारे में दी है। उनका

चंडीगढ में एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने ि ाकायत की है कि सरकार के सीनियर औफिसर्ज उनकी प्रोमो ान में रूकावट डाल रहे है। सिलैक ान ग्रेड उनको दस साल की बजाए बारह साल में दिया जाता है। आईएएस औफिसर नौ साल में ज्वांएट सैक्रेटरी बन जाता है लेकिन उनकी प्रोमो ान का कोई चांस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बडा सीरियस मामला है। इसमें एडमिनिस्ट्रे ान पर बडा असर पड रहा है।

श्री अध्यक्षः वह मेरे पास पहुंच गयी है। मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं और कल तक उसके बारे में बता दूंगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन ान मो ान दी थी।

श्री अध्यक्षः मैं उसको भी कंसीडर कर रहा हूं।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब मैं विभिन्न कार्यों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा अपनी तीसरी रिपोर्ट में नियम किए गए टाईम टेबल की रिपोर्ट पे ा करता हूं।

“The Committee met at 11.30 a.m. on Monday the 21st March, 1983, in the Chamber of the Hon. Speaker.

The Committee after some discussion, recommended that the business on 22nd, 23rd; 24th & 25th March, 1983 be transantioned by the Sabha as follows:

Tuesday, the 22nd March, 1983 (9.30 AM)	1. Question Hours. 2. Presentation and adoption of the Third Report of the Business Advisory Committee. 3. Discussion and voting on Demands for Grants on Budget.
Wednesday, the 23rd March, 1983 (9.30 AM)	1. Question Hours. 2. Motion under rule 30 regarding transaction of Government business on Thursday, the 24th March, 1983. 3. The Haryana Appropriations Bill, 1983 in respect of Budget. 4. The Haryana Appropriation Bil, 1983 in respect of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1982-83. 5. The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1983 alongwith the resolution of disapprovel of the Ordinance

	given by Shir Mangal Sein. 6. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1983.
Thursday, the 24th March, 1983 (9.30 AM)	1. Question Hours. 2. Presentation of Reports of Assembly Committees and Papers to be paid on the Table of the House, if any. 3. Offcial resolution regarding raising the limit of loans by the Haryana State Electricity Board from Rs. 250 crores to 400 crores. 4. Legislative Business (i) The Haryana Forest Development Bill, 1983 alongwith the resolution of the disapproval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein. (ii) The Maharshi Dayanand University (Amedment and Yalidation) Bill, 1983 alongwith the resolution of the Ordinance given by Shri.

	Mangal Sein.
Friday, the 25th March, 1983 (9.30 AM)	1. Question Hours. 2. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha sinedie. 4. Presentation of Reports of Assmebly Committees and Papers to be laid on the Table of the House, if any. 5. Legislative Business (i) The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1983 alongwith the resolution of disapproval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein. (ii) The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1983. (iii) The Punjab Panchayat Samities (Haryana Amendment) Bill, 1983. 6. Discussion on Motion under

	rule 84.
Shri Mangal Sein Shri Hira Nand Arya	(1) That the policy in regard Tripartite talks relating to the territorial disputes and River Water Issue and the stand taken by the State Government in this behalf be discussed.
Shri Hira Nand Arya	(2) That the day to day postponement of construction of Sutlej Yamuna Link Canal in the Punjab Territory, be discussed.
Shri. Mangal Sein	(3) That the Annaul Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 which was laid on the Table of the House on the 9th March, 1983 be discussed.
1. Shri Shiv Parshad 2. Shri Ram Bilas Sharma 3. Shri Devi Dass 4. Shri Mangal Sein	(4) That the Annual Administration report of Haryana State Electricity Board for the year 1979-80 which was laid on the table of the House on the 15th March,

	1983 be discussed.
-do-	(5) That the Annual Administration report of Haryana State Electricity Board for the year 1980-81 which was laid on the table of the House on the 15th March, 1983 be discussed.
-do-	(6) That the Annual Statement of Accounts of Haryana State Electricity Board for the year 1978-79 which was laid on the table of the House on the 15th March, 1983 be discussed.
-do-	(7) That the Annual Financial Statement (Budget Estiamtes) of Haryana State Electricity Board for the year 1982-83 which was laid on the table of the House on the 15th March, 1983 be discussed.
-do-	(8) That the 14th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corpotation for the year 1981-82 which was laid on the table of the House on the 15th

	March, 1983 be discussed.
-do-	(9) That the 15th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corpotation for the year 1981-82 which was laid on the table of the House on the 15th March, 1983 be discussed.
-do-	(10) That the 13th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corpotation for the year 1979-80 which was laid on the table of the House on the 15th March, 1983 be discussed.
-do-	(11) That the 14th Annual Report and Accounts of Haryana State Small Industries and Export Corpotation Ltd. for the year 1980-81 which was laid on the table of the House on the 15th March, 1983 be discussed.

Smt. Chandravati stressed that non-official day on Thursday the 24th March, 1983 be not converted into an official day, which was not agreed to by the other members of the Committee.

श्री अध्यक्षः आप पार्लियामैंटरी अफैयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन बिजनैंस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Mr. Speaker, Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

श्री मंगल सैन, रोहतकः अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी अफैयर्ज मिनिस्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसकी मुझे खबर नहीं भेजी। मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्षः मीटिंग की खबर तो सब को भेजी थी। हो सकता है आपको खबर न मिली हो। उस वक्त हाउस चल रहा था जब खबर भेजी थी। बहन चन्द्रावती को भी खबर भेजी थी और वे आई थी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुझे खबर नहीं मिली। आपको पता ही है कि मैं सब मीटिंग्ज में भागमिल होता हूं। स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि काफी हैवी बिजनस है। काफी रिपोर्टस है जिनके बारे में मैम्बर्ज ने अपने विचार एक्सप्रैस करने है। मैंबर साहिबान के नोटिस दिए गए है और अच्छा व्यक्त की है कि रिपोर्टस पर डिस्क ान की जाए। स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रे ान रिपोर्टस तैयार करता है और उनको सदन में रखा जाता है जिससे की हाउस के मैम्बर उस पर विचार व्यक्त कर सकें। उन पर डिस्क ान करने को उनको मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेसी में कोई बात छुपी तो नहीं रह सकती। हाउस में डिस्क ान करने के लिए ही ये तैयार की जाती है। अगर सदस्यों को टाईम नहीं मिलेगा अपरचुनेटी नहीं मिलेगी तो फिर इन रिपोर्टस को सदन में रखने का क्या फायदा और इस बारे में हम कहां बात कर पाएंगें।

स्पीकर साहब, अब आप देखिये कि नान–आफिि ायल डे एक ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हर मैंबर अपनी अपनी बात कह सकता है उसको भी ये कन्वर्ट करना चाहते है। ठीक है किन नान–आफिि ायल प्रस्ताव ट्रैजरी बेनचिज का था। हमारे माननीय सदस्य उस पर आग्रह करते रहे थे कि इसको पास होना चाहिये अब ये उसको पास करने के लिए तैयार नहीं है वे अपने ट्रेजरी बैनचिंज के मैंबर की बात मानने के लिये भी तैयार नहीं है। हमारी बात ये क्यों मानेगें? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

वह प्रस्ताव भी पास होना चाहिये और हमने जो रेजोल्यू ान मूव किये गए है वे सभी हाउस के सामने आने चाहिये और उन पर भी पूरी तरह से दिल खोल कर डिस्क ान होनी चाहिये और इस नान–आफि ायल डे को आफि ायल डे में कंवर्ट नहीं करना चाहिये। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं चौधरी भजन लाल जी कि आपको अब कोई खतरा नहीं है मैजोरिटी आपके साथ है। जो आपकी बदनामी का कारण बन सकते है ऐसे लोगों को निकाल दों, उन लोगों से अपना पीछा छुडाओं बहुमत आपके साथ है आराम से इस से ान को चलने दो। आपकी भागने की क्या पडी है? अगर चार–पांच दिन सै ान और चल जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पडने वाला है। मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब पुरजोर यह कहूंगा कि यह प्रस्ताव नहीं मानना चाहिये और आप दोबारा बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाएं और इस से ान को तीन–चार दिनों के लिये और एक्सपैंड करवाएं ताकि सभी मैंबरों को खुले दिल से बोलने का मौका मिले। मेरी पुरजोर आपसे यही अपील है।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैंन मीटिंग में भी अर्ज किया था कि यह जो से ान जल्दी समाप्त करने जा रहे है यह ठीक नही है बडा थोडा टाइम मैंबर्ज को बोलने के लिये मिला है इसलिये सै ान का समय बढाया जाए और नान–आफि ायल डे को आफि ायल डे में कंवर्ट न किया जाए। मैंने उस समय भी कहा था कि हमारे साथी किसी की लैपस की वजह से नहीं पहुंच

पाए है इसलिये मैंने इस बात के लिए एग्री नहीं किया था। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह बजट सै ान है। बजट से संबंधित फाइनैन्स से संबंधित जो भी रिपोर्टस है वे इतने थोडे समय में डिसकस नहीं हो पाएगी और सभी मैंबर साहेबान अपने अपने विचार व्यक्त न करेंगे और उन लोगों के विचार जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है इस हाउस में न रखेंगे उनके साथ भी हम अन्याय करेंगे। हमारे पास बोलने के लिये सरकार के खिलाफ काफी मैटर है सरकार की पालिसीज के बारे में हमें अपने विचार रखने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। अकेले इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड के बारे में भी आप देख लें कि उस पर बोलने के लिये कम से कम हमें एक दिन का समय चाहिये। अगर 25 तारीख को ही यह सै ान खत्म होने वाला है तो सारी चीजों के उपर डिस्क ान नहीं हो सकेगी। मैं तो यह कहूंगी कि जिन लोगों के वोट लेकर हम यहां पर आए हैं उसके साथ यह अन्याय होगा अगर सभी माननीय सदस्यों को सारी बातों पर बोलने के लिये समय नहीं दिया जाएगा। हम यहां पर यह नहीं बता पायेंगे कि पब्लिक के पैसे के साथ बडी बेईमानी हो रही है। पब्लिक के सारे पैसे को बुरी तरह से खाया जा रहा है। जब तक हम अपने विचार यहां पर नहीं रखेंगे तब तक हम पब्लिक के पैसे को कैसे मिसयूज होने से बचा पायेंगे। अगर हमें तीन चार दिन और मिल जाएं। सै ान तीन चार दिनों के लिये और बढ जाएं तो हमें अपने विचार रखने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। हम तभी सरकार की इररैगूलैरेटीज को यहां पर बता पायेंगे। इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से यह अपील

है कि इस सै ान को तीन चार दिनों के लिये और बढा दिया जाए इससे सरकार को कोई फर्क पडने वाला नहीं है। सरकार जो भागने की कोि ा ा कर रही है उसे कोई खतरा नहीं है बहुमत उसके साथ है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जब से सै ान भाुरू हुआ है और पहली रिपोर्ट आपने सदन के सामने प्रस्तुत की है तब से बारहा हम सरकार से कह रहे है कि इतना बिजनैस अभी हमारे सामने हैं और इसके लिये इतना टाइम हमें बोलने के लिये चाहिये पिछले 34–35 सालों के बाद जैसा कैसा हमने डैमोक्रेटिक सिमम इंवाल्व किया है आप देखे उस सिस्टम में किसी भी विधान सभा में इस तरह की बात नहीं हो रही है। स्पीकर साहब, हमारे पडोस में पंजाब विधान सभा का सै ान चल रहा है उनकी बिजनैस लिस्ट देखने का हमें मौका मिला इतना ओवर लोडिड नहीं है जितना कि यहां पर है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि अकाली सदस्य सै ान में नहीं आ रहे है। अगर वे आते तो भाायद और ओवर लोडिड होता फिर भी उनका सै ान 25 तक चल रहा है। स्पीकर साहब, 25 तारीख का जो कार्यक्रम रखा है उसमें 14 मो ानज अन्डर रूल 84 डिस्क ान के लिये हम पर ठोंस दिये गए है। अगर आप हरेक मो ान के उपर आधा आधा घण्टा डिस्क ान अलाउ करें फिर भी कम से कम 7 घंटे तो हमें इन मो ान्ज के लिये ही चाहिये। इतना बडा बिजनैस तीन दिनों के लिये जो बना रखा है यह कोई उचित बात नहीं की गयी है। स्पीकर साहब,

डाक्टर साहब ने भी कहा है कि इस डैमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। अगर यह सरकार इसी तरह से यहां पर गैग करके अपोजि ान वालों को दबाना चाहती है और अपनी मांगू यूं ही मनवाना चाहती है तो फिर हमारा यहां पर बोलने का क्या फायदा है। फिर तो हमने यूं ही यहीं पर 15 दिन खराब किये हम चले जाते है। जहां पर सरकार अंगूठा लगवाना चाहती है हम लगा देते है। फिर यहां सै ान बुलाने का क्या फायदा है। कल पांच डिमांडज के लिये डिस्क ान के लिये केवल एक घण्टा मिला औ सरकार की तरफ से जवाब देने के लिये डेढ घण्टा लिया गया। केवल चार विपक्ष के लोग ही उस पर बोले और आज लगभग 20 डिमांडज है उस पर भी एक घण्टा ही बोलने के लिये मिलेगा और डेढ घंटा सरकार को जवाब के लिये मिलेगा। इस प्रकार से इस सारे सिस्टम का सत्याना ा किया जा रहा है। इससे तो हमारा और तीन चार दिन रूकने का कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार ने अपनी ही मनमानी से सै ान का काम चलाना है तब हम तो यह समझेंगे कि यह सरकार हमारे विचार बिल्कुल सुनना नहीं चाहती कोई कंस्ट्रीकटिव बात अगर हम कहेंगे भी तो भी सरकार ने न ही कहनी है। कोइ बात अगर हमारे मुंह से अच्छी निकलती है तो उनका भी जवाब देने की कोि ा ा कोइ बात अगर हमारे मुहं से अच्छी निकलती है तो उनका भी जवाब देने की कोि ा ा करते हैै और उसे भी गल्त ही बताते हैं यह नहीं कहते कि अपोजि ान की तरफ से यह बात सही कही गयी है। केवल एक आध मिनिस्टर को छोडकर कोई भी मिनिस्टर

हमारी बात जो कि जनता कि भलाई के लिये कही गयी हो, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे कल भाई सुरेन्द्र सिंह जी ने हमारी कई बातों को माना है इसमें कोई आपति वाली बात नहीं है। कुछ अच्छी अच्छी बातें हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते है। हमें भी पूरा अधिकार है। हम यह भी मानते है कि हमारी कई बातें इररैलेवैन्ट हो सकती है जो सरकार को न भाती हो लेकिन जिन बातों से हम सरकार का साथ देना चाहते हो। कम से कम उन बातों को सरकार को तो मानना चाहिये। इस तरह की बातें जो आने वाली पीडियों के लिये भी सही हो, इस तरह की कार्यवाही सरकार को यहां पर करनी चाहिये। अगर सै ान चार पांच दिनों के लिये और एक्सटैण्ड हो जाएगा तो इसमें कोई आपति वाली बात नहीं होगी और हर मैम्बर अपने अपने विचार अपनी मर्जी से और खुले दिल से यहां पर दे सकेगा। इसलिये मेरी तो सिर्फ सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि इस मौ ान को तीन चार दिनों के लिये और बढाया जाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, कल हाउस मीट करने से पहले 11.30 बजे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी। अपोजि ान की तरफ से डा0 मंगल सैन जी, श्रीमति चन्द्रावती और चौधरी देवी लाल जी को इंवाइट किया गया था। डा0 मंगल सैन जी ने कहा कि उनको किन्हीं कारणों से नोटिस नहीं मिला। श्रीमति चन्द्रावती जी मीटिंग में आयी थी और देवीलाल जी नहीं आये। इधर ट्रैजरी

बैनचिंज की तरफ से भी कुछ मंत्रीगण उपस्थित थे। हमने 12.00 बजे तक डाक्टर मंगल सैन जी की इन्तजार की लेकिन वे नहीं आये। सरकार की कभी यह मं ाा नहीं रही कि अपोजि ान को कोई आदमी कंट्रीब्यूट न करे। मीटिंग में जो डिस्क ा हुआ उस पर लीडर आफ दी अपोजि ान ने यह कहा कि चूंकि उनके साथी इस मीटिंग में उपस्थित नहीं है इसलिये मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकती। स्पीकर साहब, पहली मीटिंग में जब ये सभी मौजूद थे तो वहां पर किसी वजह से मौजूद थे हालांकि वे इस कमेटी के मैम्बर नहीं थे। फिर भी वे दोनों इस बात से एग्री करते थे कि उस दिन को कंवर्ट कर दिया जाए लेकिन डा0 मंगल सैन और श्रीमति चन्द्रावती जी इस बात को नहीं माने थे वे इसको कंवर्ट कर दिया जाए। वे तो एक बात मैं न मानूं वाली बात पर ही अडे रहे।

श्री मंगल सैनः मैं न मानूं वाली बात ये गलत कह रहे हैं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, यहां पर यह बात भी कही गयी कि हमारे मैम्बर्ज को बोलने का समय नहीं मिला। यह बात इनकी गलत है। आपको पता ही है कि इनकी तरफ से इतना रैपीटि ान हुआ कि एक एक मैम्बर एक बात को ही कम से कम पांच पांच दफा बोला होगा। मेरे विचार से तो इनका एमुनी ा नही एग्जास्ट हो चुका है। स्पीकर साहब, अब अगर ये थोथे फायर करना चाहते है तो दूसरी बात है। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह इनका एलीगे ान बेसलैस है और अपनी चमडी बचाने की बात है कि हमारा एमुनी ान खत्म हो गया है। हमारे पास उनके खिलाफ बहुत कुछ है। हम डिपार्टमैंट स की वर्किन्स के बारे में भी कहेंगें और इनको अच्छे सुझाव देंगें। स्पीकर साहब, हमने अब तक कोई भी बात रिपीट नहीं की।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी का कहना था रूल 84 के तहत 14 मो ान एक दिन में रख दिये। स्पीकर साहब, टैक्नीकल तो ये 14 मो ान है लेकिन प्रेक्टीकल ये चार ही बनते है। जैसे बिजली बोर्ड के 6 मो ान है उनके उपर एक साथ डिस्क ान हो सकती है। इसी तरह से त्रिपार्टी बातचीत का एक मो ा हो जाएगा एक मो ान फाइनैंि ायल कार्पोरे ान का है और इंडस्टरी डिपार्टमैंट का है। इस तरह से चार मो ान बनते है और टाईम काफी है। (विघ्न) इनको ज्यादा टाईम देने के लिये आपने बिल्कुल ठीक सुझाव रखा कि नान–आफिि ायल–डे को आफिि ाय–डे में कंवर्ट कर दिया जाए। उस दिन जो रैजोल्यू ान आना था वह हमारे मैम्बर का था, ये वैसे ही खामखाह की बात कर रहे है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये पिछली मीटिंग में एक दिन की एक्सटैन् ान की डिमांड कर रहे थे और आज तीन दिन की डिमांड करने लग गये। जो एक दिन कंवर्ट किया गया है वह

इनकी मरजी के मुताबिक किया गया है। इसलिये हाउस इस रिपोर्ट को एडाप्ट कर लें।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वाक आउट

आवाजेंः स्पीकर साहब, हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं। (इस समय विरोधी पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये)।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस एडमिनिस्ट्रे ान की 1978 की रिपोर्ट अब आ रही है। मैं दर्खास्त करूंगा कि हर साल की रिपोर्ट टाइम पर आनी चाहिए ताकि उस पर अच्छी तरह से डिस्क ान हो सके।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः अब वर्श 1983–84 के बजट की डिमांड फार ग्रांटस पर डिस्क ान होगी। पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाइम बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी हुई सभी डिमांडज एक साथ पढी गई तथा मूव की गई समझी जाएगी। आनरेबल मैंबर किसी भी डिमांड पर बोल सकते है। लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हो। हर बोलने वाले मैम्बर को दस दस मिनट का समय दिया जाएगा।

That a sum not exceeding Rs. 106595850 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 2-**General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. 340911850 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 3-**Home.**

That a sum not exceeding Rs. 1017125295 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 9-**Education.**

That a sum not exceeding Rs. 633057590 for revenue expenditure and Rs. 32905600 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 16-**Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 719575640 for revenue expenditure and Rs. 112500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 23-**Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 7051670 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 39062365 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 5-**Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 142833095 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 6-**Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 142686460 for revenue expenditure and Rs. 3700000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 7-**Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 256384000 for revenue expenditure and Rs. 250604960 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 8-**Building and Roads.**

That a sum not exceeding Rs. 21184920 for revenue expenditure and Rs. 2500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 11-**Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. 52499215 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 12-**Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 123065040 for revenue expenditure and Rs. 11824000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 13-**Social Welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 18826960 for revenue expenditure and Rs. 1195826460 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 14-**Food and Supply.**

That a sum not exceeding Rs. 14633140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 19-**Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 116857560 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 20-**Forest.**

That a sum not exceeding Rs. 8765345 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 24-**Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 1264918000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 25-**Loan and Advances by State Government.**

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): स्पीकर साहब, फाइनैं । मिनिस्टर साहब ने जो बजट पे । किया है उसकी कुछ डिमांडज तो कल पास हो चुकी है और बाकी आज पास होने जा रही है। स्पीकर साहब फाइनैं । मिनिस्टर साहब भी मेरे ही भाहर के हैं और मुझे पता हे कि उन्होंनें किस मजबूरी और किस मायूसी के अन्दर यह बजट पे । किया है। जो इन्होंने बजट का घाटा पूरा करने के लिये बातें रखी है ये भी किसी मजबूरी में आकर ही रखी है। अगर आप इसकी तसदीक चाहते है तो आप अखबार में छपा हुआ इनक फोटो देख सकते हैं। जब ये बजट पे । करने के लिये आ रहे थे उस समय प्रैस वालों ने इनका फोटो खींचा था। आप

इस फोटो को देख कर अन्दाजा लगा सकते है कि मंत्री महोदय ने किस मजबूरी के अन्दर ये सुझाव दिये। सेल्ज टैक्ट बढाने और सैस लगाने के बारे में इन्होंने बडे मासूमाना अन्दाज से कहा कि यह जो घाटा पूरा करने के लिए सेल्ज टैक्स बढाया जा रहा है यह दुकानदार पर पडेगा। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडयूस पर सैस लगाया है यह भी खरीददार पर पडेगा। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी ई वर सिंह पदासीन हुए)** चेयरमैन साहब, यह तो वही बात है कि एक आदमी घोडे पर सवार होकर जा रहा था और उसके पास 30–40 किलो वनज भी था। वह आदमी घोडे पर सवार था और जो सामान था वह उसने अपने सिर पर रखा हुआ था। रास्ते में एक आदमी उसे मिला और पूछा कि यह बोझा आपने सिर पर क्यों रखा है घोडे पर क्यों नहीं रख लेते तो उसने जवाब दिया कि यह घोडा कमजोर है इसलिये बोझा मैंने अपने सिर पर रख लिया है। उसने कहा कि चाहे इस बोझे को आप अपने सिर पर रख लो या घोडे की पीठ पर रख लो, वजन तो घोडे पर ही पडेगा। उसी तरह से हमारे मंत्री महोदय ने किया है। मंत्री महोदय को पता है कि हमारे प्रदे ा में 80 प्रति ात पापुले ान देहातों में रहती है। इन्होंने कहा कि इस टैक्स का बोझ देहातियों पर नहीं पडेगा। अगर देहात के लोग सामान खरीदने के लिये भाहर में आते है तो दुकानदार टैक्स उन से ही लेगा। दुकानदार लोग सेल्ज टैक्स खुद नहीं देते बल्कि इन डायरैक्टली वह जमीदारों पर ही पडता है या दूसरे कंज्यूमर्ज पर पडता है। चेयरमैन साहब, आप भी जानते है

और मंत्री जी भी जानते है कि टैक्स में कितनी चोरी होती है। दिल्ली के नजदीक के जो भाहर है जैसे रोहतक, बहादुरगढ, फरीदाबाद और पानीपत तथा करनाल वगैरह है। यहां से रोजाना तीन चार हजार लोग दो दो, चार चार हजार रू0 का सामान खरीदने के लिये दिल्ली जाते है और वे डेली पेसैंजर है। वे वहां पर कम टैक्स देते है और इधर आकर महसूल और दूसरे टैक्स नहीं देते है। उस माल को वे मुनाफे पर दूसरे दुकानदारों को बेच देते है। जिस दुकानदार को माल बेचा जाएगा वह भी उस सामान पर 7–8 प्रति ात टैक्स चार्ज करेगा और उससे अपनी ब्लैक की आदमनी बढाएगा। चेयरमैन साहब, 11.00 बजे यदि सरकार को बजट का घाटा पूरा करना है तो सबसे पहले इस सरकार के मिनिस्टर्ज को अपने खर्चे कम करने होंगे। जो मिनिस्टर्ज साहब दौरे पर जाते है उनको अपना 3 या 4 दिन का इक्टठा दौरा नहीं रखते। जैसे एक मिनिस्टिर आज सोनीपत के दौरे पर जाता है तो वह भााम को वापिस चंडीगढ आ जाता है अगले दिन वहीं मिनिस्टर रोहतक के दौरे पर जाता है और भााम को फिर चंडीगढ वापिस आ जाता है। इसी तरह से वही मिनिस्टर अगले दिन हांसी के दौरे पर जाता है और भााम को वापिस चंडीगढ आ जाता है इस तरह से दौरे पर जाने से बहुत खर्चा होता है। यदि मिनिस्टर साहब तीन दिन का इक्टठा ही दौरा रख करके सोनीपत, रोहतक और हांसी जाएं तो इससे सरकारी खर्चे में काफी बचत होगी। फिर ये दूसरों को कहते है कि खर्चा कम करके घाटे को पूरा करें। चेयरमैन साहब, मंहगाई के कारण गरीब आदमियों की कमर

टूट रही है। इस बजट में करोडों रूपए का घाटा खुला छोड दिया गया है जिसको पूरा करने के लिए यह सरकार दो या तीन महीने के बाद जनता पर कर लगाएगी।

वित्तमंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि आनरेबल मैम्बर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे है जिनका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आनरेबल मैम्बर कौन सी डिमांड पर बोल रहे है।

श्री मंगल सैन: मैम्बर साहब, जनरल एडमिनिस्ट्रे ान की डिमांड पर बोल रहे हैं। (ाोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: जनरल एडमिनिस्ट्रे ान की डिमांड में सेल्ज टैक्स बढाने के बारे में कोई बात नहीं है।

Shri Mangal Sein: He is quite relevant. There is nothing wrong in what he is saying.

श्री फतेह चन्द विज: चेयरमैन साहब, यदि स्टेट का रैवेन्यू कम हो गया तो इससे स्टेट के बिजनैस को धक्का पहुंचेगा और बाद में यह सरकार अपनी गलती को महसूस करेगी। काफी ऐसे लोग है जो हर चीज दिल्ली से माल लाकर हरियाणा में दिल्ली के आस पास सप्लाई करते हैं वे लोग सेल्ज टैक्स नहीं देते और न ही उस माल की कोई चुंगी वगैरह देते हैं। रैवेन्यू कम होने से यदि स्टेट का बिजनैस तबाह हो गया तो यह सरकार बाद

में अपनी गलती को महसूस करेगी। इस बारे में एक भोयर अर्ज करना चाहता हूं–

मुसाफिर जब कोई जंगल में भटक कर मर गया।

फिर सदांए देता हुआ कोई कारवां आया तो क्या।

चेयरमैन साहब, आज से तीन साल पहले जब चौधरी सतबीर सिंह मलिक फाइनैंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने वूलन यार्न पर टैक्स का झगडा डाला था जिसके कारण पानीपत का सारा वूलन यार्न का बिजनैस राजस्थान में ट्रांसफर हो गया। चेयरमैन साहब, सारे हिन्दुस्तान में यह बात मानी गयी है कि जो वूलन के कम्बल डिफैंस को सप्लाई होते है उनका 75 परसैन्ट पानीपत के वूलन कारखानों से सप्लाई किया जाता है। (घंटी) चेयरमैन साहब, मुझे आज ही बोलने का मौका मिला है। आप मुझे दो मिनट का टाईम और दे दें। चेयरमैन साहब, हरियाणा में वूलन पर टैक्स लगने के कारण सारे वूलन के कारखाने राजस्थान में लग गए है।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। हुडडा ने पानीपत में हाउसिंग कालोनी बनाने के लिए आज से 6 साल पहले जमीन एक्वायर की थी लेकिन आज तक वहां पर कालोनी नहीं बनाई गई है। उनको जब भी उस कालोनी को बनाने के लिए कहा जाता है तो कह देते है कि बहुत जल्दी बना देंगे। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह तो वही बात

हो गई जैसे एक आदमी की बीवी ने कहा कि मैंने आज कोई सब्जी नहीं बनाई मैं सिर्फ रोटियां बना लेती हूं आप बाजार से भल्ले पकोडै ले आओ उनके साथ हम रोटी खा लेंगे। वह आदमी बाजार से भल्ले पकोडै लेकर आ रहा था तो उस आदमी को रास्ते में सरदार लछमन सिंह जैसे दो–तीन आदमी मिल गए उन्होंने उस आदमी से पूछा कि आप कहां जा रहे है तो उसने कहा कि मैं बाजार से भल्ले पकोडै लेकर आया हूं और अपने घर जा कर इनके साथ हम रोटी खाएंगे लेकिन उन्होंने कहा कि बैठ यार, ले सुलफे का सूटा ला ले। उसके बाद घर चले जाना। वह आदमी सुलफा पी कर वहीं पर सो गया। जब सुबह हुई तो याद आया कि मैं तो बाजार से भल्ले पकोडै लेने आया था फिर वह आदमी भल्ले पकोडों की कटोरी लेकर जल्दी जल्दी चल पडा और सोचा कि बहुत देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तो मकान के दरवाजे पर ठोकर खाकर मुंह के बल गिर गया। भल्ले पकोडों का कटोरा एक तरफ जा गिरा और खुद दूसरी तरफ जा गिरा। उस वक्त वह आदमी कहने लगा कि मुझे औरत को जल्दी ने मारा है। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि 6 साल का अर्सा हो गया है पानीपत में हाउसिंग कालोनी नहीं बनाई गई है और जब हम इस बारे में हुडडा से कहते है तो वह कह देते है कि बहुत जल्दी बना देंगे। हुडडा के साथ कहीं वह बात तो नहीं हो रही है जैसे उस आदमी ने कहा था कि मुझे औरत की जल्दी ने मारा है। इन

भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी नर सिंह (पाई): चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले डिमांड नम्बर दो के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं यह डिमांड जनरल एडमिनिस्ट्रे ान के बारे में है। इस डिमांड के जरिए यह सरकार करोडों रूपए की हाउस से मंजूरी मांग रही है। चेयरमैन साहब, देहातों या भाहरों में जहां कही भी सरकारी आफिसर्ज है उनको यह सरकार एक जगह पर 6 महीने भी नहीं टिकने देती है। पोलिटिक्ल प्रै ार की वजह से सरकारी प्रै ार की वजह से आईएएस और एचसीएस आफिसर्ज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन आफिसर्ज से जिस इलाके में वे लगे होते हैं वहां पर विकास के कार्य करवाने होते हैं लेकिन उनको यह सरकार 6 महीने भी नहीं टिकने देती है उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, यदि कोई छोटा किसान सरकारी आफिसर्ज के पास अपनी किसी चीज का लाईसैंस बनवाने के लिए जाता है तो उसको एक हजार रूपए की स्माल सेविंग के लिए कह दिया जाता है यदि किसी गरीब आदमी के पास स्माल सेविंग जमा करवाने के लिए एक हजार रूपया नहीं होगा तो वह कैसे जमा करवा सकता है। उसको लाईसैंस बनवाने के लिए 6–6 महीने तक दफतरों के चक्कर काटने पडते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रे ान का बहुत बुरा हाल है और इससे किसी भी आदमी को कोई राहत नहीं मिल पाती है। चेयरमैन

साहब, इसी तरह से होम डिपार्टमैंट है जिसके अंडर पुलिस डिपार्टमैंट आता है। पुलिस डिपार्टमैंट का यह हाल है कि वह बिल्कुल सरकार का भाग बना चुकी है। पुलिसवालों को मंत्री और रूलिंग पार्टी के एमएलए जो बात कहते हैं वही मनासिब समझते है। पुलिस के सामने न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। चेयरमैन साहब, थाने के अन्दर जो एसएचओ होता है उसके पास यदि कोई 107151 का केस आ जाता है तो वह 500 रूपए बोली लगाता है यदि एक पार्टी उसकी 500 रूपए देने के लिए कह देती है और दूसरी 700 रूपए की बोली देने के लिए कह देती है तो वह पहले वाली पार्टी को पकड कर बंद कर देता हैं और 700 रूपए देने वाली पार्टी को छोड देता है चाहे उस पार्टी का कसूर की क्यों न हो। थानों के अन्दर एसएचओ रि वत ले रहे है और सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। चेयरमैन साहब, मैं सदर थाना कैथल का जिकर करना चाहूंगा। उस थाने में एक जीत सिंह नाम का एसएचओ लगा हुआ है। (ाोर एवं विघ्न)।

श्री सभापतिः किसी पर्टीकुलर आदमी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

चौधरी नर सिहः चेयरमैन साहब, सदर थाना कैथल की पुलिस तिलोंवाली गांव गई और उसने वहां पर एक भाराब की भटटी पकडी लेकिन जिस समय भाराब की भटटी पकडी उस समय वहां के लोगों ने पुलिस के दो हवालदारों की बाजू तोड दी। गांव वालों के खिलाफ 325 और 307 का मुकदमा दायर किया गया।

लेकिन पुलिस आज तक उनको पकडने में नाकामयाब रही है। इसका कारण यह है कि वहां का जो एसएचओ है वह उन्हें पकडना नहीं चाहता। एसएचओ पर सरकार का दबाव है कि उनको पकडना नहीं है। सरकार के दबाव के कारण ही उनको पकड कर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। इस केस को हुए 3 महीने का समय हो चुका है लेकिन जिन लोगों ने पुलिस के कर्मचारियों की बाजू तोडी थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ******। (ाोर)

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): चेयरमैन साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि मैम्बर साहेबान किसी पर पर्सनल एलीगे ान न लगायें। इन्होंने जो पर्सनल एलीगे ान लगाया है उसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाना चाहिए। (ाोर)

श्री सभापतिः जो पर्सनल एलीगे ान लगाया गया है उसको एक्सपंज कर दिया जाये।

चौधरी नर सिंहः सभापति जी यदि कोई आम व्यक्ति या विधान सभा का मैम्बर भी एसएचओ के पास जाता है तो वह ठीक व्यवहार नहीं करता। एसएचओ को यह नहीं पता होता कि विधायक से किस तरह से बात करनी चाहिए। जब वह इलाके के विधायक के साथ ही ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर सकता तो

आप इस बात का अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगा।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं0 9 के बारे में बोलना चाहता हूं। यह डिमांड एजुके ान से संबंधित है आज देहात के अन्दर बच्चों को बैठने के लिए टाट तक नहीं मिल पा रहा और न ही देहात में स्कूलों के अन्दर स्टाफ पूरा है। जबकि इसके विपरित भाहरों के स्कूलों को सारी सुविधाएं प्रदान की गई है। देहात के अन्दर जो 80 परसैंट बच्चे पढते है उनमें से 2 परसैंट बच्चे भी आईएएस या एचसीएस अफसर नहीं बन पाते। इसका सबसे बडा कारण यही है कि देहात के अन्दर एजुके ान का प्रबन्ध ठीक नहीं है और न ही इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। वहां पर जो टीचर लगे हुए है उनको भी कांग्रेसी विधायकों के यानि पोलिटिकल प्रै ारों के कारण बदलते रहते हैं। टीचरों के बार बार बदले जाने से भी बच्चों पर बहुत बुरा असर पडता है और ऐसे ट्रांसफरों से अच्छा पढाने वाला एक अध्यापक भी ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पाता। आज हरियाणा के अन्दर प्रत्येक हारा हुआ कांग्रेस का विधायक चुने हुए विधायकों से भी उपर है। सरकार अपनी पार्टी के मैम्बरों के सिवाये किसी दूसरे का काम नहीं करना चाहती यहां पर प्रजातंत्र की दुहाई दी जाती है लेकिन कांग्रेसी विधायक में ही प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज पोलिटिकल प्रै ार से कोई भी आदमी बच नहीं पाया है। एजुके ान का यदि यही हाल रहा तेा नौबत यहां तक आ जायेगी कि बच्चे स्कूलों में

जाना बंद कर देंगे। आज सरकार एक वर्ग वि ोश और वि ोश जाति का ही ध्यान करती है। हरियाणा के अन्दर जो यूनिवर्सिटीयां यास कालेजिज है उनके जो रूल है उनमें लिखा हुआ है कि पांच या दस परसेन्ट कैन्डीडेटस जो हरियाणा से बाहर के होगें रखा जा सकता है जबकि इसके विपरित हरियाणा में होता यह है कि यहां पर 80 प्रति ात व्यक्ति ऐसे रखे जाते है जो हरियाणा से बाहर के है। एजुके ान के अन्दर जो भर्ती की गई है उसमें हरियाणा के मास्टरों को छोड दिया गया है और बाहर के मास्टरों को लगा लिया गया है। इससे जो मास्टर की डिग्री लिए हुए है उन्हें काफी ठेस पहुंची है। मेरा सरकार को सुझाव है कि इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नं0 10 पर जो मैडिकल से संबंधित है बोलना चाहता हूं कैथल के अन्दर एक डाक्टर था। उसका अब वहां से ट्रांसफर हो गया है और उसे अब एसएमओ लगाया गया है। उसकी यह हालत थी कि जब वह अस्पताल में बैठता था तो लोगों की जेबों की तरफ देखा करता था। वह डाक्टर जिसने किसी की जान बचानी होती हैं जान बचाने की बजायें जान लेने की को ि ा ा करता था।

चेयरमैन साहब, मेरे हलके पाई के अन्दर पानी की भारी समस्या है क्योंकि वहां पर पानी अधिकतर खारा है। मेरे हलके के अन्दर 36737 गांव हैं। इनमें से मु ि कल से 3–4 गांवों के अन्दर पानी की सुविधा सरकार की तरफ से प्रदान की हुई है जबकि

इसके विपरित आदमपुर हल्के के अन्दर 30–35 गांवों में से मुि कल से 3–4 गांव ही ऐसे रहते होगें जहां पर सरकार की तरफ से पानी की सुविधा न दी गई होगी। मेरे हलके के दो गांव ऐसे है जिनका पानी बिल्कुल ही खारा है सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार कहती है कि हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक के साथ न्याय नही कर रही।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं 20 पर बोलना चाहता हूं। सरकार 20 सुत्री कार्यक्रम का नारा लगाकर बडे बडे पोस्टर लगवाती है और उसमें इंदिरा गांधी के गुण गाये जाते हैं। यदि इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई किसान अपनी जमीन में सफेदे लगा लेता है तो सरकार उसको भी नहीं छोडती। मेरे हलके के अन्दर रेहडा नाम का एक गांव है। वहां के धर्मसिंह नाम के एक किसान ने साढे सात एकड जमीन के अन्दर सफेदे लगाये। हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और हैं। यही हाल सरकार का है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इस किसान ने साढे सात एकड जमीन में सफेदे लगाये लेकिन जब इनको लगाये हुए तीन साल हो गये तो बिजली बोर्ड की तरफ से उस किसान के नाम 4200 रू0 का बिल भेज दिया गया। जब पूछा गया कि यह बिल क्यों भेजा गया है तो पता लगा कि वहां की लाईन बदलनी है। सरकार पब्लिक इन्ट्रैस्ट में कुछ भी काम नहीं करना चाहती। सरकार ने वनों को बढावा देने के नाम से 35 करोड रू0

का एक बोर्ड तो जरूर बना दिया लेकिन जो किसान अपनी तरफ से वृक्ष लगाने की कोि ा ा करता है उसको परे ाान किया जाता है। इस बोर्ड को बनाकर एक प्रकार से घपला किया जा रहा है। रैवेन्यू मिनिस्टर साहब, यहां पर बैठे हुए है। वे बडे समझदार है। वे इस काम को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इनको नया बोर्ड बनाने की कोई आव यकता नहीं थी। आज सरकार की तरफ से किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं की जा रही। जिस प्रंकार से सरकार ने उस किसान को जिसने साढे सात एकड जमीन में सफेदे लगाये थे तो अपनी फसल बढाना चाहते है। छोड दें। आजकल यह कहा जा रहा है कि सरकार गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन करवाना चाहती है। यदि किसान लोग अपनी मेहनत से गन्ना अधिक पैदा करेंगे तो उनका भी यही हाल होगा जो एक किसान के साथ हुआ है। सरकार को इस तरह से किसानों को परे ाान नहीं करना चाहिए।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नं0 25 के बारे में बोलना चाहता हूं। सरकार ने एक वीकर सैक ान कार्पोरे ान खोली है। कांग्रेस सरका अग्रेंजों की पालिसी पर चलती है। जो पालिसी अंग्रेज बनाया करते थे। उसी तरह की पालिसी आज की सरकार अपना रही है। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी मजदूर, किसान या मेहनतक ा आज की सरकार से खु ा नहीं है। सरकार ने वीकर सैक ान के लिए 25 परसैन्ट पैसे आपी तरफ से रखे हैं और बाकी 75 परसैन्ट पैसा बैंको के जरिये देने के लिए

कहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को सुझाव है कि जो भी पैसा सरकार इन लोगों को दे वह बैकों के जरिए न दे। क्योंकि आज कल बैंकों के अन्दर काफी नाजायज धांधलियां मची हुई है। बैंक का जो मैनेजर है वह जो लोग पैसा लेने जायेंगे उनको परे ाान करेगा। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को सुझाव है कि जो भी पैसा सरकार वीकर सैक ान को दे वह खुद दें, बैंकों के जरिए किसी को पेमेंट न दी जायें, बैंकों के चक्कर जो बार बार काटे जायेंगे। उस कोई भी व्यक्ति सहन नही कर पायेगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापतिः श्री भले राम

वाक आउट

श्री हीरा नन्द आर्यः आप हमें बोलने का मौका दें। हमारी तरफ से कोई भी नहीं बोला है।

श्री सभापतिः इनके बोलने के बाद आपको भी मौका दिया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः चेयरमैन साहब, अब हमें बोलने का टाईम दिया जाये। मेरे बाद श्री भले राम जी बोल लेंगे। (व्यवधान) हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है।

श्री सभापतिः ट्रैजरी बैचिज की तरफ से आज कोई नहीं बोला है। भले राम जी के बाद आपोजी ान साईड से बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः चेयरमैन साहब, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए ऐज ए प्रोटैस्ट मैं वाक आउट करता हूं। (व्यवधान)

(इस समय श्री हीरा नन्द आर्य सदन से वाक आउट कर गए)

वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री भले राम (बडौदा अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं मांग नं0 8 और 13 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमति चन्द्रावतीः आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, हमारी पार्टी के बहुत कम मैम्बर बोले है और आज डिस्क ान भ्ाुरू ही हमारे मैम्बरों की तरफ से होनी चाहिए थी। जितना टाईम हमें मिलना है उस हिसाब से हमारे बहुत कम आदमी बोले हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी वाले सदस्य न तो बोलना चाहते हैं और न ही इनका टाईम बकाया है ये बहुत बोल चुके है अब हमें टाईम मिलना चाहिए।

श्री सभापतिः श्री भले राम जी के बाद आपके मैम्बरों को बुलायेंगे। आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

चौधरी कुलबीर सिह मलिकः चेयरमैन साहब, पहले आप इस बात का फैसला कर लें कि बोलने वाले सदस्यों को कितना कितना टाईम देना है। (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापतिः स्पीकर साहब ने पहले ही कह दिया है 10—10 मिनट देंगें।

श्री भले रामः चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट की डिमांड पर बोलूगां। सरकार वीकर सैक ान के लोगों को उपर उठाना चाहती है इसीलिए सरकार डिमांड नं 13 के तहत 56756096 रू0 खर्च करने के लिए मंजूरी मांग रही है। आप सब जानते हैं कि सरकार खास कर कमजोर वर्गो को जो आर्थिक रूप से और भौक्षणिक दृशिट से पिछडे हुए है उंचा उठाना चाहती है। इस औब्जैक्टिव को अचीव करने के लिए जितने महकमें हरियाणा में हैं उनको जो पैसा बजट में दिया गया है उसका साढे 12 परसैंट पैसा ि ाडल्यूड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज पर खर्च होगा जो कुल मिलाकर 28 करोड रू0 बनता है। यह रा ि ा पिछले साल से 4 करोड रूपया ज्यादा है। जितने हमारे हरिजन भाई है उन सबको पता है कि सरकार बच्चों को वजीफे ही नहीं देती बलिक फीस भी मुआफ करती है। इसके अलावा अगर कोई हरिजन बच्चा स्कूल में या कालेज में

मैथेमैटिक्स और साईंस में कमजोर है तो उनको सरकार की तरफ से स्पै ाल कोचिंग दी जाती है। यहीं नहीं फ्री किताबें भी दी जाती है। चेयरमैन साहब, आपको जानकर खु ाी होगी कि पहले नौंवी और दसवी क्लास के बच्चों को 16 रूपये वजीफा दिया जाता था लेकिन अब सरकार ने बडी फ्राखदिली से काम लिया और आने वाले इस बजट में इस रा ि ा को 16 रूपये से बढाकर 30 रूपया कर दिा है। इसके साथ ही वजीफा लेने के लिये लिमिट पहले 6000 रूपये थी लेकिन अब सरकार ने स लिमिट को बढाकर 10 हजार रूपये कर दिया। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो सरकार हरिजनों के लिए और वीकर सैक् ानज के लिए कर रही है। सरकार ि ाक्षा की दृश्टि से आर्थिक दृश्टि से तरह तरह की स्कीमें बनाकर वीकर सैक् ानज को उंचा उठाना चाहती है जिसके लिए इन्ट्रैस्ट फ्री लोन देती है इसके अलावा मकान बनाने के लिए दो हजार रूपया देती है। भेड बकरियां पालने के लिए भी लोन देती है जिनसमें हरिजनों का उत्थान हो रहा है। चेयरमैन साहब, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की पालिसी है कि 100 ट्रक परमिट हरिजनों को दिए जाएं लेकिन इस पालिसी को इम्पलीमैंट करने में भी कुछ दिक्कतें आती है। हरिजन को ट्रक खरीदने के लिए 75 परसैन्ट रूपया बैंक देता है और 25 परसैन्ट पैसा जो एक मार्जिनल अमाउन्ट है उसको देने का इन्तजाम सरकार ने किया है। 75 परसैंट जो बैंक लोन देगा इसकी गारन्टी हरिजन कल्याण निगम देगा और 25 परसैंट पैसा सरकार देगी। इस तरह से हरिजन को

अपनी जेब से कुछ नहीं देना पडता। लेकिन इसकी इम्पलीमैंटे ान में भी कुछ दिक्कत है। हम दिक्कत को दूर करने के लिए मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा। परमिट देते समय एक दिक्कत आती है और वह यह कि ट्रक का नम्बर पहले देना पडता है। क्योंकि हरिजन ट्रक पहले ले नहीं सकता इसलिए दिखायेगा क्या? इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले लाइसैंस दिया जाए, ट्रक बाद में लेता रहेगा। इस स्कीम दोबारा एडवरटाइज की जाएं ताकि लोगों को परमिट और लाईसैंस इ ाू किये जा सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह सुझाव सरकार जरूर मानेगी और एप्लीके ान्ज दोबारा इन्वाईट करेगी।

चेयरमैन साहब, आपको पता है हरिजन कल्याण निगम की कुल पूंजी 5 करोड रूपये की है और इस पूंजी से निगम ने तकरीबन 18 हजार लोगों को फायदा पहुंचाया है। मेरा सरकार को सुझाव है कि इस पूंजी को बढाकर 10 करोड कर दिया जाए ताकि कर्जा लेने वाले गरीब हरिजनों को ज्यादा कर्जा मिल सके। अब तो आबादी भी बहुत बढ गई है। 5 करोड से बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचता है इसलिए मेरा सुझाव है कि इस रा ि ा को 10 करोड तक बढाया जाए। चेयरमैन साहब, इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज निगम है। इसके पास 2 करोड की पूंजी थी इसको बढाकर 4 करोड किया गया है लेकिन यह भी कम है इसको और बढाया जाए। इन सब कारनामें को देखते हुए मैं कहूंगा कि सरकार ने गरीबों को उंचा उठाने का इरादा किया हुआ है।

इसलिए मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस सो ाल वैल्फेयर की डिमांड को पास किया जाए। चेयरमैन साहब, एक प्वायंट रह गया है जिसके बारे में हाउस को बताना चाहता हूं कि सरकार ने भेदभाव को कास्टीजम को खत्म करने का फैसला किया है और एलान किया है कि जो व्यक्ति हरिजन लडका या लडकी से इन्टर कास्ट मैरिज करेगा उसको दो हजार रूपया दिया जाएगा। यह बहुत अच्छा कदम है इससे कांस्टीजम खत्म करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा मैं रोडज के बारे में थोडा सा अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, हरियाणा प्रदे ा एक ऐसा प्रदे ा है जिसके हर एक गांव को सडकों के साथ जोडा गया है लेकिन कुछ गांव ऐसे है जो डायरैक्टरी विलेजिज में तो नहीं आते जिनकी आबादी 250 के करीब बैठती है। लेकिन फिर भी सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे गांवों में भी सडके बनाई जायेगीी। इसमें खास बात यह है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जितनी हरिजन बस्तियां है उन सब को सडकों के साथ जोडा जाएगा लेकिन इस के बारे में मेरा एक सुझाव है उम्मीद है सरकार इसको मानेगी। बहुत सी हरिजन बस्तियां ऐसी है जो एक जगह पर नहीं होती गांव के चारों और फैली होती है। इन बस्तियां को भी सडकों से जोडा जाए क्येांकि कुछ बस्तियां ऐसी है जिनको सडकों के साथ जोडना निहायत जरूरी है। बहुत सी सडके ऐसी है जो दो डिस्ट्रिक्टस भी आपस में जोडती हैं बहुत

कम डिस्टैंस रहता है अगर इस डिस्टैंस को कवर करके सडक से जोडा जाए तो हरिजन बस्तियों को भी फायदा होगा और दोनों डिस्ट्रिक्टस भी आपस में जुड जायेंगे। एक सडक जागसी और सरफाबाद है। इन दोनों गांवों में बहुत कम डिस्टैंस है और ये दोनों गांव बनी है। इसी तरह से रानाखेडी अैज्ञर बाघडू सडक है। रानाखेडी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पडता है और बाघडू डिस्ट्रिक्ट जींद में पडता है। यहां पर परचेज सैन्टर भी है। इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि इस सडक को मार्किटिंग बोर्ड बनायेगा। इसी तरह से स्वानामाल से बाहरखेज की सडक बनाई जाए। स्वानामाल डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से पडता है और बाहरखेज डिस्ट्रिक्ट जींद में पडता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सडकों को बनाया जाए ताकि दो डिस्ट्रिक्टस को आपस में मिलाया जाए।

चेयरमैन साहब, कई आनरेबल मैम्बर्ज ने ला एंड आर्डर का जिकर किया है। हरियाणा में दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप सब जानते है कि हरियाणा की पुलिस ने कितनी बहादुरी के साथ काम किया यह बात पुलिस की रिपोर्ट जो सदन में पे ा हे से पता चलती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि इस रिपोर्ट में क्राईम्ज कुछ बढ़े हुए दिखाये गये हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि पुलिस हर केस को दर्ज करती है, इसी लिए क्राईम्ज के केसिज की संख्या हमें ज्यादा दिखती है। आपको पता हैं, एशियाड के खेलों में हरियाणा

को इज्जत का सवाल था और पुलिस ने अच्छा काम करके सारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है और यही कारण हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट हरियाणा की पुलिस को डिमांड करती है। अपोजीशन के भाई बेकार ही इतराज करते हैं, इसलिए अन्त में मेरी यह प्रार्थना है कि इन डिमांडज को पास किया जाए।

श्री मनफूल सिंह (असन्ध, अनुसूचित–जाति): चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पहली बार हाउस में बोलने का समय दिया मुझे आज तक बोलने का मौका ही नहीं मिला था। आज हाउस के सामने डिमांडज पेश हैं। मैं सब से पहले जो डिमांड हरिजनों के बारे में जैं, उस पर बोलना चाहता हूं। यहां हाउस में कहा जाता है कि हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं, हरिजनों को जिन्दा जलाया जाता है लेकिन इस बात के बारे में कहूंगा कि हमारे साथी एम.एल.ए. खुद जलवाते हैं। चौ. भलेराम जी 23 हजार वोटों से जीत कर आये थे लेकिन आज अपोजीशन को छोड़कर उधर रूलिंग पार्टी में बैठे है। आज फिर यह हरिजनों के बारे में बात करें तो इनकी कौन बात सुनेगा। आया राम गया राम वाली बात तो इन लोगों ने खुद शुरू की है फिर इन लोगों पर जुल्म न होंगे तो किन लोगों के साथ होंगे? मास्टर राम सिंह जी का और मेरा कमरा एम.एल.ए. होस्टल में साथ ही साथ है। 26 नवम्बर और 28 नवम्बर हमें अलाट हुआ है। चेयरमैन साहब भजन लाल जी ने अनपढ़ आदमियों को चेयरमैन बना दिया परन्तु मास्टर राम सिंह

जी जो कि पढ़े–लिखे भी हैं ओर मास्टर जी भी रहे हैं उनको कुछ भी नहीं बनाया। वे बड़े दु:खी और परेशान से रहते हैं। वे कहते हैं कि मास्टर होते हुए भी मुझे चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है। तो यह अन्याय नहीं है तो और क्या है? हरिजनों के साथ विधान सभा में भी अन्याय किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, महाशय बनारसीं दास, दिलू राम और गिरि राज किशोर आदि को भी चेयरमैन लगा दिया गया है। उधर चौ. अमर सिंह जी को चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी लगा दिया गया है। अब चौ. अमर सिंह जी हरिजनों का नाम ही लेना भूल गये है। पहले हरिजनों की बड़ी चर्चा किया करते थे लेकिन अब उनका नाम लेना ही भूल गए हैं। अब वे नीची गर्दन किये बैठे रहते हैं।

चेयरमैन साहब, यह बात दरूस्त है कि देश आजाद है लेकिन आजाद होते हुए भी बाल्मीकी गुलाम हैं क्योंकि एक स्वीपर ऐसा है जिसे दो नौकरियों करनी पड़ती है। वह रात को भी डियूटी देता है और दिन को भी देता है। कफद लोग उसमे बैकवर्ड जाति के भी आ जाते हैं जैसे कई दफतरों में पोस्ट होती है स्वीपर–कम–चौकीदार की दिन में दफतर की सफाई करता है और रात को दफतर की चौकीदारी करता है। उस बेचारे से दो नौकरियां करवायी जाती है लेकिन तन्खाह उतनी ही देते हैं जितनी एक को दी जाती है। उन बेचारों को तन्खाह भी लेट मिलती हैं। इस तरह की नौकरियों पर अदर कास्टस के लोग भी लगे हुए हैं जैसे माली–कम–चौकीदार। उनसे भी दो प्रकार की

डियूटियां ली जाती हैं। उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें एक ही डियूटी देनी पड़े। इन्दिरा जी की सभी तारीु करते हैं कि उसने बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया है। चेयरमैन साहब, सूत्र तो तीन ही हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये 17 सूत्र तो कांग्रेस वालों पर ही लागू होते हैं। चेयरमैन सहाब, सहकारिता विभाग द्वारा हर कम्चूनिटी को लोन दिया जाता है हरिजनों को भी दिया जाता है और दूसरों को भी दिया जाता है। जिन लोगों को लोन दिया जाता है चाहे वह भैंसों के लिए दिया जाए या गाए पालने के लिए दिया जाए, उसका दूध खरीदा जाता है लेकिन गडरियों, धानकों या जो भी लोग रेबड़ पालते हैं, भेड़–बकरियां पालते हैं उन्हें भी लोन दिया जाता है लेकिन सरकार उनकी ऊन को नहीं खरीदती है। जब लोन देने वाले का सामान खरीदती हे तो भेड़–बकरियों की ऊन को नहीं खरीदती है। जब लोन देने वाले का सामान खरीदती है तो भेड़–बकरियों की ऊ को क्यों नहीं खरीदती। उन लोगों से व्यापारी या दूसरे लोग ठेकेदार बन जाते हैं। वे लोग उनसे ऊन खरीदते हैं जो कि बहुत सस्ते भाव पर खरीदते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को उनकी ऊन खरीदने का भी प्रबन्ध करना चाहिए।

चेयरमैन साहब, मैंने फतेहाबाद के बारे में एक काल–अटैन्शन मोशन भी दिया था लेकिन वह रिजैक्ट कर दिया गया है। वह इसलिए रिजैक्ट कर दिया गया कि वह हरिजनों से सम्बन्धित था। फतेहाबाद के 19 हरिजनों को अरैस्ट किया गया

उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया। हरिजनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही हमारे हरिजन एम.एल.एज. साथियों को किसी पकार की शर्म आती है। वे तो अपनी कुर्सी पक्की करना चाहते हैं उनकी कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि चौ. भले राम जी भी मिनिस्टरी में आयें कयोंकि अमर सिंह जी आ सकते हैं तो भले राम जी उनसे कम क्वालिफाईड नहीं हैं। वे भी हरिजन हैं इसलिए उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।

चेयरमैन साहब अब मैं थोड़ा–बहुत हैलि डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। पानीपत तहसील बहुत ही पुरानी तहसील है। पानीपत में तो बहुत बड़ी–बड़ी लड़ाइयां हुई है लेकिन हमारे मंत्री जी पानीपत के विशय में कोई ख्याल नहीं रखते हैं। मैंने उनसे कई दफा इस बारे में दरखास्त की है लेकिन वे कोई ध्यान नहीं देते। वे केवल अपनी हैल्थ का ख्याल रखते हैं। आम पब्लिक का कोई ख्याल नहीं करते। पानीपत के हस्पताल में एक बैड के नीचे दस हजार मच्छर 24 घंटे मिलेंगे। इसलिए सरकार को उस तरफ ध्यान देकर मच्छरों को मरवाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

इसी तरह से हरियाणा के अन्दर दवाइयों की फैक्टरियां 250 और 300 के करीब हैं। जिनमें नकली दवाइयां भी बनती हैं। सारी फैक्टरीज के ऊपर एक ही आदमी ड्रग कन्ट्रोलर इन्चार्ज लगा है जो चैकिंग करता है यानी सैम्पल वगैरह लेता है। उस व्यक्ति का नाम ओ.पी. अग्रवाल है। आप अन्दाला लगायें कि सारी

फैक्टरीज की एक आदमी किस प्रकार से चैंकिग और कट्रोल कर सकात है चैकिंग की पावर ड्रग इन्सपैक्टर को मिलनी चाहिए। वे ड्रग इन्सपैक्टर्ज को पावर इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि सारा माल अकेले की खाना चाहते हैं। कुंडली में एक दवाइयों की फैक्टरी थी। वह नाजायज जाली इवाईयां बना कर बेचा करती थी। गवर्नमैंट ने उस फैक्अरी को बन्द करवा दिया लेकिन उसी फैक्टरी को दूसरे व्यक्ति के नाम से लाइसैंस दे दिया गया और आज के दिन वे फैक्टरी चल रही है। इसी प्रकार से गुड़गावां के अन्दर एक गलूकोस की फैक्टरी थी। आप को याद होगा कि कानपुर मे उसके गलूकोस के इस्तेमाल से 78 आदमी मारे भी गये थे लेकिन अब वह फैक्टरी फिर चालू हो गई है। दूसरे व्यक्ति के नाम से लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया है। इसलिए आपके जरिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जितनी फैक्टरीज हैं उनकी इन्सपैक्शन या चैकिंग डिस्ट्रिक्ट का ड्रग इन्सपैक्टर करे। ओ.पी. अग्रवाल से यह चार्ज लिया जाना चाहिए। साल में 365 दिन होते हैं और वरकिंग डे 180 के करीब होते हैं। एक आदमी अकेला ही 180 दिन में 250 फैक्टरीज को कैसे चैक कर सकता है? सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है क्योंकि यह खुद भ्रश्ट है।

चेयरमैन साहब जिस एम.एल.एज. को खरीदा गया है अब वे चेयरमैन लग चुके हैं। चेयरमैन साहब, चौ. लाल सिंह, चन्दा सिंह जी के गांव में बड़े नाचे थे। उस वक्त मेरी जेब में

दस रूपये का नोट था, मैने उन पर वार कर दे दिया था। चौ. लाल सिंह के महकमे को मेरे हल्के के बारे में कोई ख्याल नहीं है। वहां बड़े–बड़े गांव हैं, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी को जब भी कोई बात कही जाती है तो वह टोपी ओढ़ कर चल देते हैं।

चेयरमैन साहब, गगसीना, बला, कवई पाढ़ा, लुहारी आदि गांवों में पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। ये मेरे अपने हल्के के बड़े–बड़े गांव हैं। जब सरकार में कोई मंत्री बने तो उसे दूसरे हल्के के गांवों को ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। (घंटी) चेयरमैन साहब मैं तो पहली बार बोला हूं। कम से कम मुझे आधा घन्टा मिलना चाहिए। मैं तो अच्छी सुजैशन दे रहा हूं। (घंटी)

चेयरमैन साहब, यह गलत बात है, मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूं। शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां स्कूलों का बहुत बुरा होल है क्योंकि स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिगें ज्यादातर गिर चुकी हैं क्योंकि उनके अन्दर मैटीरियल सब–स्टैंडर्ड लगा होता है। इसके अलावा, उनमें पूरी टीचर्ज भी नहीं हैं। जो सरकार ने स्कूल अपग्रेड किये थे, उनमें आज तक भी पूरे टीचर नहीं पहुंचे हैं और सरकार द्वारा उनकी तरफ पूरा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। खैर, शिक्षा मंत्री जी

यहां पर बैठे हुए हैं और वे नोट कर रहे हैं, वे कृप्या इस बारे में देख लें।

इसके अलावा, चेयरमैन साहब, थोड़ी सी बात मैं विधान सभा के बारे में कहना चाहता हूं। जो हमारा एम.एल.एज. होस्टल है, उसके अन्दर काम करने वाले कर्मचारी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करते हैं। लेकिन उनको कोई ओवर–टाईम अलाउन्स नहीं दिया जाता। मेरा कहना यह है कि उनको ओवर–टाईम अलाउन्स देना चाहिये। जब वह बेचारे सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक वहीं खड़े होते हैं और हमारी सबकी सेवा करते हैं, उनको ओवर–टाईम अलाउन्स दिया ही जाना चाहिये। वे थोड़ा बहुत मिनिस्टरों की सेवा भी करते हैं ओर उनके घरों में जाकर भी सारा काम करते हैं। जो भी सामान उनको दिया जाता हैं, वे घरों में जाकर भी सारा काम करते हैं। जो भी सामान उनको दिया जाता है, वे घरों में जाकर देते हैं। इसलिये चेयरमैन साहब, मेरा कहना यह है कि उनको ओवर टाईम अलाउन्स दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भी गरीब आदमी हैं। (घंटी) चेयरमैन साहब, अब मैं बसिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नाम तो डीलक्स रखा हुआ है लेकिन अगर देखा जाये तो उनके अन्दर शीशे नहीं हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और उनमें लाईट और वैल की भी कोई खासत सुविधा नहीं है। इसके अलावा, उसके अन्दर फर्स्ट एड बाकस भी नहीं होता। पिछले दिनों की ही बात बताता हूं। एक आदमी गिर गया। हमने कंडक्टर से

पूछा कि भाई, फर्स्ट एक बाक्स है। तो उसने कहा कि हमें तेा मिलता ही नहीं है। इसलिये चेयरमैन साहब, मेरा कहना यह है कि यह तो कम से कम जरूर दिया जाना चाहिये। जब मैं कुछ सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश मे पहले चौ. बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने सड़कों के मामले में बहुत अच्छा काम किया था। आज जाकर आप कहीं भी देख लें, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोई भी सड़क ठीक नहीं है। मैं अपने हल्के के बारे में ज्यादा बता सकता हूं। एक गांव कुडलाइना है। उसमें सिर्फ 500 मीटर का टुकडा बनना है। वहां पर पानी खड़ा है। कुडलाइना से पाडा सड़क को मिलाने के लिये कई मंत्री महोदय आज तक वहां पर पहुंच लिये और सब यही कह कर आये कि इसको जरूर पक्का करवा दें गे, लेकिन आज तक वह सड़क पक्की नहीं हुई है। उसके बाद पानी का एक पुल है जो रजबाहे को क्रौस करता है। उसके दोनों साइडज पर जबरदस्त खड्डे हैं मैं चीफ मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब आप दोनों को ही वहां आने के लिय इन्वाईट करूंगा कि आप खुद वहां पर आकर देख लें कि वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती। (घंटी) चेयरमैन साहब, आपका बहुत–हुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिये अदा करना पड़ता है क्योंकि एक तो आप लायक आदमी है दूसरे आप मंत्री बनने के लायक हो। इसके अलावा मैं कुछ बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। रोजगार का महकमा हमारे शर्मा साहब के पास है। हमारे शर्मा साहब के पिता तो गवर्नर हैं, ये भी यहां पर गवर्नर होने चाहियें थे, शान तो इसी में होती लेकिन चेयरमैन

साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एम्पलायमैंट का इतना बुरा हाल है कि 5–5, 6–6 साल कार्ड रीन्यू करवाते हुए हो जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार से वैस्ट बंगाल में बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है, मैं यह चाहता हूं कि उस प्रकार से यहां पर भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये (घंटी) चेयरमैन साहब, कार्ड निकलवाने में भी 50 रूपये से लेकर 2000 रूपये तक रिश्वत चलती है (घंटी) (व्यवधान व शोर)।

श्री सभापति: आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठिये।

श्री मनफूल सिंह: चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा मैं इनसे यह कहूंगा कि यह दरखत न कटवाये। (घंटी) अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर ओम प्रकाश।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, अब हमारा बोलने का नम्बर है। आखिर कोई न कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिये मैं आपसे फिर यह रिक्वैस्ट करूंगा कि बाई रोटेशन पार्टीज को काल–अपौन कीजिये। अब हमारा नम्बर आता है। हमारे बाद कांग्रेस (आई) का नम्बर आयेगा। इसलिये पहले हमारी साइड

से यदि किसी मैम्बर को बुलवा लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इनकी तरफ से बाद में बोल सकते है।

श्री सभापतिः श्री ओम प्रकाश जी आप बैठिये, इनकी तरफ से श्री लछमन सिंह कम्बोज बोल लें उसके बाद आप बोल लेना।

डा. ओम प्रकाश शर्माः अच्छा जी, जैसे आपका हुक्म है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज (इन्द्री)ः चेयरमैन साहब, डिमांड न. 8 पर मैं सड़कों के बारे में बोलना चाहता हूं। मेरे इलाके इन्द्री में एक चन्द्रो है। वहां पर पंजाब से आये हुए पाकिस्तानी और दूसरे गरीब हरिजन रहते हैं। करोड़ों रूप्या इस बजट का टैक्स लगाकर इकट्ठा यिका जा रहा है। आज तक भी उस गांव पर कोई पुल नहीं बना है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी यहां पर सरकार बनती है तो वहां के लोग सरकार के पास आकर आना रोना रोते है। जब चौमासा वहां पर लगता है तेा उनके छोटे–छोटे बच्चे उसमें डूब कर मर जाते हैं। लेकिन आज तक सरकार की और से इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उन चन्द्रो पर पुल जरूर जल्दी से जल्दी बनवायें। इसके अलावा, चेयरमैन साहब, फल्डज के लिये काफी बजट रखा गया है। यू.पी. की सरकार ने हरियाणा के साथ

लगते इलाके में, कुछ करूक्षेत्र के इलाके में और कुछ इन्द्री के हल्के में इतेन बड़े–बड़े जमुना नदी पर बांध बनाये हैं कि उससे हमारे हरियाणा के किसानों की कई हजार एकड़ भूमि जमुना में चला गयी है। मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार को भी यू.पी. सरकार की तरह से ठोकरें या कोई पटरियां अपनी तरफ भी बनानी चाहियें ताकि किसानों की जमीन को बचाया जा सके। चेयरमैन साहब, मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज किसान बहुत बुरी तरह से बरबाद हो रहा है। हौस्पिटल्ज की जहां तक इन्द्री हल्के की बात है, करनाल में ही सिर्फ एक हौस्पिटल है। वह वहां से 30–40 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे इलाके में कई हजार जनता बसती है। मेरे यहां पर सिर्फ 10 बैडज का ही हौस्पिटल है। मैं यहां पर हैल्थ मिनिस्टर से यह कहना चाहूंगा कि उसे बढ़ाकर कम से कम 25 बैडज का हौस्पिटल बना दिया जाये क्योंकि अगर वहां पर मरीज 10 की बजाये 20 हो जाते हैं, तो कैवल 10 को ही वहां पर जगह मिल सकती है बाकी के 10 मरीजों को करनाल जाना पड़ता है ओर वह बेचारे रास्ते में ही मर जाते हैं क्योंकि वह काफी दूर पड़ता है। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में आज तक भी कई ऐसे गांव है, जिन्होंने सड़क का मुंह नहीं देखा है। वे कस्बों में 15 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। इन गांवों में भील आदिवासी और मजदूर कम्युनिटी के लोग रहते है। वहां पर आज तक भी पशुओं के लिए कोई अस्पताल नहीं है और नही वहां पर सड़कें हैं। इसलिऐ मैं पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर महोदय

से यह कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके के लोगों के लिए भी सड़क की सुविधा प्रदान करवायी जाये।

चेयरमैन साहब मेरे हल्के इन्द्री में तो पुलिस का बुरा हाल है। वहां पर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ दिया गया है और वहां पर इस्लाम खतरे में है। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में कोई कालिज नहीं है। हमारे यहां के बच्चों को करनाल में कालिज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बीस–तीस किलोमीटर दूर तक हमारे यहां कोई कालिज नहीं हैं। इस लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे यहां कालिज बनाया जाए। मैं ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से खासतौर से कहना चाहता हूं कि इन्द्री के अन्दर कालिज बनाना जाए क्योंकि वह इलाका बैकवर्ड है। अन्त में चेयरमैन साहब, मैंने अपने इलाके के लिए जो भी डिमान्डज रखी हैं, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनको पूरा किया जाए। चेयरमैन सहाब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. ओम प्रकाश शर्मा (जगाधरी): चेयरमैन साहब, सदन में 1983–84 के बजट की डिमाण्डज फार ग्रांटस पर चर्चा चल रही है। मैं डिमांड नम्बर पांच पर अपने विचार रखना चाहता हूं क्योंकि जिस हल्के की मैं नुमाइंदगी इस सदन में करता हूं उसका ताल्लुक डिमांड नम्बर पांच से है। इस डिमांड में लिखा है।

"That an sum not exceeding Rs. 39062365 for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1983&84 in respect of the charges under Demnad No. 5 – Excise and Taxation."

चेयरमैन साहब, गवर्नर को खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान दीं जाए, यह मांग नम्बर पांच के तहत कहा गया है, चेयरमैन सहाब, जहां तक खर्चों को चुकाने वाली बात हैं हर प्रगतिशील मुल्क के अन्दर या प्रान्त के अन्दर खर्चा होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा खर्चा होना जरूीर है। मगर जहां डिमान्डज में 39062365 रूपये की मांग की गई है, वहां पर हमें यह भी देखना है कि जिन लोगों के लिए यह मांग की जा रही है उनकी कारकर्दगी में कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिस से हमारी स्टेट का जो एक्सचैकर है, उस पर बिना वजह बोझा पड़ता हो। चेयरमैन सहाब, सेल्ज टैक्स में एक परसैन्ट और दो परसैन्ट की बढ़ौतरी की गई है। जो लग्जरी गुडज हैं, उन पर दो परसैन्ट की बढ़ौतरी की गई है। चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि इस टैक्स का बोझ जो हमारी आज जनता, उस पर पड़ना है। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के के अन्दर, जो एक इंडस्ट्रियल टाउन है, इस सेल्ज टैक्स को लेकर काफी चर्चा हैं और हमारे विपक्ष के भाई भी, चाहे वे सदन के अन्दर हैं या बाहर हैं, इसकी चर्चा करते रहे हैं। इस बारे में व्यापारी भी काफी विचार व्यक्त करते रहे हैं और अपनी मुश्किलात बयान करते रहे है। भारती जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह व्यापारियों की जमात हैं और यह पार्टी व्यापारी वर्ग की नुमांइन्दगी करती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि

आज डा. मंगल सैन यहां पर नजर नहीं आ रहे है (शोर एवं व्यवधान) पता नहीं वे आज सदन में क्यों गेर हाजिर हैं। उनके एक साथी यहां पर बोल चुके हैं। जब मैं सदन में आ रहा था तो वे बाहर जा रहे थे। जब उनका एक साथी बोल कर समाप्त कर रहा था तो मैं भी खड़ा हो रहा था इसलिए डा. मंगल सैन को पता है कि मैंने बोलना है इसलिए वे अपने साथी के बोलने के बाद उठकर चले गए। अगर वे यहां होते तो मैं उनसे एक–दो बात पूछता।

श्री राम बिलास शर्मा: चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफर आर्डर। ये डिमांड पर नहीं बोल रहे हैं। इनको कहिए कि ये डिमांड के ऊपर बोलें।

श्री सभापति: आनरेबल मैम्बर, डिमांड पर ही बोलें।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: मेरे अजीज ने जो कहा है, चेयरमैन सहाब, उसके मुताबिक ही मैं बोलूंगा क्योंकि आजकल बच्चों का कहना मानना पड़ता है। चेयरमैन सहाब, सेल्ज–टैक्स के अन्दर इवेजन को चैक करने के लिए, टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार ने दो प्रकार के फार्म बनाए हैं। एक फार्म 'डी' जिसको डिक्लेयरेशन फार्म कहा जाता है और दूसरा 'सी' फार्म है। ये दोनों फार्म इन्टर–स्टेट ट्रांजेक्शन के काम में आते हैं जो रजिस्टर्ड डीलर है, उसको महकमे वाले 'डी' फार्म की पचास–पचास की जो कापी होती है, वह देते हैं। चेयरमैन साहब,

इस सेल्ज–टैक्स फार्म की कापी के बारे में कफद कहना चाहता हूं। कितनी ही बार ऐसा हेाता है कि व्यापारी महकमें वालों के पास जाता है और उनसे कापी तलब करता है। डिपार्टमैंट वाले कई बार व्यापारी को कह देते हैं कि फार्म की कापी नहीं है क्योंकि उनका कुछ अपना इंट्रेस्ट होता है, अपना स्वार्थ होता है ओर जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, वे आसानी से डी फार्म की पचास वाली कापी नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि डी फार्म के चार हिस्से होते हैं – ए., बी., सी., और डी.। 'ए' यानी औरिजनल कापी ओर डी कापी खरीदने वाला बेचने वाले को दे देता है ओर असैसमैंट के वक्त जो बेचने वाला है उस औरिजनल कापी को एक्वाईज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के हवाले कर देता है और एक कापी बेचने वाले के रिकार्ड में रह जाती हैं। इसी तरह से दूसरी जो कापियां बी. और सी है वे खरीदार के पास रह जाती हैं। इससे क्या होता है कि इन कापियों को या इन फार्मज का कहीं भी मिलान नहीं होता।

चेयरमैन सहाब, इन फार्मों को कहीं पर भी टैली नहीं किया जाता। इनके बण्डलों के बण्डल, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अन्दर चले जाइए, वहां पर पड़े हुए आपको मिलेंगे। इनकी बोरियां भरी हुई आपको मिलेंगी। इसलिये सरकार कोई ऐसी रास्ता निकाले जिससे कि उन फार्मों को टैली किया जा सके। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अन्दर कितनी भारी हेरा फेरी है। अगर हम ऐसी हेरा–फेरी को पकड़ ले तो जो

हमने सेल्ज टैक्स लगा रखा है, उसका कम से कम 50 परसैन्ट का फायदा हम अपने एक ही काम से कर सकते हैं। इससे प्रान्त के एक्सचैकर को और व्यापारियों को काफी राहत मिल सकती है। साथ ही जो कुरप्शन इसमें हो रही है, वह भी दूर होगी। चेयरमैन साहब, जगाधरी के अन्दर इस चीज को लेकर काफी व्यापारी फंसे हुए हैं। कफद चालाक किस्म के लोग हैं जोकि विभाग के आदमियों से मिल जाते हैं ओर उन से मिलकर उन्हीं फार्मो के अन्दर हेरा–फेरी करते हैं। जो टैक्स होता है, वह सीधे–सीधे जो व्यापारी हैं, उन पर लाद देते हैं। होता क्या है? चेयरमैन साहब, बोगस बिल की परचेज होती है। आज उन्हीं बोगस बिलों की लपेट के अन्दर जगाधरी में बहुत से लोग फंसे हुए है और उन पर लाखों रूप्ये की पैनल्टी पड़ी हुई हे, जिसके कारण लोग फंसे हुए है और उन पर लाखों रूपये की पैनल्अी पड़ी हुई है, जिसके कारण लोग बड़े दु:खी हैं और अगर खरीददार सिकी वजह से बच जाए तो बेचने वाले से वह राशि रिकवर की जाती है। ऐसी हालत के अन्दर जो चालाक आदमी हैं, वह पहले ही बचने का रास्ता निकाल लेते हैं, ओर भोले–भाले आदमी फंस जाते हैं। चालाक लोग और विभाग के भ्रश्ट कर्मचारी दोनों ऐशो–आराम की जिन्दगी बसर करते हैं। उसी काले धन से उन्हीं लोगों की आज कोठियां और बंगले बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो ईमानदार दुकानदार हैं, कारखानेदार हैं, वे अपने खून पसीने की कमाई का पैसा कमाते हैं, उनकी जब असैसमैंट होती है तेा जो नहीं दे पाता, उसके वारन्ट जारी करते हैं। जब उन लोगों के वारन्ट निकलते हैं

तो वे बेचारे इधर उधर भागते हैं। इसके लिये वे अपीले भी करते हैं। जहां इस पैसे की रिकवरी के लिये जो व्यापारी जिम्मेवार है वहां विभाग के अन्दर इस बारे में कोई नहीं देखता कि कोई खरीददार साफ निकल गया है और वह विभाग के आदमी जिन्होंने 'डी' फार्म दिया होता है वह कभी भी टैली नहीं करते इस हेरा–फेरी के लिये कौन जिम्मेवार है? मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि यह बड़ा भारी स्कैन्डल है, इसकी जांच करवायी जाए और उन गरीब आदमियों को जोकि अपने हाथ से काम करते हैं, घरेलू इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनको राहत दिलवायी जाए। आज जगाधरी के अन्दर दो हजार के लगभग फैक्टरियां है और उनके अन्दर 1500 ऐसी हैं जिनके अन्दर लोग अपने हाथ से काम करते हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: ओम प्रकाश जी, आपका समय हो गया है, आप वाइंड अप करें।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: चेयरमैन साहब, मैं सरकार से स्पैशल रिक्वैस्ट करूंगा कि आज तक जो ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वह इंटर–स्टेट है या चाहे स्टेट के अन्दर हुई है, और जो इस बारे में फार्मज विभाग के अन्दर मौजूद हैं, जिनका मिलान नहीं किया गया है, उसकी चैकिंग के लिये आप हुक्म दें। सरकार इस काम के लिये एक स्पैशल सैल बनाए जोकि इस सारे काम–काज की देखभाल करे। आपको लाखों करोड़ों रूप्ये की इवेजन मिलेगी (शेम–शेम की आवाजें) चेयरमैन साहब, ये अपोजीशन वाले

शेम–शेम कर रहे हैं, यह तो इनके लिए शेम होनी चाहिए, हमने तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिये सुझाव ही दिया है ताकि सरकार का और हमीर सारी हरियाणा की जनता का भला हो सके।

इससे आगें, चेयरमैंन साहब, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे स्टेनलैस स्टील के बर्तन हैं, पीतल व तांबे के बर्तन हैं, उनको डिक्लेयर गुडस में रखा जाये। जिन पर चार परसैन्ट टैक्स लगता है जो व्यापारी है,वे शीटस पर फलैट रेट चार परसैन्ट टैक्स लगाकर बिल काल देते हैं, वे कैश के बिल काट देते हैं, वे बोगस बिल होते हैं। न ही कोई व्यापारी होता है और नहीं कोई फर्म बगैरह होती है, सब कुछ बोगस होता है इससे क्या होता है कि वे 4 परसैन्ट टैक्स जमा करवा लेते है। फिर उन बर्तनों के ऊपर 8 परसैन्ट टैक्स आ जाता है। इससे दो रूपये प्रति किलो का फर्क पड़ता है। व्यापारी को आठ आने किलो से एक रूप्या किलो तक फर्क पड़ता है। उससे टैक्स जो है, वह दो रूप्या आ जाता है। इससे टैक्स का इवेजन बढ़ता है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर महोदय को आपके द्वारा कहूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि सरकार को नुक्सान न हो और लोगों मे भी परेशानी न बढ़े। चेयरमैन साहब, हमारा प्रदेश कृशि प्रधान प्रदेश है। इसके अन्दर जहां तक हमारी इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है, न तो हमारे प्रान्त में रा–मैटीरिजल पैदा होता है और न ही हमारे प्रान्त में बर्तनों की खप्त है। बर्तन बनाने के लिए जितना भी

रा–मैटीरियल आता है, वह या तो फारेन से आता है या साउथ से, कलकत्ता और मद्रास बगैरह से आता है। हजारों किलोमीटर दूर से हमारे यहां बर्तन बनाने का रा–मैटीरियल आता है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस पर ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता होगा और कितना आकट्रायल का खर्चा लगता होगा। इतना खर्चा होने के बाद हमारे यहां बर्तान बनाने का रा–मैटीरियल पहुंचता है। चेयरमैन साहब, बर्तन बनाने की फैक्टरीज हर स्टेट में लग चुकी हैं। हमें हर स्टेट को कम्पीट करना है। यदि हजारों किलोमीटर दूर से रा–मैटीरियल हमारे यहां पहुंचेगा तो आप अन्दाजा लगाएं कि हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दूसरी कई स्टेटस में बर्तन बनाने का रा–मैटीरियल अवैलेबल होता हैं उनको वहीं रा–मैटीरियल मिल जाता है और वहां फैक्ट्रीज बर्तन बना लेती हैं। उनके बर्तन भी सस्ते पड़ते हैं। यदि हम दूसरी स्टेटस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो हमारे यहां बर्तनों की फैक्ट्रीज का बुरा हाल हो जाएगा। चेयरमैन साहब, आज जगाधरी में जितनी भी बर्तन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, वे सारी तबाही की तरफ बढ़ रही हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जगाधरी की बर्तन की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सरकार बर्तनों को डिक्लेयर गुडज करार दे और उस पर चार परसैन्ट सेल्ज टैक्स लगाए ताकि जगाधरी की बर्तनों की इंडस्ट्रीज को तबाह होने से बचाया जा सके। इस समय बर्तनों पर सेल्ज टैक्स से, जो सरकार को आमदनी होती है यदि वह चार परसैन्ट कर दिया जाता है तो दोगुना से तीन गुणा तक हो जायेगी। इससे हमारे यहां ज्यादा से

ज्यादा बर्तन बनाए जाएंगे और हम दूसरी स्टेंटस का मुकाबला कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौ. रोशन लाल आर्य (छछरौली): सभापति महोदय, बजट की अनुदान की मांगों पर जो सुपर फास्ट रफतार से चर्चा हो रही है, इस बारे मे ंमैं यह कहना चाहता हूं कि अनुदानों की बहुत लम्बी लिस्ट है और आपने हर माननीय सदस्य को 10–10 मिनट बोलने के लिए समय दिया है। यह समय बहुत ही कम है लेकिन मैं फिर भी 10 मिनट में अपनी सारी बातें कहने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले मांग नम्बर 3 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह मांग गृह विभाग के बारे में है। इस मांग पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह विभाग के अधीन जो पुलिस विभाग है, उसको लोकतान्त्रिक रूप देना चाहिए। इस समय हमारे यहां जो पुलिस है वह ब्रिटिश शासन के समय में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में अपना राज स्थापित करने के लिए और लोगों को कुचलने के लिए जो बनाई थी, वही है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि आज वह पुलिस हमारा काम नहीं कर सकती। हमें पुलिस की ट्रेनिंग बदलनी पड़ेगी ओर लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना पड़ेगा। यहां की पुलिस में अच्छे स्तर के लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकारी बैंचिज पर बैठे माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि उनको पुलिस के कामों की तरफ पूरा ध्यान देना

चाहिए। जिन लोगों ने चुनावों के दौरान आप लोगों का साथ नहीं दिया, उन पर आप झूठे मुकदमें न बनवाएं। आप पुलिस को यह हिदायत दें कि जिन लोगों ने चुनावों के दौरान आपका साथ नहीं दिया, उन पर झूठे मुकदमें न बनाएं आपको इस तरह की व्यवस्था गृह विभाग के अधीन करनी चाहिए। सभापति महोदय, आज बहुत सी ऐसी बातें है, जैसे स्मगलिंग का धंधा है और इस प्रकार के दूसरे धंधे हैं जिनसे जनता बहुत परेशान है। सभापति महोदय, जो स्मगलर हैं, उनके पास आज बहुत साधन हैं। उनके पास गाड़ियों है, हवाई जहाज हैं। इस प्रकार के बड़े–बड़े साधन उनके पास हैं। उनका पुलिस में भी हाथ हैं और सत्ता में भी हाथ है। मैं इस बारे में सरकार से कहना चाहता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग बदली जाए और पुलिस में हर वर्ग के लोगों की भर्ती की जाए जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको पुलिस में अच्छे–अच्छे पदों पर भर्ती किया जाए ताकि जो नीचे के स्तर के लाग है, उनको भी मौका मिल सके। सभापति महोदय, अब मैं मांग नम्बर 9 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मांग नम्बर 9 शिक्षा विभाग के बारे में है। सभापति महोदय, शिक्षा के विकास में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ऐसे बहुत से देहाती हल्के हैं, जिनमें स्कूलों की बहुत कमी है जिसके कारण देहात के बच्चें शिक्षा प्रापत नहीं कर सकते। मेरे हल्के छछरौली में बहुत से ऐसे गांव हैं जिन गांवों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में नहीं जा पाते। ऐसे बहुत से गांव हैं, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है यदि उन छोटे–2 गांवों की आबादी को मिलाया जाए तो 10

हजार की आबादी हो सकती है और वहां पर स्कूल बनाए जा सकते है। मेरे हल्के में बहुत से ऐसे छोटे–छोटे गांव है जिनमें स्कूल नहीं हैं। उन छोटे–छोटे गांवों की आबादी को मिलाया जाए और उनके बीच में कहीं पर स्कूल बनाए जाएं ताकि वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्कूल भी हैं, जिनको अप–ग्रेड किया जाना बहुत ही जरूरी है। उनको अपग्रेड किया जाए। सरकार नए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 200 नई प्राईमरी स्कूल लड़कियों के लिए खोलने जा रही है। मैं यह समझता हूं कि लड़कियों के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा बल्कि लड़कियों के लिए हाई स्कूल भी खोले जाने चाहिएं, सभापति महोदय, छछरोली बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर सरकार की तरफ से कोई कालेज नहीं खोला गया है मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि छछरौली में एक सरकारी कालेज खोला जाए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अम्बाला तहसील में आई.टी.आई. नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे हल्के मेंएक आई.टी.आई. और एक सरकार कालेज बनाया जाए ताकि वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, अब मैं मांग नम्बर 10 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह मांग चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य के बारे में है। सभापति महोदय, मैं चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य विभाग के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में

हैल्थ सर्विसिज ठीक काम नहीं कर रही क्योंकि अच्छे डाक्टर्ज उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने अम्लाबा जिले में एक मैडिकल कालेज के लिए बार बार मांग की कि अम्बाला में एक मैडिकल कालेज खोला जाए ताकि वहां के नौजवान मैडिकल कालेज में शिक्षा प्राप्त करके मैडिकल सर्विसिज में जा सकें। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि अम्बाला में एक मैडिकल कालेज खोला जाए। इसके अलावा अम्बाला सिविल अस्पताल के बारे में जो भी शिकायतें आती हैं, उनको अपोजीशन का हल्का समझकर गोलमाल कर दिया जाता है, और उनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। वह बहुत गल्त परम्परा पड़ती जा रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति बदलती रहती है और कल को आपकी स्थिति भी बदलेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी जायज बातों को मान लेंगे। इसलिए मैं इस सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सरकार मेरी मांगों को माने। सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना चाहिए। आप सभी यह जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाईयों से बहुत बड़ी–बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सारी दुनियां में साईस के आधार पर लोग एम.बी.बी.एस. की डिग्री ले लेते हैं लेकिन वे कई बड़ी बीमारियों को दूर नहीं कर सकते लेकिन मैं यह कहता हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति से बड़ी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हर जिले में एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोला जाए ताकि जो बीमारियां

हैं, उनका इलाज किया जा सके। जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसको भी अजमाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं मांग नम्बर 16 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, यमुनानगर में बहुत ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं और स्माल–स्केल यूनिटस भी काफी लगे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यमुनानगर को भी उधोगिक नगर के रूप में जाना जाना चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) यमुनानगर में डिस्ट्रिक्ट लैवल का इन्डस्ट्रीज सैन्टर नहीं है। वहां पर एक्साईज एक्ट टैक्सेशन का डिस्ट्रिक्ट लैवल का आफिस है और एम्पलायमैंट एक्सचेंज का डिस्ट्रिक्ट लैवल का आफिस है लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्अ लैवल का इंडस्ट्रीज सैंटर नहीं बनाया हुआ। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट लैवल का इंडस्ट्रीज सैंटर भी बना दिया जाए। इस समय वहां पर जो इंडस्ट्रीज टाउन का आफिस है, उसको अप–ग्रेड किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह बात कहना चाहता हूं कि देहातों में स्माल स्केल यूनिटस काफी मात्रा में लगे हुए हैं। यदि कोई नौजवान नये स्माल स्केल यूनिट लगाया चाहे तो उनको सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिए। देहात के नौजवान अपना कोई यूनिट स्थापित करना चाहते हैं इसके लिए यदि वे सरकार के पास आते हैं, तो सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें बहुत से नौजवाब मिलते हैं। वे कहते

हे। कि हमें दफ्तरों के चक्कर कटवाने की बात समझ में नहीं आती। हमारी जो जायज मांगे हैं उनको दफ्तरों में उलझा कर रख दिया जाता है। मैं सरकार में प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नौजवान अपना कोई यूनिट स्थापित करना चाहता है उसकी पूरी सहायता की जाए तथा उसको लोन दिलवाया जाना चाहिए। बहुत से बैंक ऐसे हैं जो सरकार की हिदायतों की पालना नहीं करते जिसके कारण लोन लेने वाले को काफी परेशानी होती है। सरकार को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को लोन ठीक समय पर मिल सके।

अब मैं मांग न. 23 जो परिवहन के बारे में है, कहना चाहता हूं। देहात के अन्दर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर बसें पहुंच नहीं पातीं, जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए और दूसरे लोगों को कचहरी आदि तथा दूसरे स्थानों पर पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। हरियाणा रोड़वेज की 500 बसें खराब खड़ी हैं। इन बसों की नीलामी भी नहीं की जा रही है। नीलामी न होने कारण समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से 50 बसें चण्डीगढ़ डिपू के अन्दर भी बेकार की खड़ी हैं। मैंने वहां पर इन बसों के संबंध में पूछा तो मुझे बताया गया कि इनका अन्दर का सारा सामान निकाल लिया गया है जिस कारण अब नीलाम नहीं हो पा रही हैं। इसी प्रकार से और भी डिपुओं के अन्दर बसें खड़ी है जिनकी यही हालत होगी। इस संबंध में मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि जिस किसी की लापरवाही के कारण इन बसों का

सामान निकाला गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि हरियाणा रोड़वेज की बसों को ठीक प्रकार से चलाया जाये तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन बसों द्वारा कमाया जा सकता है। आज प्रातः प्रश्नकाल के दौरान स्वयं मंत्री जी ने माना है कि दिल्ली के अन्दर एक किलोमीटर का किराया साढ़े तीन पैसे है जबकि हरियाणा के अन्दर एक किलोमीअर का किराया 10 पैसे है। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि किराये के मामले में लोगों को कुछ राहत देकर बस सेवाएं और ज्यादा उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड न. 8 जो भवन तथा सड़कों से संबधित है, कहना चाहता हूं।। मेरे हल्के के अन्दर अस्पताल, स्कूल चिकित्सा केन्द्र या सरकार के जितने भी दफ्तर हैं उन सभी की बिल्डिंगों को अनसेफ डिकलेयर किया हुआ है। इन अनसेफ बिल्डिंगों में तहसीलदार का आफिस भी शामिल है। वहीं पर रोजगार का दफतर भी है और कचहरी भी वहीं पर है। जो सरकारी कर्मचारी इन बिल्डिंगों में बैठते हैं, उनकी जान का खतरा है। इसके साथ–साथ उन लोगों की जान को भी खतरा है जो लोग अना काम करवाने के लिए वहां जाते हैं। बुरी घटना किसी भी समय घट सकती है ओर उससे जनता को काफी नुकसान हो सकता है। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि इस ओर विशेश ध्यान देकर कोई न कोई हल निकालना चाहिए। प्रश्नकाल के समय भी मैंने कहा था कि कई सड़कें कागजों में तो हैं,

लेकिन असल में नहीं हैं। जब दफतर में पता करने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि यह सड़क 5 साल से बनी हुइ है लेकिन वास्तव में वह मौके पर नहीं होती। जो सड़कें बनी भी हुई हैं उनकी बहुत खराब हालत हैं। इसी प्रकार से वहां पर कई महत्वपूर्ण पुल है। जिनकी ओर सरकार को गौर करके उन पर काम शुरू करना चाहिए। जिन पुलों के पत्थर रखे हुए हैं, उन पर सरकार को काम करना चाहिए और उनको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि लोगों के साथ कोई काम करने का झूइा वायदा न किया जाये। यदि कोई वायदा किया जाता है तो उसको नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से पीने के पानी की समस्या मेरे हल्के में अभी भी बनी हुई है। अम्बाला क्षेत्र में कालका और नारायणगढ़ हल्कों के अन्दर तो जरूर पानी का प्रबन्ध किया गया है, क्योंकि यहां के दो मिनिस्टर बैठे हैं। मेरे हल्के के अन्दर भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। मेरे हल्के के कई गांव ऐसे हैं, जहां पर एक ही घाट पर पशु और आदमी पानी पीते हैं। सरकार को इस तरफ भी विशेश ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांडों का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

प्वायंट आफ आर्डर

विधान भवन में मैम्बर्ज को पैम्फलैट पब्लिकेशन डिस्ट्रिब्यूट करने सम्बन्धी

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। स्पीकर साहब, क्या कोई व्यक्ति हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही के खिलाफ, विधान सभा में भाग लैने वाले विधायकों के खिलाफ या सरकार या प्रैस के खिलाफ कोई चीज या पैम्फलैट लिख कर बांअ सकता है? इस हाउस के गेट पर यह पैम्फलैट सभी को बांटा जा रहा है। क्या आपने सैक्रेटेरियेट के किसी अधिकारी की डियूटी लगाई हुई है? यह पैम्फलैट हरद्वारी लाल द्वारा लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: हमारा आफिसर तो कोई भी नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: आपने किसी को इजाजत दे रखी होगी। यह पैम्फलैट जो सभी विधायको को बांटा जा रहा है इसमें विधायकों, सरकार और प्रैस के खिलाफ लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। मैं इसे कल देखूंगा।

वर्श 1983–84 के बजट की डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री देवी दास (सोनीपत): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 9, 10, 11 तथा 16 पर बोलना चाहता हूं। मैं सबसे पहले डिमांड न. 9 पर बोलना चाहता हूं। इस डिमांड के तहत 101 करोड़ 71 लाख रूपये खर्च करने के लिए मांगे जा रहे हैं। इससे

पहले भी मैंने बजट पर बोलते हुए कहा था कि हरियाणा के बन्दर जो 21 हजार टीचर मान्यता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारे वजीर साहब कभी खड़े होकर उनकी मांगों के समर्थन में हां कह देते हैं तो कभी खड़े होकर कहते हैं कि हमने इन अध्यापकों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। स्पीकर साहब, सोनीपत जिले के अन्दर न कोई गवर्नमैंट कालेज है और न ही सोनीपत के अन्दर कोई गवर्नमैंट हाई स्कूल हैं और न ही वहां पर डी.ई.ओ. का आफिस ठीक जगह पर है। डी.ई.ओ. का आफिस जिस जगह पर अब है, वह एक पुरानी बिल्डिंग किराये पर ली हुई है। इतना ही नहीं म्युनिसिपल कमेटी का जो स्कूल गवर्नमैंट ने लिया था, उसकी हालत भी बहुत खसता है। इस संबंध में मैं कई दफा डी.ई.ओ. से भी मिल चुका हूं और एजुकेशन के जो बड़े–बड़े अधिकारी हैं, उनके भी मिला हूं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि उस स्कूल की बिल्डिंग तुरन्त ठीक करवायी जानी चाहिए। यदि जल्दी से जल्दी उस स्कूल की बिल्डिंग ठीक न करवाई गई तो उससे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है।

अब मैं डिमांड न. 10 पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर साहब, सोनीपत के अन्दर 15–16 साल पहले का एक पुराना अस्पताल बना हुआ है। वहां का कोई कमरा ठीक नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही जनरल वार्ड बना हुआ है। न उस अस्पताल के

अन्दर एमरजैंसी वार्ड है और न ही दूसरी सुविधाएं। उस अस्पताल के अन्दर सारे मरीजों को इक्ट्ठा रखा जाता है। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि इस और ध्यान दिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, आज से तीन साल पहले वहां पर एक नया हस्पताल बनना शुरू हुआ था। उस अस्पताल को बनते हुए करीब तीन साल हो गए हैं। में यह समझता हूं कि यदि उस अस्पताल पर इसी तरीके से काम होता रहा तो उसे अभी बनने में पांच साल का और समय लगेगा। इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उस अस्पताल के अन्दर जो मैटीरियल लगाया जा रहा है वह ठीक नहीहं है। अभी से उस अस्पताल में जो ईटें लगाई जा रही है, उन पर सफेदी आनी शुरू हो गई है और इसी प्रकार से सीमेंट की जो पुताई की जाती है, वह भी अभी से उखड़नी शुरू हो गई है। मैंने इस संबंध में वहां सक सी.एम.ओ. से भी कहा था। उन्होंने कहा कि यह काम तो पी.डब्ल्यू.डी. का है। जब काम अस्पताल का हो रहा है तेा वहां का जो सी.एम.ओ. हे, वह पी. डब्ल्यू.डी. के एक्सीयन को कह सकात है कि ठीक मैटिरियल लगाये। यदि इस नए अस्पताल की तरफ ध्यान न दिया गया तो इसकी भी हालत कुछ समय बाद पुराने हस्पताल जैसी ही हो जायेगी। स्पीकर साहब, आज से पांच साल पहले चौ. भजन लाल जी ने, जिस समय ये मंत्री थे, पिलाना गांव में एक डिस्पैंसरी के लिए नींव पत्थर रखा था। वहां की बिल्डिंग भी गांवों वालों ने बनाई थी और जमीन भी गांवों वालों ने दी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर आज तक न तो कोई डाक्टर

पहुंचा है और न ही कोई कम्पाऊंडर गया है। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार को गुजारिश है कि उस डिस्पैन्सरी में डाक्टर वगैरह भेज कर जल्दी से जल्दी चालू किया जाये।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड न. 16 पर आता हूं। सोनीपत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं लेकिन रूरल इंडस्ट्रियलाईजेशन स्कीम के अन्तर्गत जितने यूनिटस सोनीपत जिले में लगे हैं, इनकी बड़ी बुरी हालत है। ये पैटों वाले बाबू इन यूनिटस के मालिकों के पीछे घूम रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग फैक्ट्रियां बन्द करके चले गये हैं। इसका कारण यह है कि यूनिट लगाने से पहले हरियाणा गवर्नमैंट ने उनको विश्वास दिलाया था कि जो रूरल एरियाज में इंडस्ट्री लगायेगा, उनको कच्चा माल दिया जाएगा, नगरपालिका की चूंगी खत्म की जाएगी, उनके बनाये हुए माल पर सैल्ज टैक्स खत्म किया जाएगा और माल को सरकार खुद खरीदेगी। लोगों ने मंहगी जमीन लेकर रूरल एरियाज में अपनी फैक्ट्रियां लगाई, यहां पर हैंडलूम का काम बहुत अच्छा चलता था लेकिन सरकार की गल्त पालिसी की वजह से इसमें भी गिरावट आ रही है। अगर सिकी ने फाऊंडरी लगाई होती या कच्चा माल बनाने के लिए कोई यूनिट लगाया होता जो चला न हो और फेल हो गया हो तो मैं मान सकता था लेकिन अगर लोगों ने खड्डियां लगाई हों और वे भी फेल हो रही हों, तो इसका मतलब यही है कि सरकार की गल्त नीतियों की वजह से ये यूनिटस फेल हो रहे हैं। यह

खड्डियां जो माल तैयार करती हैं, उसको खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं हैं, म्यूनिसिपल कमेटी की चूंगी मुआफ करने के लिए सरकार तैयार नहीं। इसके इलावा, स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि रूरल इंडस्ट्रियलाईजेशन स्कीम के अन्तर्गत जो यूनिटस रजिस्टर हुए हैं, उनको सबसिडी नहीं दी गई और न ही वह सहूलियतें दी गई हैं, जो देनी चाहिए। जब इंडस्ट्रीज आफिसर से यूनिटस के मालिकों ने बार–बार कहा तो वे कह देते हैं कि आपका केस चण्डीगढ़ भेज दिया गया हैं। आप जानते हैं कि चण्डीगढ़ में जो फाइल एक दफा आ जाए, वह वापिस नहीं जाती। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सोनीपत के अन्दर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम के तहत जो यूनिटस लगे हैं, अगर सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये सारे के सारे खत्म हो जायेंगे। बड़ी फैक्ट्रियों वाले तो पहले से ही चाहते हैं कि छोटी फैक्ट्रियों वाले न पनपें ताकि उनकी मनौपली बनी रहे। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को छोटे यूनिटस की तरफ ज्यादा ध्यणन देना चाहिए। इसके इलावा सरकार ने कुछ छोटी इंडस्ट्रीज पर पाबन्दी लगा रखी है जो बड़ी नुक्सानदेह है। अगर कोई व्यक्ति आटे की चक्की लगाने के लिए एप्लाई करता है, तेल का कोहलू लगाने के लिए एप्लाई करता हे तो कह दिया जाता है कि इस पर सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है। इन यूनिटस के इलावा और तो कोई इंडस्ट्री बची नहीं जो रूरल एरियाज में लगाई जा सके और जब कोई व्यक्ति एप्लाई करता है तो पाबन्दी लगाई जाती है।

स्पीकर साहब, अब मैं मांग न. 11 की तरफ आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, ये नगर विकास की बड़ी–बड़ी करते हैं और इसके लिये इन्होंने सारे हरियाणा में सैक्शन 4 के तहत जमीन एक्वायर कर ली है। जहां यह सैक्शन लागू होता है, वहां किसान मरता है। न तो किसान अपनी जमीन सिकी और को बेच सकता है और न ही गवर्नमैंट उस जमीन को एक्वायर करती है। सोनीपत जिले में सैकड़ों एकड़ जमीन सैक्शन 4 के तहत एक्वायर की जा रही है। जो आदमी एप्रोच कर लेते हैं, वे तो अपनी जमीन छूड़वा लेते हैं, लेकिन दूसरे गरीब आदमी नुक्सान उठाते हैं। सोनीपत ने बहादुरगढ़ तक और दिल्ली तक सैक्शन 4 के तहत जमीन एक्वायर की जा रही है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार को जितनी जमीन चाहिए उतनी बेशक एक्वायर कर सकती है लेकिन किसान को उसकी जमीन की ठीक–ठीक प्राईस दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सस्ती जमीन लेकर बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस को फायदा पहुंचाये।

स्पीकर साहब, डिवैल्पमैंट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये 20 सूत्रीय प्रोग्राम की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि छोटे दुकानदारों के लिए लाईसैंस फीस 10 रूपये थी लेकिन इन्होंने इसको बढ़ाकर 100 रूपया कर दिया। एक–एक दुकानदार जिसके पास पांच–पांच लाईसैंस होते थे, और उनको 50 रूपये देने पड़ते थे लेकिन अब उसको 500 रूपये देने पड़ेंगे। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार इस तरफ

ध्यान दे। सोनीपत के अन्दर नगर विकास की बात करने वाले यूनिटस अलग–अलग काम करते हैं। 'हुड्डा' अलग काम करता है, हाउसिंग बोर्ड अलग काम करता हे, नगरपालिका अलग काम करती है और इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट अलग काम करता है। इतने विकास यूनिटस होते हुए भी सोनीपत की हालत बहुत खराब है। स्पीकर साहब, ड्रेन न. 6 पहले सोनीपत शहर के बाहर से जाती थी लेकिन अब अन्दर से जाती है। बाहर से इसलिए बनाई थी ताकि फ्लड का पानी इस ड्रेन में बह जाए। अन्दर से जाने के कारण इस ड्रेन में सारे शहर का गंद गिरता है जिसकी वजह से डेन न. 6 एक गंदा नाला बन कर रह गई हैं। वहां पर एक बीयर फैक्ट्री है, इसका बदबू वाला पानी इस डेन में जाता है। शूगर फैक्ट्री का गंदा पानी इस में जाता है और हाउसिंग कालोनी का गंदा पानी भी इसी में जाता है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि ड्रेन न. 6 जो सोनीपत शहर के बीच से निकलती है, इसको बाहर से निकाला जाए।

स्पीकर साहब, मेरे भाई श्री मनफूल सिंह जी ने कहा था कि विधान सभा के एम.एल.ए. होस्टल में काम करने वाले कर्मचारी सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन उनको ओवर टाईम नहीं मिलता। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको ओवर टाईम दिया जाए। स्पीकर साहब, मैं भी एम. एल.ए. फ्लैट में रहता हूं। फ्लैट में सुबह 7 बजे पानी चला जाता है और कई बार सारा सारा दिन पानी नहीं आता। इसलिए पानी

की रैगुलर सप्लाई होनी चाहिए ताकि एम.एल.ए. फ्लैट में रहने वाले एम.एल.ए. सुबह स्नान कर सकें। इसके इलावा जो स्टाफ ज्यादा देर डियूटी देता है, उसको ओवर टाईम दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): स्पीकर साहब, मैं हाउस का ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता। थोड़ा सा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बोलना चाहता हूं। स्पीकर साहब, आपने दखेा होगा कि हाउस के अन्दर इस बात की बड़ी चर्चा रही है और पिछले दो–तीन सालों के अन्दर नैचुरल क्लैमिटीज की वजह से सरकार को काफी पैसा देना पड़ा और यह बोझ सरकार को बहुत पिंच किया था। सरकार ने दूसरे महकमों के बजट से पैसा निकाल कर किसानों को बतौर रिलीफ दिया था। मुझे रवैन्यू मिनिस्टर साहब ने बताया था कि इस साल बतौर रिलीफ 14 करोड़ रूप्या खर्च किया है। यह तो हर साल का रूटीन हो गया है क्योंकि हर साल ही अनसर्टन नेचर की वजह से नैचुरल क्लेमिटीज आती है। पिछले साल चौ. शमशेर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इनसे पहले ब्रिगेडिर रणसिंह मिनिस्टर थे। ब्रिगेडियर रणसिंह के टाईम से एक स्कीम चल रही थी, जिसको क्रोप इन्शोरैंस स्कीम कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस स्कीम का क्या बना? इस स्कीम के लिए पैसा न तो बजट के अन्दर है और न ही इन डिमांडज के अन्दर कोई डिमांड है। इसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया। जहां तक मैं समझता हूं, इस स्कीम

को खत्म ही कर दिया गया है। Even if this Scheme has not been abandoned it is riciculous that only a sum of Rs. 2200/- per farm will be given to a farmer as insurance money. अगर किसी किसान का खराबा 2200 रूपये से अधिक है, तो उसको किसी भी हालत में इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा।

यह स्कीम सरकार के ध्यान में है और इस स्कीम के बारे में सब जानते हैं। कुछ न कुछ सरकार को इस बारे में कहना चाहिए। अगर जनरल इन्शयोरैन्स की स्कीम भारत सरकार की है और उसकी वजह से कोई लिमिटेशन है, तो हमें अपनी कोई स्कीम लानी चाहिए।

कृशि मंत्री (चौ. सुरेन्द्र सिंह): आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर कृशि विभाग के विशय में बोल रहे हैं लेकिन कृशि विभाग की डिमान्डज कल पास हो चुकी हैं। क्या गवर्नमैंट की तरफ से जवाब देने का मौका हमें भी मिलेगा?

राव इन्द्रजीत सिंह: मैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूं। यह डिमांड एग्रीकलचर के बारे में हैं लेकिन सारी डिमांडज से पैसा निकाल करर देना पड़ेगा। अगर एग्रीकलचर मिनिस्टर साहब जवाब नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें। अगर सरकार भारत सरकार की जनरल इन्शयोरेन्स स्कीम को लागू करने में कोई डिफिकल्टी समझती है तो हरियाणा सरकार अपनी खुद की कोई स्कीम बना ले ताकि किसानों का भला हो

सके। इतनी ही मेरी सुजैशन हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार क्रोप इन्शयोरैंस की स्कीम को इम्पलीमैंट करे।

श्री भागी राम (एलनाबाद, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, हाउस के सामने 20 डिमान्डज पेश हुई हैं। इन डिमांडज के थ्रू डिपार्टमैंटस को अलग–अलग पैसा अलाट किया गया है कि किसको कितना पैसा दिया जायेगा। स्पीकर साहब, इन डिमांडज के मंजूर होने के बाद यह पैसा कैसे खर्च होता है, उसके ऊपर मैं अपने विचार हाउस में रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जिस महकमें का है, वह अपने तरीके से अपने हल्के में पैसा खर्च करता है। आज हाउस चलते हुए कितने दिन हो गये हैं लेकिन अपोजीशन की बातों की ओर कोई विशेश ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी तरफ तो ध्यान देने की बात ही नहीं है, जो भाई हमारी तरफ से गये हैं वे भी नीचे–नीचे दुखी हैं। * * * *

श्री अध्यक्ष: बन्धवा लफ्ज को एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, हर मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट होती है। हर मिनिस्टर को इसका एक–एक लाख रूप्या मिलता है। अगर आप यह पता करें कि वह ग्रान्ट किस को दी गयी है तो आपको पता लगेगा कि जहां पर मिनिस्टर का भाई ब्याहा हुआ है, लड़के की ससुराल है या साली ब्याही हुई है, वहां पर उस गांव में डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट दी जाती है। जिन

गांवों में या जिन संस्थाओं को ग्रान्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें नहीं दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा को सामने रख कर देख लें, सबसे ज्यादा ग्रान्टस आदमपुर कांस्टीच्यूएंसी में दी गई है। एक तरफ सारा हरियाणा है और दूसरी ओर आदमपुर कांस्टीच्यूएंसी है। आदमपुर में बजट का 1/4 हिस्सा खर्च होता है। आज मेरा फतेहबाद के बारे में क्वैश्चन था कि वहां पर सब–डिपो बनाया जायेगा या नहीं लेकिन जवाब मिला कि अभी वहां पर सब–डिपो सैट–अप नहीं किया गया है।

सिरसा के अन्दर डिपों बना दिया गया है लेकिन वहां पर बिल्डिंग नहीं बनायी जा रही है। सिरसार जिले को इग्नोर किया जा रहा है। सिरसार की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है लेकिन फतेहाबाद के पास पता नहीं ब्याह रखे हैं या कोई उनका रिश्तेदार है वहां पर भी तरक्की हो रही है। इसी प्राकर आदमपुर में बस अड्डे पर बीस लाख रूपया खर्च किया गया। आदमपुर कांस्टीच्युएंसी तो दूर से ऐसी लगती है जैसे कोई चंडीगढ़ पहुंच गया हो। अगर कोई अपोजीशन के हल्के में जाता है तो ऐसा लगात है कि जैसे जैसलमेर पहुंच गया हो।

स्पीकर साहब, अब मैं एग्रीकलचर और सहकारिता के बारे में कुछ अर्ज करना चाहात हूं। स्पीकर सहाब, इन मिनिस्टरों के टेलीफोन के बिल्ज ही इतने हो जाते हैं विकास के काम हो ही नहीं पाते। मैंने टेलीफोन बिलों के बारे में जिक्र किया था क्योंकि इस बारे में मेरा क्वैश्चन भा था। जब ये मिनिस्टर टेलीफोन करते

हैं तो यही पूछते हैं कि पप्पी जाग गई है या सो रही है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, ये लोग नाजायज खर्च करते हैं और हमारे से इस पैसे को पास करवाते हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने जिले सिरसा के बारे में खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर आटोमोबाइल मार्किट बन रही है। उसके लिये जमीन एक्वायर की गई। जिस आदमी की जमीन एक्वायर की गर्ठ वह औरिजनल कांग्रेसी है। उस आदमी ने चुनाव भी लड़ा था। अब सरकार ने उस जमीन को छोड़ दिया है लेकिन गरीब आदमियों की जमीन एक्वायर कर ली गई है। एक मिनिस्टर महोदय हैं, जिनका मैं हाउस में नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने अपनी रेड्डी चोटी का जोर लगा कर जमीन को छुडवाया है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनिस्टर ने तो डी.सी. साहब को बहुत डांटा कि इतने बड़े खजानची की जमीन को क्यों एक्वायर किया हैं। उसी खजांची की जमीन बस अड्डे के लिए एक्वायर की गई थी। पता नहीं भजन लाल जी से किस तरह से सांठगांठ करके वह जमीन छुड़वा ली गयी। इसी तरह से ओढ़ा में एक ट्रेनिंग सैन्टर खोला गया था। स्पीकर साहब, मेरे से पूछ कर तो किसी ने पैसा दिया नहीं लेकिन लोग कहते हैं कि पांच–पांच सौ रूप्या उस में दाखिला का दिया है। सिरसा जिले में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। बसों के मामले में भी यही स्थिति है। सिरसा को सारी बातों में इग्नोर किया जा रहा है। हमारे सिरसा जिले में तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। वहां के तीन मिनिस्टर ले लिये हैं। तीन का तो नाम ही बुरा होता हैं। तीन आदमी कहीं

जाते हैं तो वहां काम नहीं बन पाता है। तीन में या तो एक को ड्राप कर दिया जाय या ठाकुर बहादुर सिंह को भी ले लिया जाये। उनके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया हुआ है?

श्री अध्यक्ष: आपकी अपनी मर्जी क्या है?

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं कभी भी * * * * बनने के लिए तैयार नहीं। स्पीकर साहब, सुबह मुख्यमंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि लोग प्रेम सम्बन्ध के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। कभी इनमें से कोई आत्महत्या न कर ले। इसी प्रकार से मेरी कांस्टीच्यूएंसी में बदले की भावना से 15–20 सरपंचों को सन्पैन्ड किया हुआ है। नेहरा साहब जरा ध्यान से सुन लें। जो भी सरपंच हमारे नजदीद का है ये उसे ही सस्पैंड कर देते हैं। मतवा गांव के सरपंच को इसी बात पर सैस्पैन्ड कर दिया। जब वहां बी.डी.ओ. साहब चुनाव कराने के लिए गये तो पांचों के पांचों पंच हमारे अपने ग्रुप के थे। अब सवाल आया कि किस को सरपंच चुने। मैं यह सब बातें नेहरा साहब की इतलाह के लिए बताना चाहता हूं कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। हमारे आदमी पर केस बनवा दिया और अपने आदमी को सरपंच बना दिया।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। क्या ये बजट पर बोल रहे हैं? इन्हें सोच–समझ कर बातें करनी चाहिएं। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः चौ. भारी राम जी, आप का टाईम हो गया है। इसलिए आप जल्दी खत्म करें।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं।

श्री जगदीश नेहराः आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। स्पीकर सहाब, इस साइड वाले माननीय सदस्य श्री भागीराम जी बार–बार जो कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्या बजट का यह कोई मौजू है या यूं ही हर बात गलत और बिना तरीके से हर प्वायंट पर कहनी है। मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी है। इन्होंने लगातार कई बार मेरा नाम लेकर एलीगेशन्ज लगाये हैं। क्या * * बोलने का ठेका हर बार इन्होंने ही ले रखा है। स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना हैं कि आप हमारे इस विरोधी दल के भाइयों को गलत बात कहने से रोकें।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, अगर आप मुझे 5 मिनट और बोलने की इजाजत दे ंतो मैं इनके सारे कारनामें खोल दूं। अगर आप कहें तो आपके टेबल पर रखवा दूं।

श्री अध्यक्षः नहीं।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैं सड़कों के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, नेहरा साहब ने कहा है कि * * बोलने का इन्होंने ठेका ले रखा है, आप देख लीजिये * * शब्द अन–पार्लियामैंट्री है, इसको आप एक्सपंज करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: हां, इसे एक्सपंज कर दिया जाये। (व्यवधान एवं शोर) एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बात के बारे में आपके पास फैक्टस न हों, वह बात कहने से अवायड करना चाहिये। (व्यवधान एवं शोर)

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, सड़कों के बारे में जहां तक बात है, जब से यह मौजूदा सरकार हरियाणा में आयी है, तब से ही मेरे हल्के में जिन–जिन सड़कों पर पहले काम शुरू हो रहा था, वह भी बन्द कर दिया गया है। अभौली से धनौराखेड़ा तक एक सड़ बननी थी वह मन्जूर हो चुकी थी, गांव वालों ने मिलकर मिट्टी भी डाल दी थी लेकिन वह बनानी बन्द कर दी गयी। (व्यवधान एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: आपका टाईम हो गया है। अब आप कृपाया बैठिए।

श्री भागी राम: * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ इन्होंने अभी मेरे आर्डर के बिना बोला है, यह सब एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर, सर यह तो फैक्ट की बात कह रहे हैं, यह तो रिकार्ड पर रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जब मैं खड़ा हूं तब भी यह बैठने की बजाये बोलते रहते हैं, आप इनको समझायें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, उसके लिये तो मैं आगे से इन्हें बता दूंगा और ये बैठ जाया करेंगे लेकिन जो फैक्चुअल बात है, वह तो एक्सपंज नहीं होनी चाहिये।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): स्पीकर साहब, आज जो मांगे इस हाउस में पेश की गयी हैं, मैं उनमें से मांग संख्या 9, 16, 12, 8 और 13 के बारे में अपने विचार रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मेरे कई साथियों ने अपने विचार इन मांगों के बारे में रखे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: एन, उन फैक्टस को जो आपने एक्सपंज करवा दिये थे, क्या आपने उनको रिकार्ड पर रखने के लिये हुक्म दे दिया है। (व्यवधान एवं शोर).....

श्री अध्यक्ष: जब कोई मैम्बर मेरे खड़ा हो जाने के बावजूद न बैठे और बोलता चला जाये, तो मेरे पास आप ही बताइये कि क्या आल्टरनेटिव है सिवाये इसके कि उसके शब्दों को एक्सपंज कर दूं।

श्रीमती चन्द्रावती: सर, आपने जो हुक्म दिया है, वह तो हम मानते हैं लेकिन जो कुछ भी भागी राम जी ने कहा है, वह प्रान्त के भले के लिये कहा है, इसलिये वह रिकार्ड पर रहना चाहिये।

Mr. Speaker: I have given my ruling. Now Sh. Amir Chand Makkar may continue.

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, मेरे बहुत से साथी काफी कुछ बोल रहे थे। मुझे एक शेयर याद आ रह है –

खुदा ने उस कौम की आज तक हालत बदली नहीं,

जिसको खुद ख्याल न हो, उसको बदलने का। (व्यवधान एवं शोर)

स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं मांग संख्या 9 पर अपने विचार रखूंगा। शिक्षा के विकास के बारे में हरियाणा सरकार ने जो मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस साल सारे हरियाणा में 200 प्राइमरी स्कूल खोलने और 100 स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, यह निहायत काबिले तारीफ है। बैकवर्ड क्लासिज हरिजन लड़कों और छोटे–छोटे बच्चों को तालीम देने के लिये सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, वह एक सराहनीय कार्य है। मैं यह चाहूंगा कि जैसे हरियाणा सरकार शिक्षा के विकास के मामले में सारे हरियाणा में काम कर रही है, वैसे ही हांसी के अन्दर भी काम होना चाहिये। हांसी के अन्दर आज कोई

भी मुख्य रूप से स्कूल की बिल्डिंग ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे हरियाणा सरकार सारे प्रान्त में शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रही है, वैसी ही हांसी में स्कूल की बिल्डिंग भी ठीक होनी चाहिये।

अब मैं मांग संख्या 16 पर जो कि इंडस्ट्रीज के बारे में है, कुछ कहना चाहता हूं। सारे हरियाणा के अनदर उद्योगों के सिलसिलें में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। बड़े–बड़े उद्योगपतियों को हरियाणा मे उद्योग लगाने के लिये आवाहन किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे हरियाणा का विकास होगा और हरियाणा के लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे पंचकूला में 21 करोड़ रूप्ये की लातग से जो सरकार का कारखाना लगाने की स्कीम है, वह बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पानीपत के पास ही एक तेल शोधक कारखाना सैंट्रल गवर्नमैंट लगाने लग रही है इससे भी 2000 को काम मिलेगा। इससे काफी फायदा हरियाणा का होगा। यह भी एक अच्छी स्कीम है। जो मांग संख्या 12 है, अब मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सरकार ने मजदूरों के हित के लिये भी काम किया है। इसने आम मजदूर की दिहाड़ी 13 रूप्ये और खेतीहर मजदूर की दिहाड़ी 14 रूप्ये करने का भी इसमें प्रावधान रखा है। यह एक बहुत अच्छी बात है। इससे आपको अपने पांच पर खड़ा किया जा सकेगां उनको अपने पांव पर खड़ा करने के

लिये जो स्कीम बनायी गयी है, यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अन्दर 1983–84 के दौरान 38 करोड़ रूपया इस काम के लिये रखा गया है ताकि मजदूरों के लिये रोजगार के साधन बढ़ाये जा सकें। सबसे पिछड़े हुए लोगों और हरिजन तबके के लोगों की हालत सुधारने के लिये भी इसमें तजवीज रखी गयी है। यह एक बहुत ही अच्छी तजवीज हैं इससे पिछड़े हुए लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने और उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिये काम किया जा सकेगा। मैं इसका समर्थन करता हूं।

अब मैं डिमांड न. 8 पर बोलना चाहता हूं। बिल्डिंगज और रोड्ज के बारे में हरियाणा प्रदेश सरकार ने पहले ही बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है कि इसने हर गांव में सड़क पहुंचा दी है। अगर कोई गांव रह गये हैं, जैसे हरिजन बस्तियों का जिक्र आया है, ऐसे स्थानों पर, जहां पर आधी से ज्यादा आबादी हरिजनों की है, वहां पर भी सड़कें जरूर पहुंचायी जायेंगी। इसके अलावा अढ़ाई सौ की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जायेगा। यह एक बहुत अच्छा काम है। मैं इस बारे में यह अर्ज करूंगा कि मेरे हांसी हल्के में भी दो–चार गांव ऐसे रह गये हैं जहां पर अभी सड़के ले जाने की जरूरत है। एक सिंधवा से मदनहेड़ी, सीसर से खरबला और भाटोल से खरकड़ा आदि तक सड़कें बनाना जरूरी है ये गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें बनाने की अभी जरूरत है। इसके अलावा, ढानियां अभी कई हैं, जहां पर

सड़कें बनायी जानी शेश हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के में खासतौर पर इन गांवों मे ंभी सड़कें बनायी जायें।

13.00 बजे

इस सरकार ने साढ़े तीन हजार मकान बनाने का प्रावधान किया है। इसमें से 65 प्रतिशत हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को ये मकान दिए जाएंगे। इससे जो बेघर लोग हैं उनको बहुत लाभ होगा और वे लोग अने मकानों में रहने के लायक हो सकेंगे। इसके साथ–ही–साथ मांग नम्बर ग्यारह, जो अर्बन डिवैल्पमैंट से सम्बन्धित है के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस मद मे भी काफी पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि यह पैसा अभी भी कम है। स्पीकर साहब, सरकार ने बहुत से शहरों का दर्जा बढ़ाया है जिससे एम्पलाईज को बहुत फायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस मद में और पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है। स्पीकर साहब, हांसी जो कस्बा है वह मुगलों के जमाने का बसा हुआ है लेकिन आज तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर सरकार स्कूल, कालिज और सड़कें बनाए जिससे कि यह कस्बा कुछ उन्नति कर सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं चिकित्सा और पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। इस सरकार ने गांवों में डिस्पैसरियां खोली हैं और शहरों में बड़े–बड़े अस्पताल खोले हैं। मेरा

कहना यह है कि जहां पर दवाइयां या डाक्टर्ज नहीं है सरकार को वहां पर ये चीजें जुटानी चाहिएं और इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने भी अच्छा काम किया है और लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिल रहा हैं डिपार्टमैंट ने पानी की कई स्कीम्ज बनाई हैं और उन स्कीम्ज के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे हल्के हांसी में सोरखी, देपली, रामायण डंडेरी, सैनीपुरा और उसके आप–पास जो तीन चार ढानियां हैं, वहां पर भी पीने के पानी की स्कीम्ज चालू की जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे टाईम दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती बसन्ती देवी (हसनगढ़): स्पीकर साहब, एशियाड 1982 के दौरान एक फ्रैंच दिल्ली आया और दिल्ली को देखर बहुत इम्प्रैस हुआ। एशियाड 82 का इन–औगरेशन देखा, गेम्ज देखे और देखकर बहुत इम्प्रैस हुआ और उसने यह समझा कि यह देश बहुत अमीर है और इस देश ने बहुत तरक्की की है। दूसरे दिन बदकिस्मती से वह जामामस्जिद की तरफ चला गया लेकिन वहां पर उसने दूसरी ही तस्वीर देखी। वहां पर उसने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को देखा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए लोगों को देखा, भीख मांगी हुई लड़कियों को देखा जिनके बदन पर फटे चीथड़े थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थीं ओर वे लड़कियां पीछा नहीं छोड़ रही थीं। यह देखकर उसको अपने देश की याद आ गई

जहां पर रैवोल्यूशन आया था। वह भागा हुआ गया और तार देने लगा और उसमें लिखने लगा – "Revolution is expected in India within 24 hours. वहां पर एक अंग्रेज खड़ा था। उसने कहा कि दोस्त तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि देश की क्या हालत है। उस अंग्रेज ने कहा – 'Forget it. It would not come for another 100 years." अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों में से किसी से भी सहमत नहीं हूं। न तो 24 घंटे में रैवोल्यूशन आता है और न ही सौ साल लगने वाले हैं। स्पीकर साहब, जब कभी भी हम रूलिंग पार्टी वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में हालात बहुत खराब हैं, यहां एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है, तो उधर के लोग ऐसे हंसते हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे वे जानते ही नहीं कि हरियाणा में क्या हो रहा है। स्पीकर साहब, हरियाणा में जो कानून है वह मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें मक्खी और छोटे–मोटे कीड़े तो फंसते हैं लेकिन बड़े कीड़े जाले को लेकर भाग जाते हैं। आज हरियाणा में बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस लाखों रूप्ये की बिजली की चोरी हर महीने करते हैं लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। स्पीकर सहाब, जवाहर लाल नेहरू कैनाल पर करोड़ों रूपया खर्च किया गया। जिन कट्रैक्टर्ज ने नहर बनाई और जिन औफिसर्ज ने इसको पास किया उन्होंने इसमें वारे न्यारे कर लिए आज उस नहर की जो हालत है उसको शायद मिनिस्टर साहब ने देखा होगा। वह इसलिए बनाई गई थी कि आस–पास की जमीन पर वाटर लौगिंग न हो। लेकिन आज

हालात यह है कि नहर के काफी दूर तक सारे साल पानी खड़ा रहता है। वे ठेकेदार और वे अफसर जिन्होंने उस नहर का बनाया और पास किया वे करोड़पति बने हुए हैं और जिन किसानों की जमीन ली गई वे बेचारे भिखारी हो गए। स्पीकर साहब, आज किस चीज में मिलावट नहीं है? आज आप किसी चीज को ले लीजिए, दूध ले लीजिए, मिट्टी का तेल ले लीजिए, खाने–पीने की चीजों को ले लीजिए और शराब को ले लीजिए, कहने का मतलब यह कि हर चीज में मिलावट है। मिलावट करने वाला आदमी हरियाणा में छूट सकता है। दूसरे देशों में अगर कोई आदमी किसी को कत्ल कर देता है तो वह फांसी से छूट सकता है लेकिन मिलावट करने वाला फांसी से नहीं छूट सकता। कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा है कि मिलावट करने वाले पर दो सौ रूप्या जुर्माना और दो महीने की सजा। स्पीकर साहब, जिस आदमी ने करोड़ों रूपया मिलावट करके कमा लिया उसको सिर्फ दो सौ रूपया जुर्माना किया जाता है। कितनी अजीब बात है? स्पीकर साहब, आज यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं जो ब्लैक में नहीं मिलती हो लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैंने किसी को सजा पाते हुए नहीं देखा और ऐसी सजा पाते हुए नहीं देखा जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। दूसरी तरफ 15 अगस्त, 1982 को कुछ सिपाहियों ने अपनी डयूटी का इसलिए बहिश्कार किया ताकि सरकार को पता लग जाए कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, वे दुःखी हैं और उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। लेकिन हमारे

सी.एम. साहब ने बहुत बेरहमी से उनको नौकरी से निकाल दिया और उनके बिस्तर बंधवा दिए।

स्पीकर साहब, ये जो बड़े आदमी हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये लोग कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, कानून खरीद सकते हैं सजा देने वालो को भी खरीद सकते हैं और रिकार्ड वगैरह को भी बदलवा सकते हैं। स्पीकर साहब, एक और बात की तरफ मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहती हूं कि जो सरकार ने पीछे सिपाही निकाले हैं, वे बेचारे बिल्कुल बेकसूर थे। वे इसलिये निकाले गये क्योंकि वे किसानों के बेटे थे, उनमें कानून खरीदने की ताकत नहीं थी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहती हूं कि कम से कम सरकार उनसे उनकी तकलीफें तो पूछ लेती कि आपको क्या दिक्कतें हैं? हम यह कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उन लोगों ने किसी चाव में आकर के नौकरियां छोड़ी हों? स्पीकर साहब, उन पर यह इलजाम लगाया गया कि उन्होंने इनडिसिपलिन क्रिऐट किया है इसलिए उनको नौकरियां से हटाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनको किसी ने सुनने का साहस तक नहीं किया है। स्पीकर साहब, पुलिस में भर्ती के लिए मैट्रिक की क्वालिफिकेशन रखी हुई है और नौकरियों के लिए एम.ए. क्वालिफिकेशन के लड़के आते रहते है, और आये भी हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिलतीं और जब वे लोग कहीं डयूटी पर आते हैं तो उन्हें सीनियर आफिसर्ज के घर पर काम करना पड़ता है जिसके लिए वे

मजबूर हो जाते हैं। स्पीकर साहब, नौकरियों से निकलने वाले जो सिपाही थे, उन का यह कहना था, वे सरकार को यह कहना भी चाहते थे कि सरकार ने हमारी दुखभरी कहानी नहीं सुनी और हमको डिसमिस कर दिया गया। (घंटी) स्पीकर साहब, बस एक दो मिनट ही लूंगी। कल चौ. हरपाल सिंह जी ने कहा कि हमने डंगरों की नसल सुधारने के लिए प्रान्त में काफी कुछ किया है, मैं इनको यह कहूंगी कि कोई ऐसी डिपार्टमैंट भी खोलें कि जहां पर ये आदमियों की नसल का भी सुधार कर दिया करें। (हंसी एवं शोर) स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े ही सहज ढंग से यह कह दिया कि भाई क्या करें दूसरी स्टेट के लोग आ गए थे, उनकी परसेन्टेज हाई थी, उनकी सिफारिश माननी पड़ी। मैं इनसे यह कहूंगी कि अगर ये चाहेंगे तो वे आयेंगे, अगर ये नहीं चाहेंगे तो वे नहीं आयेंगे। अगर इसी तरह के हालात हमारे यहां हरियाणा में स्पीकर साहब, पैदा होते रहे तो मुझे यह कहने में बिल्कुल झिझक न होगी कि यहां पर भी दूसरा आसाम बनेगा।

चेयरमैन साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहूंगी से यह कहूंगी कि किसान केवल दो रोटियां ही चाहता है। अगर उसको पेट भर खाना मिलता रहेगा तो वह चैन से बैठा रहेगा और खुशी से रहेगा और अगर उसको पेट भर खाना भी न मिलेगा तो वह कैसे दिक्कतों का सामना करेगा? स्पीकर सहाब, अब मैं मारूति के लिए जो जमीन ली गयी है, उस बारे में कहना चाहती हूं। अगर वह जमीन मालिकों के पास ही रहती तो आज वे

लोग करोड़पति होते। वे लोग आज भूखे मर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। अगर उनमें से आज कोई चपरासी की पोस्ट के लिए भी जाता है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इतना बुरा हाल है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीब किसानों की जमीनें एक्वायर न की जाएं और न ही वे एक्वायर करके प्राइवेट आदमियों को दी जाएं।

स्पीकर साहब, अन्त में मैं एक बात कहूंगी कि आपने ''गांधी'' पिक्चर देखी होगी, शायद सभी ने देखी होगी। स्पीकर सहाब, वही गरीबी, वहीं गरीबी के दु:ख लेकिन अफसोस है कि उन दु:खों को देखने के लिए आज मोहन दास कर्म चन्द गांधी जी की ही जरूरत थी जो हमारे बीच में नहीं हैं। धन्यवाद।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, यहां पर बहुत सी बातें इंडस्ट्रीज के बारे में कही गयी और मेरे फाजिल दोस्त श्री रोशन लाल आर्य जी ने कहा कि यमुनानगर के अन्दर कोई डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैन्टर सरकार की तरफ से खोला जाना चाहिये। स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि यमुनानगर में बड़े लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं और इसी तरह से अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर में भी इंडस्ट्रीज का बड़ा भारी केन्द्र है और आलरेडी अम्बाला में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर का आफिस है, यदि किसी किस्म की कोई दिक्कत आये तो इस कार्यालय द्वारा हल की जा सकती है। इसलिये वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सैन्टर खोलने का कोई खास कारण दिखाई नहीं देता। दूसरी

बैंकस की बात कही गयी। मैंने पहले अपने क्वैश्चन के जवाब में भी बतलाया था कि जो नैशनेलाइजड बैंकस हैं, वहां लोनज वगैरह लेने के लिये काफी फारमैलिटीज पूरी करने की दिक्कतें आती हैं लेकिन अगर मेरे दोस्त किसी खास पर्टीकुलर केस के बारे में बताएंगे, तो उस केस मैं सरकार की तरफ से मदद की जा सकती है।

स्पीकर साहब, एक बात मेरे फाजिल दोस्त श्री देवीदास जी ने कही कि रूरल इंडस्ट्रीज सैंट परसैंट फेल हो चुकी हैं। इस बारे में, मैं उनको डाकूमैंटरी प्रूफ से संतुश्ट कराना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक–आध जगह पर इंडस्ट्रीज अवश्य फेल हुई हैं, इससे हम इन्कार नहीं करते लेकिन यह कह देना कि सारे हरियाणा में इंडस्ट्रीज बुरी तरह फेल हुई है, यह तो बिल्कुल ही गलत बात और बेबुनियाद बात है। मैं उनको बाकायदा फिगर्ज बता देता हूं, अगर लोग हर साल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो फेल कैसे होगी? स्पीकर साहब, 1978–79 में एक रूरल स्कीम चली थी, उस समय 674 इंडस्ट्रीज हमारी स्टेट में लगायी गई थीं। 1979–80 से 1561, 1980–81 में 2813, 1981–82 में 3745, 1982–83 में 3233, 19780–79 की फिगर्ज निकाल कर के टोटल 11352 इंडस्ट्रीज लगी हैं। अगर ये सैन्ट परसैन्ट इंडस्ट्रीज फेल हुई हों तो इस तरह से हर तरफ इंक्रीज कैसे हो सकती है? मेरी समझ में यह नहीं आया कि मेरे माननीय फाजिल दोस्त यह बात किस आधार पर कह गये। इसलिये यह बात जंचती नहीं है।

स्पीकर साहब, मैं हाउस की इतलाह के लिये बताना चाहता हूं कि आने वाले अगले तीन सालों के अन्दर हमारा हरियाणा प्रदेश इंडस्ट्रीज के मामले में टौप पर होगा। हमारे पास इतने बड़े–बड़े प्रोजैक्टस आ रहे हैं, और आये भी हैं। अभी पंचकूला में बी.एच.ई. एल. एक प्रोजैक्ट लगाने जा रहा है जोकि 20 करोड़ रूपये की लागत से लगेगा और कम से कम 2 हजार आदमियों को वहां पर रोजगार भी मिल सकेगा। इसी तरह से डैनिश कोलेबोलेशन से एक और बड़ा भारी प्रोजैक्ट लगा रहे हैं, मिलचिंग मशीनों के जरिये भैंसों का दूध निकाला जाएगा और वे मशीनें पांच मिनट के अन्दर–अन्दर चार–पांच भैंसों का दूध निकाल सकेंगी। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी।

श्री लछमन सिंह: बेकारी कहां बढ़ेगी बहन जी? पहले तो अन–हाईजनिक तरीके से बात हो रही थी और अब हाईजनिक तरीके से बात होगी। बड़ा अच्छा प्रोजैक्ट है। स्पीकर साहब इसी तरह से उद्योग–विहार बन रहा है। अभी यहां पर मारूति का भी जिक्र आया यह एक हमारा बड़ा प्रैस्टिज वाला प्रोजैक्ट है। स्पीकर साहब, देश के अन्दर आटोमोबाइल में भी बड़ी हलचल मची हुई है और हमारे यहां पर आटोमोबाइल में भी लोगों ने काफी सुधार करना शुरू कर दिया है। हम बड़े लक्की हैं कि हमारे यहां पर बहुत बड़े–बड़े प्रोजैक्टस शुरू हुए हैं उनकी एनसिलिरीज के मुताबिक हम उन्हें उद्योग बिहार में प्लाट दे रहे हैं ताकि उसमें किसी को दिक्कत न हो। हम सारे प्रदेश को ही इंडस्ट्रीयलाइज

करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह समझ नहीं सका कि मैंबर साहेबान ने किस बिनाह पर यह कह दिया कि सैन्ट परसैंट इंडस्ट्रीज फेल हुई हैं। हो सकता है कि दो–चार इंडस्ट्रीज फेल हो गयी हों, लेकिन इनकी बात कोई जंचती नहीं। रूरल इंडस्ट्रीज को पहले दो सालों के लिये सेल्ज टैक्स माफ है इसमें एक दिक्कत हैं कि जिन लोगों की दुकानें शहरों में हैं उन्होंने रूरल इंडस्ट्रीज भी लगा रखी हैं। रूरल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन को वे अपनी शहर वाली दुकानों में बेचते हैं उसके लिये सेल्ज टैक्स वालों को और चुंगी वालों को और चुंगी वालों को एतराज है। वे समझते हैं कि यह माल या तो दिल्ली से खरीद कर लाते हैं या कहीं और जगह से। वे समझते हैं कि टैक्स बचाने के लिए दुकानदार ऐसा करते हैं। बाकी जो रूरल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन होती है, उसको डिपार्टमैंट परचेज करता है। कोई आदमी अंजान हो सकता है, वह गलत चीज बना ले, ऐसे केसिज में तो दिक्कत हो सकती है। मुझे ऐसी बात मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैम्बर साहब, अगर कोई बात मेरे नोटिस में लांएगे तो उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। जहां तक रा–मैटिरियल की बात है, आज किसी भी रा–मैटिरिलय की शार्टेज नहीं है। मोम के बारे में पिछली सरकार के समय इतना शोर मचा था लेकिन आज कोई आदमी हमारे से जितना चाहे मोम ले सकता है। इसका कारण यह है कि मार्किट के अन्दर मन्दा है और इस पर कोई प्रीमियम नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं रिकवैस्ट करूंगा कि डिमांडज पास की जाएं।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मांग न. 9 शिक्षा विभाग से संबंधित है और इसके जरिये 1017125295 रू. मांगे जा रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने काफी बातें कहीं। पहली बात तो स्टाफ पूरा न होने के बारे में कही गई मैंने पहले भी कहा था कि इस साल स्टाफ की कुछ कमी रही है जो हम जल्दी ही पूरी कर रहे हैं। इसमें कोई रूरल या अर्बन एरिया की बात नहीं है बल्कि जहां कहीं भी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक सदस्य ने ट्रांसफरों में पोलिटीकल इन्टरफियरैन्स की बात कही। यह बात बिलकुल निराधार है। ट्रांसफर या तो व्यक्ति की अपनी इच्दा पर होती है या जो ठीक ढंग से कार्य न करे या शिकायत की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज को ध्यान में रख कर ही ट्रांसफर होती है। लेकिन यह बात ठीक है कि शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर का सिस्टम है, उसमें कुछ सुधार करने के बारे में बात है कि ज्यादा ट्रांसफर्ज न की जाएं। इस बार इस कोशिश करेंगे कि ज्यादा ट्रांसफर्ज न की जाएं। इसके अलावा शिखा विभाग में भर्ती के बारे में बात आई कि जो शिक्षकों की भर्ती की गई, उसमें गड़बड़ हुई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जितनी भी भर्ती हुई वह क्राईटेरिया के तहत हुई और कहीं भी गड़बड़ वाली बात नहीं हुई। जिनका अकेडैमिक एक्सपीरिएंस ज्यादा था उन्हीं को भर्ती किया गया है। एक सदस्य ने स्कूलों की बुरी हालत के बारे में कहा कि कई स्कूल की बिल्डिंगों की बुरी हालत है। इसका कारण हमेशा यह रहा है कि गांवों और शहरों

में लोग कम्यूनिटी बिल्डिंग बना देते थे और गवर्नमैंट टीचर भेज देती थी। शहरों में कम्यूनिटी थोड़ी आगे नहीं आ रही है जैसे गांवों में आ रही है .....

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफर आर्डर है। स्पीकर साहब, बहुत से सरकारी स्कूल किराये की बिल्डिगों में हैं और वे बिल्डिगें गिरती जा रही है। उसके लिये सरकार क्या विचार कर रही है? क्या सरकार द्वारा वहां पर नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी?

श्री जगदीश नेहरा: किराये की बिल्डिंगे नहीं है बल्कि 50 से 80 साल तक की पुरानी बिल्डिगें हैं जो कि कम्युनिटी ने बनाई थीं। शहरों में बहुत सी जगहों पर ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, ऐसी बिल्डिगों पर न तो एजुकेशन डिपार्टमैंट खर्च कर सकता है और न ही उनके मालिक कर रहे हैं।

श्री जगदीश नेहरा: मैंने अभी बताया है कि उनको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सब–स्टैंडर्ड मैटिरियल लगा हुआ है। सरकार ने तो आम तौर पर कोई नई बिल्डिंग बनाई नहीं। जो आलरेडी बनी हुई हैं वह लोगों ने बनाई हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया कि सब–स्टैंडर्ड मैटिरियल लगा हुआ है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर सदन की सहमति हो तो बैठक का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: ठीक है जी!

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्श 1983–84 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, श्री लछमन सिंह कम्बोज ने इन्दरी में कालेज खोलने के बारे में कहा था। अगर जरूरत समझी जाएगी तो वहां कालेज खोलार जाएगा। रोशन लाल जी ने भी स्कूल और कालेज खोलने के बारे में बात की थी। जहां कहीं भी जरूरत समझी जाएगी वहां पर स्कूल और कालेज खोल दिये जाएंगे। हरियाणा में स्कूलों का सिस्टम जितना अच्छा है, मेरे ख्याल में ऐसा सिस्टम कहीं भी न होगा। हरियाणा में एक किलोमीटर के रेडियस के अन्दर प्राइमरी स्कूल है, दो किलोमीअर के रेडियस के अन्दर मिडल स्कूल है और तीन या साढ़े–तीन किलोमीटर के रेडियस के अन्दर हाई स्कूल है। यह बहुत ही

अच्छी बात है। इसके अलावा और भी कई बातें माननीय सदस्यों ने कहीं विशेशतौर से जो हमारे सिरसा जिले से माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सिरसा के बारे में बातें कहीं जोकि शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं थीं। उन्होंने कई बातें ऐसी कहीं जो मेरे बताने की हैं। इसके राज में स्कूलों के बारे में वहां कोई बात नहीं की गई। वहां पर एक काला तितर बनाया गया जिसकी अब तक बहुत गूंज है। उसके ऊपर 50 लाख रूपये लगे और उसकी आमदनी आज पांच रूपये रोज की भी नहीं है।

श्रीमती बसन्तों देवी: स्पीकर साहब, मेरी रिकवैस्ट यह है कि अगर काला तितर किसी काम नहीं आता तो वहां पर स्कूल खोल दीजिये।

श्री जगदीश नेहरा: वह स्कूल की जगह नहीं है। वह ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां पर उसका कोई प्रयोग नहीं है। पता नहीं बनाने वाले की बुद्धि कहां चली गई थी। अध्यक्ष महोदय, इनके राज में स्टेडियम बना, तो वह चुटाले में बना, हस्पताल बना, तो वह चुटाले में बना और टूरिजम कम्पलैक्स बना तो वह चुटाले में बना। समझ नहीं आती कि उस समय की सरकार किस तरह से कार्यवाही कर रही थी। सड़कें भी चुटाले के चारों तरफ बनाई गई थीं। माननीय सदस्य ने कई बातें इस तरह की कहीं जो उनको कहनी नहीं चाहिएं थीं लेकिन उनकी जितनी बुद्धि है उतनी ही बात करेंगे। (शोर)

श्री भागीराम: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है कि अभी मंत्री जी ने बोलते हुए यह कहा कि इनकी जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बात करेंगे। स्पीकर साहब, इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारी तरफ भी काफी माननीय सदस्य ऐसे हैं जो काफी बुजुर्ग हैं। (शोर एवं विघ्न)

चौ. बलवीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी स्कूलों के बारे में बात रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में एक मित्ताथल गांव है, उस गांव के स्कूल की बिल्डिंग को डिप्टी कमीशनर ने डेजरस डिक्लेयर कर दिया है और उस बिल्डिंग को लाक लगवा दिया है और तीन महीने से उस बिल्डिंग में कोई काम नहीं हो रहा है। (शोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मेरे अपोजीशन के भाई बार–बार उठकर प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं। प्वायंट आफ आर्डर रेज करने का तो हमारे रूल्ज में प्रोवीजन है लेकिन ये टाईम का मिसयुज कर रहे हैं। स्पीच में थोड़ा बहुत इन्ट्रप्ट कर सकते हैं लेकिन 100 फीसदी इन्ट्रप्ट करना ठीक नहीं है।

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, जहां–जहां पर जितने स्कूल अपग्रेड करने का टारगेट था, वहां–वहां पर उतने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। सरकार की तरफ से 679 स्कूल अपग्रेड करने का टारगेट रखा गया था लेकिन अब तक 884 स्कूल अपग्रेड किए

जा चुके हैं जोकि बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह से शिक्षा विभाग के लिए प्लान साइड में और नान प्लान साइड में जो पैसा एलोकेट किया गया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से बहुत सोच–समझ कर दिया गया है। इसलिए मैं आपके द्वारा सदन से दरख्वास्त करूंगा कि 101 करोड़ 17 लाख 25 हजार रूपए की जो शिक्षा विभाग की डिमांड है वह इसको मंजूर करें।

लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री (चौ. लाल सिंह): स्पीकर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। स्पीकर साहब, हमारे कई माननीय सदस्यों ने पब्लिक हैल्थ के बारे में काफी बातें कहीं हैं और मेरे अपोजीशन के भाइयों ने यह भी कहा है कि आदमपुर में यह कर दिया, वह कर दिया, हिसार में यह कर दिया वह कर दिया। स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत एक अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा में कुल 6731 गांव हैं और इनमें से हमने 2170 गांवों के एक–एक आदमी को पीने का पानी दिया है। इसके अलावा में माननीय सदस्यों को वह भी बताना चाहता हूं कि हम साढ़े–आठ साल के अन्दर सारे हरियाणा के गांवों को पीने का पानी दे देंगे। स्पीकर साहब, अगर कोई आदमी यह कहे कि लाल सिंह मैं तेरे गोली मारूंगा तो मैं उसको कहता हूं कि भाई तू पहले मेरे हाथ से पानी पी ले उसके बाद गाली मारूंगा तो मैं उसको कहता हूं कि भाई तू पहले मेरे हाथ से पानी पी ले उसके बाद गोली मारना। (हंसी) प्यासे को पानी

पिलाना धर्म का काम है। इसके अलावा, स्पीकर साहब, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि इस हल्के में काम करना है और इस हल्के में नहीं करना है। मैं ईमानदारी से यह बात कहता हूं। स्पीकर साहब, सारे हरियाणा प्रान्त के गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दो अरब 25 करोड़ रूप्या चाहिए। यदि यह पैसा मिल जाता है तो साऐ आठ साल में सारे गावों को पीने का पानी दे दिया जाएगा। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने सरकार पर गलत तरीके से इल्जाम लगाए हैं उनको हाउस की प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाए। हम हरियाणा प्रान्त के हर आदमी को पीने का पानी देंगे।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए. सी. चौधरी): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 11 के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्रीदेवी दास जी ने इस डिमांड पर बोलते हुए कुछ एतराज किए थे। उन्होंने इस डिमांड पर बोलते हुए सबसे पहली बात यह कही कि सरकार ने हर छोटे दुकानदार पर 50 रूपये से लेकर 100 रूपये पर मंथ सेल्ज टैक्स लगा दिया, जो बिल्कुल निराधार है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सेल्ज टैक्स आज से नहीं बल्कि 10–11 साल पहले से लगाया हुआ है। ओफेन्सियल ट्रेडज पर और डेंजरस ट्रेडज पर जितने भी टैक्स थे, उन टैक्सों की दरों का रीविजन हुआ है। ये टैक्स कई साल पहले लागू किए गए थे। जिस समय यह टैक्स लागू किए गए थे, उस

समय इनका गजट में नोटिफिकेशन भी किया गया था और इन टैक्सों के बारे में आबजैक्शन भी इनवाइट किए गए थे और आबजैक्शन रेज करने के लिए टाईम भी दिया गया था। इन टैक्सों के बारे में जितने भी आबजैक्शन आए, उनको कंसीडर करके और लोगों की परेशानी को देख कर के यह फैसला किया गया कि इन टैक्सों को स्ट्रीम लाइन कर दिया जाए। उसी उदेश्य से व्यापारियों के प्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार की तरफ से इसके लिए 15 अप्रैल तक की अवधि रखी जाती है उसके बाद यह टैक्स स्ट्रीम लाइन कर दिए जाएंगे। स्पीकर साहब, इन टैक्सों से किसी भी दुकानदार को 10—15 रूपये से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री देवी दास जी ने यह भी कहा कि सोनीपत में जो सिवरेज की लाइन बिछाई गई है उसका लैवल ठीक है जिसके कारण सिवरेज का पानी नहीं गुजरता है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिस समय सिवरेज की पाइप लाइन बिछाई जाती है उस समय पूरी तरह से लैवल ठीक करके पाइप लाइन बिछाई जाती है। बगैर लैवल किए यदि पाइप लाइन बिछा दी जाए तो पानी का निकाल नहीं हो सकता यह बात तो सबको पता है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो सिवरेज की पाइप लाइन बिछाई गई है उसका पूरा लैवल ठीक करके बिछाई गई है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। मैंने यह कहा है कि सोनीपत में हाउसिंग बोर्ड ने जो कालोनी बनाई है उसके अन्दर सिवरेज की पाइप लाइन बिल्कुल बंद है। यदि उस कालोनी में सिवरेज की पाइप लाइन लैवल लेकर बिछाई जाती तो पानी का निकास हो जाता। उस कालोनी में सिवरेल बिल्कुल बंद पड़ी है चाहे मिनिस्टर साहब खुद इस बात की इनक्वायरी कर लें।

श्री ए.सी. चौधरी: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यदि वहां की म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से यह शिकायत आएगी कि वहां पर सिवरेज के पानी का निकास नहीं होता है तो हम उसको सिवरेज क्लिनीजिंग मशीन लगाने के लिए स्पैशल ग्रांट देंगे। इसके अलावा, इन्होंने सोनीपत की ड्रेन नम्बर 6 के बारे में कहा कि वह शहर के अन्दर से गुजरती है उसमें बहुत गंदगी रहती है। मैं अपने माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार उस ड्रेन की गंदगी हटाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है और जल्दी ही यह काम करने के लिए विचार किया जाएगा। एक बात उन्होंने यह कही कि वहां पर लोगों को पीने का पानी कई–कई दिन तक नहीं मिलता। उनका यह कहना बिल्कुल निराधार है कि लोगों को पीने का पानी कई–कई दिन तक नहीं मिलता। उनका यह कहना बिल्कुल निराधार हे कि लोगों को पीने का पानी कई–कई दिन तक नहीं मिलता। मैं यह बतानाप चाहता हूं कि एक बार यह शिकायत जरूर

आई थी कि पीने के पानी की सप्लाई बहुत कम हो रही है। उसका कारण यह था कि पीछे से बिजली का ब्रेक–डाउन हो गया था जिसके कारण पानी की सप्लाई कम हुई थी। इस समय ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा स्पीकर साहब, श्री अमीर चन्द मक्कड़ ने कहा कि लोकल बौडीज को फण्डज दिए जाने चाहिएं। इस बारे में मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां–जहां पर सरकार खुद लोकल बौडीज को फण्डज देने के लिए जरूरत महसूस करेगी, वहां पर दे दिए जाएंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जन–सुविधाओं की बात है, वह पैसे की कमी की वजह से नहीं रूकेंगी। मैं हाउस को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं। इन शब्दों के साथ मैं हाउस से निवेदन करूंग कि डिमांड नम्बर 11 में जितने पैसे का प्रावधान किया गया है उसको मंजूरी दी जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, डिमांड न. 10 के बारे में जो हाउस के सामने पेश की गई थी, कुछ साथियों ने अपने–अपने विचार प्रकट किए है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि स्वास्थ्य विभाग पूरे तौर से लोगों के स्वास्थ्य की सेवा कर रहा है। श्री देवीदास ने कहा कि सोनीपत के अन्दर जो नया अस्पताल बनाया जा रहा है उसक अन्दर ठीक मैटिरियल नहीं लगाया जा रहा और जो पुराना अस्पताल है उसके अन्दर कोई एमरजैसी वार्ड नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सोनीपत में जो पुराना अस्पताल है, उसमें अलग

से एक एमरजैंसी वार्ड बना हुआ है और उसके अन्दर 8 बैडस हैं। नए अस्पताल के मैटिरियल के संबंध में कोई शिकायत मेरे नोटिस में नहीं आई। नए अस्पताल को जितना जल्दी हो सकेगा, उतना ही जल्दी उसे पूरा करने की पूरी–पूरी कोशिश की जायेगी। एक बात श्री रोशन लाल आर्य जी ने आयुर्वेदिक के बारे में कही है। इन्होंने छछरौली अस्पताल के बारे में कहा है। मैं इन्हें बता देना चाहती हूं कि उसके लिए बजट बनाया जा रहा है और बजट में यह देखा जा रहा है कि इस पर कितना खर्च रिपेयर पर आना है। मैं इनको विश्वास दिलाती हूं कि यदि नए अस्पताल के बनाने की आवश्यकता हुई तो उसको भी बना दिया जायेगा। यहां पर नेचुरल इलाज के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में मैं हाउस को बताना चाहती हूं कि इस काम को स्वयं सरकार अपने तौर पर तो शुरू नहीं कर सकती। इतना जरूर कर सकती है कि यह कोई प्राइवेट संस्था इसे चालू करें तो उसमें सरकार आर्थिक तोर पर कुछ मदद कर सकती है। आयुर्वेदिक के बारे में यह भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ये डिस्पैन्सरियां खुलनी चाहिएं। इस संबंध में मैं हाउस को बताना चाहती हूं कि इस समय हरियाणा के अन्दर ये डिसपैन्सरियां 341 हैं। पिछले साल हमने 24 डिस्पैन्सरियां खोली थीं और इस साल 10 नई डिस्पेन्सरियां खोलने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक के 10 बैडस के दो हस्पताल हैं और 25 बैडस का एक हस्पताल है। इनके अलावा कुरूक्षेत्र आयुर्वेदिक कालेज में भी 25 बिस्तरों का एक और हस्पताल है। स्पीकर साहब, स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी सेवाएं प्रदेश को प्रदान

कर रहा है। एक बात चौ. नर सिंह जी ने डाक्टरों के तबादलों के बारे में कही हैं। इन्होंने कहा है कि डाक्टरों के पैसे लेकर बार–बार तबादले किए जाते हैं। स्पीकर साहब, शायद इनको पता न हो कि डाक्टरों की बदली उसी सूरत में की जाती है जब किसी दूसरे हस्पताल में उस सब्जैक्ट के डाक्टर की आवश्यकता हो। एक ही हस्पताल में एक ही सब्जैक्ट के कई डाक्टर नहीं रखे जाते। नरसिंह जी ने बोलते हुए यह भी कहा था कि आदमपुर में सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन्होंने जो बात कही है, वह बिल्कुल गलत कही है। किसी भी हल्के के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। सरकार की पूरी कोशिश होती है कि हरेक हल्के में बराबर के काम हों और किसी के साथ भेदभाव न हो। सरकार अब स्कूलों में पढने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ भी पूरा–पूरा ध्यान दे रही है। स्पीकर साहब, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूं कि हमने एक स्कीम चालू की है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग सारे प्रदेश में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों, जिनकी संख्या 20 लाख 50 हजार है, के स्वास्थ्य की जांच के लिए काम करेगा।

श्री निहाल सिंह: जिस प्रकार से सारा हैल्थ डिपार्टमैंट हैल्थ मिनिस्टर की हैल्थ बनाने में लगा हुआ है, क्या उसी प्रकार से सभी की हैलि बनायी जायेगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यही बात बताने जा रही थी कि सभी का बराबर ध्यान रखा

जा रहा है। हमने एक स्कीम बनाई है जिसमें 20 लाख 50 हजार बच्चे जो हमारे स्कूलों में पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उनकी सेहत की तरफ स्वास्थ्य विभाग ध्यान देगा। इस काम में शिक्षा विभाग ने भी हमें पूरा–पूरा सहयोग दिया है। हम सभी बच्चों का पहली कक्षा से कार्ड बना करके दसवीं कक्षा तक पूरा रिकार्ड रखेंगे और अब स्वास्थ्य विभाग ने इस काम को शुरू भी कर दिया हैं। हमें आशा है कि हम इस काम को 31 दिसम्बर, 1983 तक पूरा कर देंगे। इस काम में हम हरेक स्कूल के हरेक बच्चे को देखेंगे। यदि उन्हें इलाज की आवश्यकता हुई तो उनका इलाज भी स्वास्थ्य विभाग करेगा और इन बच्चों को अच्छी प्रकार से चैक करेंगे। यदि किसी बच्चे को चश्में आदि की आवश्यकता हुई तो उसको भी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से प्रदान करने की कोशिश करेगा। जिस साथियों ने भेद भाव का जिक्र किया है, उनको मैं बताना चाहती हूं कि किसी के साथ भी भेजभाव नहीं किया जा रहा है।

श्री मंगल सैन: कलानौर में हस्पताल बनाने की बात सी. एम. साहब ने कही हुई है लेकिन वह हस्पताल आज तक नहीं बनाया गया है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे कर रखे हैं उनको पूरा किया जा रहा और पूरे हो रहे हैं।

श्रीमती करतार देवी: डा. साहब ने कलानौर में हस्पताल बनाने का जिक्र किया है। उस संबंध में मैं डा. साहब को बड़े अदब से बताना चाहती हूं कि सी.एम. साहब ने जो वायदे वहां पर किए थे से सभी पूरे हो चुके हैं। वहां पर हस्पताल के लिए पैसा भी सैक्शन हो चुका है। हस्पताल के लिए अब सिर्फ जमीन ही ट्रांसफर होनी शेश रहती है।

चौ. नर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर, अभी मंत्री महोदया ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए हुए हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब ये जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे, इन्होंने कैथल को जिला बनाने के लिए वायदा किया था, क्या उसे पूरा कर दिया है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जैसा कि मैं बता रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे या घोशणाएं की हुई हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। स्पीकर साहब, जो–जो स्वास्थ्य विभाग की स्कीमें बनी हुई हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग पूरा करने की पूरी–पूरी कोशिश कर रहा है। श्री मनफूल सिंह ने पानीपत में मच्छरों की शिकायत की है कि वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा हैं। स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार का इस तरफ पूरा–पूरा ध्यान है कि मच्छरों को खत्म किया जाये। मैं साथ

में यह भी बताना चाहूंगी कि पिछली रिपोर्टों की एवरेज को देखते हुए इस समय मच्छरों को काफी हद तक कम कर दिया गया है। में यह भी इनको बताना चाहूंगी कि हम इस तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे। अन्त में मैं स्पीकर साहब आपके द्वारा हाउस से प्रार्थना करना चाहूंगी कि 632057780 रूपये, जो डिमाड न. 10 के तहत मांगे जा रहे हैं, पास किए जायें। इस रूप्ये में से 38 करोड़ 99 लाख 59 हजार रूपये हैल्थ के हैं और 24 करोड़ 30 लाख 98 हजार 780 रूपये जन–स्वास्थ्य के हैं। इन दोनों की एक ही डिमांड है। मैं अन्त में फिर हाउस से प्रार्थना करूंगी कि इस डिमांड का पास कर दिया जाये।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): स्पीकर साहब, मैं डिमांड न. 13 के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे बेहद अफसोस है कि डिमांड 13 पर विपक्ष की तरफ से कोई नहीं बोला जबकि यह डिमांड हरिजनों से संबंधित है। इस डिमांड में हरिजनों के हितों के लिए पैसा रखा हुआ है। विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक सदस्य श्री मनफूल सिंह ने बोलते हुए हरिजनों के बारे में कुछ कहा है। बाकी विपक्ष का कोई भी सदस्य हरिजनों के सुख–दुख के बारे में कुछ भी नहीं बोल सका। (शोर)

चौ. बलबीर सिंह ग्रेवाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी बहिन जी ने कहा हे कि इन डिमांडों पर बोलते हुए विपक्ष की तरफ से कोई भी सदस्य हरिजनों के हितों के लिए नहीं बोल सका। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि विपक्ष के 14

हरिजन एम.एल.ज. चुनाव जीत के आये थे और कांग्रेस के सिर्फ तीन ही हरिजन विधायक चुन कर आये थे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, अगर मेरे भाई हरिजनों के लिए बनाई गई योजनाओं को पढ़ लेते तो अच्छा होता और इनको पता लग जाता कि सरकार हरिजनों के लिए क्या कुछ कर रही है। अगर ये पढ़ लेते तो केवल हरिजन ही नहीं, ये स्वयं भी हमारी तरफ आने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि हरिजनों के हितों का जहां तक सवाल है, इनके हितों के लिये बनाई गई योजनाओं का पढ़ने का ये जरा भी कश्ट ही नही करते। स्पीकर साहब, जो पार्टी हरिजनों को वोट भी न डालने दे और सरप्लस जमीन को हरिजनों में न बंटने दे, उस पार्टी के आदमी हरिजनों के हितों की बात कैसे सोचे सकते हैं। मैं सदन को इतना ही बताना चाहूंगी कि आज की सरकार हरिजनों की हितैशी है। स्पीकर साहब, जब चौ. देवी लाल की सरकार थी तो हरिजनों को मकान बनाने के लिए दो–दो हजार रूपये प्रति व्यक्ति देती थी लेकिन इसके साथ शर्त यह थी कि जो व्यक्ति अढ़ाई हजार रूपये बैंक से कर्जा लेगा उसी को समाज कल्याण विभाग की तरफ से दो हजार रूपये अनुदान के रूप में मिलेगा। यह पाईल–अप स्कीम थी। इस स्कीम किसी तरह से खत्म हो गई और हमने इसकी जगह दूसरी स्कीम चालू

कर दी। यह स्कीम इसलिए खत्म हो गई और हमने इसकी जगह दूसरी स्कीम चालू कर दी। यह स्कीम इसलिए खत्म कर दी क्योंकि जो आदमी पैसा वापिस देने की हैसियत ही नहीं रखता था, वह बैंक से अढ़ाई हजार रूप्ये का कर्जा क्यों लेगा। अगर वह अढ़ाई हजार बैंक से कर्जा नहीं लेगा तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से वह दो हजार रूप्ये का अनुदान कैसे लेगा। इस शर्त की वजह से लोगों ने सरकार के अनुदान का फायदा नहीं उठाया और आपने शायद देखा होगा, अनुदान के रूप में जो पैसा रखा था। वह सारे का सारा लैप्स हो गया था। भजन लाल की सरकार ने इस स्कीम का बदल दिया है और आपने देखा होगा कि 1979–80 और 1980–81 में एक ही बार में हरिजनों में 25 लाख रूपया दे दिया और अधिकतर हरिजनों ने इसका फायदा उठाया। स्पीकर साहब, श्री मनफूल सिंह जी कह रहे थे कि हरिजनों को दबाया जा रहा है। मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि हम हरिजनों को बसाना चाहते हैं जिसके लिए अलग–अलग स्कीमें मकान देने के लिए बनाई गई हैं। अगर कोई हरिजन स्वयं मेहनत करके मिट्टी के साथ मकान बनानाप चाहे तो हम उसको दो हजार रूपये का अनुदान देंगे। (व्यवधान) स्पीकर साहब, हम हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हरिजनों को हरिजन कालोनियां बनाकर दे रहे हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बहन जी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरे एक

सवाल का जवाब दे दें। इन्होंने विधवाओं को जो 50 रूपये की पैन्शन दे रखी है, क्या इसको बढ़ाकर 10 रूपया मासिक करने की प्रपोजल पर विचार करेंगी?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: यह मामला पहले ही हमारे विचाराधीन है। स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ, राश्ट्रीयकृत बैकों द्वारा दो–दो हजार रूपए का अनुदान देकर कालोनियों बनवानी शुरू कर दी हैं। इस स्कीम के तहत ताउड़ के अन्दर एक कालोनी बनाने का निर्णय लिया गया है। अगर स्कीम कामयाब हुई तो सारे हरियाणा में इस तरह की कालोनियां बनाने की योजना चालू करेंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: टाईम कम रहा गया है, इसलिए हाउस का टाईम 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाना है ताकि एजेन्डा कम्पलीट हो जाए।

वर्श 1983–84 के बजट की डिमांडज फार ग्रान्टस पर चर्चा ता मतदान (पुनरारम्भ)

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, पिछले दिनों हरिजनों के लिए चौपालें बनाई गई। हरिजनों को चौपाल

बनाने के लिए मैचिंग ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता था लेकिन अब हमने मैचिंग सिस्टम खत्म कर दिया है। अब 15 हजार रूप्ये वाली मैचिंग ग्रांट हरिजनों के लिए नहीं रखी बल्कि सीधा ही 15 हजार रूपया हरिजनों को चौपाल बनाने के लिए दे दिया जाता है। मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूं कि पहले हरिजन को दो हजार रूपये का कर्जा लेने के लिए दफतर में तीन बार जाना पड़ता था क्योंकि दो हजार रूपये का कर्जा तीन किश्तों में दिया जाता था। लोगों को तीन–तीन बार दफतर में आना पड़ता था, कितना कश्ट उठाया पड़ता था। अब हमने दो हजार रूपया एक ही किश्त में देने का फैसला किया है। इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर आफिसर का काम बहुत महत्वपूर्ण है लेनिक इनकी उपेक्षा की जाती थी। इन आफिसर्ज को इधर–उधर जाने के लिए जीप नहीं दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने प्रत्येक वैल्फेयर आफिसर को समाज कल्याण विभाग का कार्य देखने के लिए एक–एक जीप देने का प्रोवीजन किया है। स्पीकर साहब, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि जब श्री भजन लाल की सरकार नहीं थी, यानी जब भजन लाल, मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस विभाग का शेयर कैपिटल दो करोड़ रूपए का था लेकिन जब यह मुख्यमंत्री बने तो यह बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके इलावा बैकवर्ड क्लासिज की भलाई के लिए सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज निगम बनाई है और यह निगम यही समझ कर बनाई गयी हे कि सरकार गरीबों

की हितैशी है। बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को जमीन देने के लिए बैकवर्ड क्लासिज निगम बनाया गया जिसका शेयर कैपिटल पहले दो करोड़ रूपए था लेकिन अब इसको बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। जिस व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे हरिजन हो और चाहे अहीर हो, जो कमजोर होगा, गरीबी की रेखा से नीचे होगा, उसकी सहायता के लिए भी एक निगम बनाया गया है। पहले दो करोड़ इसका शेयर कैपीटल रखा था लेकिन अब सरकार का विचार है कि इस राशि को और बढ़ाया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मंत्री महोदय काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन क्या मंत्री महोयद इस मामले पर विचार करेगी कि खेतीहर मजदूर, खेती करने वाला किसान, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, उसको बुढ़ापे की पैन्शन दी जाए?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: इस किस्म का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इकनौमिकल वीकर सैक्शन की भलाई के लिए जो निगम बना है, इसमें एक आदमी गया और उसने निगम के अधिकारियों को बताया कि मेरी आमदनी 3500 रूपया सालाना हैं, मेरी हैल्प की जाए। अधिकारियों ने बताया कि तुम्हारी आमदनी तो कम है, अगर तुमको सहायता दे

दी तो रिकवरी कैसे करेंगे। दूसरे दिन कोई दूसरा आदमी फिर निगम में गया और उसने कहा कि मेरी आमदनी 10 हजार रूपये सालाना है। इसको भी यही कहा कि तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारी आमदनी ज्यादा है। इस बोर्ड में तो इस तरह के काम हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, सब जगह एक ही प्रवृति के आदमी नहीं बैठाये जा सकते। अगर इस किस्म की बात है तो आप मुझे बतायें। स्पीकर साहब, श्री मनफूल सिंह जी ने कहा कि बाल्मिकियों का दमन किया जा रहा है। मैं इनको सिर्फ इतना ही बता देना चाहती हूं कि हरियाणा सरकार ने करनाल के अन्दर बाल्मिकी भाईयों की शिक्षा के लिए एक आश्रम बना रखा है। छोटे–छोटे बच्चे इसमें शिक्षा ले सकते है ताकि वाल्मिकी भाईयों के बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। इसी तरह का आश्रम रिवाड़ी में भी खोला गया है। पिछले दिनों जींद में विमुक्त जातियो के लिए एक हौस्पिटल खोला है। इसके साथ ही साथ, स्पीकर साहब, हमने महसूस किया है कि हमारे हरिजन बच्चे नौजवान होने के बाद जो मैला उठाना पसन्द नहीं करते, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमने योजना बनाई है। ये नौजवान बच्चे आम तौर पर रिक्शा चलाते हैं लेकिन जो रिक्शा का ठेकेदार है, वह उनकी मेहनत का काफी भाग किराये के रू॰ में ले जाता है। इस बात को मदे नजर रखते हुए उनको रिक्शा देने का प्रावधान किया गया है। इसे खरीदने के लिये वे लोग पैसा हरिजन

कल्याण निगम से या बैंकों से ले सकेंगे। स्पीकर साहब, इस सरकार ने 50 रूपये महीना बाल्मीकी इम्पलाइज का एकदम से बढ़ाया था और दस रूपये की एक और भी किश्त उन्हें दी गई है। कहने का मतलब यह कि इस सरकार ने 60 रूपया एकदम से उनकी तनख्वाह में बढ़ाया था। मैं चाहूंगी कि इन डिमान्डज को सर्वसम्मति से पास किया जाये।

14.00 बजे

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी बहिन जी ने कहा था कि किसी हल्के के बारे कोई बात हो तो हमें बतायें हम जरूर कार्यवाही करेंगे। हमारे रूलिंग पार्टी के साथी श्री निर्मल सिंह के हल्के में लदाना गांव है, वहां पर बहिन जी आज से तीन साल पहले हरिजन चौपाल का पत्थर रख कर आयी थीं। वह पत्थर आज भी यों का यों ही रखा हुआ है लेकिन चौपाल बनाने के लिये वहां पर कोई पैसा नहीं दिया गया।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: यह बात सच है कि वहां पर मैं पत्थर रख कर आयी थी लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर कई चीजें याद नहीं रहती। मैंने उनसे गांव का नाम भी पूछा था लेकिन नाम नहीं बताया। गांव का नाम बता दें मैं आज ही पैसा दे देती हूं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला है। आनरेबल मैम्बर कह हरे हैं लेकिन मिनिस्टर महोदया ने कोई एक्शन नहीं लिया है।

श्री निर्मल सिंह: बहिन जी ने वायदा कर रखा है। वह काम टाईम पर हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अब मैं वेरियस डिमान्डज फार ग्रान्टस वोटिंग के लिए पुट करता हूं।

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 106595850 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 2-**General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. 340911850 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 3-**Home.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 633057780 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 9-**Education.**

That a sum not exceeding Rs. 633057590 for revenue expenditure and Rs. 32905600 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 10-**Medical and Public Health.**

The motion was carried.

आवाजे: इनको इकट्ठा पुट कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 58335590 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 16-**Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 719575640 for revenue expenditure and Rs. 112500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 23-**Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 7051670 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 39062365 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 5-**Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 142833095 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 6-**Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 142686460 for revenue expenditure and Rs. 3700000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 7-**Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 256384000 for revenue expenditure and Rs. 250604960 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 8-**Building and Roads.**

That a sum not exceeding Rs. 21184920 for revenue expenditure and Rs. 2500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 11-**Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. 52499215 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 12-**Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 123065040 for revenue expenditure and Rs. 11824000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of

charges under Demand No. 13-**Social Welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 18826960 for revenue expenditure and Rs. 1195826460 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 14-**Food and Supply.**

That a sum not exceeding Rs. 14633140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 19-**Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 116857560 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 20-**Forest.**

That a sum not exceeding Rs. 8765345 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 24-**Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 1264918000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 25-**Loan and Advances by State Government.**

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

***14.05 बजे**

(तत्पश्चात सदन बुधवार, 23.3.83 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ)